www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

23 सितंबर–29 सितंबर 2013

दंगे शुरू हो चुके हैं

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली और मुज़फ़्फ़रनगर में होने वाले सांप्रदायिक दंगों में 19 गांव प्रभावित हुए हैं और लगभग एक लाख मुस्लिम आबादी बेघर हुई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इन दंगों में मरने वालों की संख्या 500 के क़रीब है. ज़िला प्रशासन इन दंगों को रोकने में विफल रहा, जिसकी वजह से हालात ज़्यादा ख़राब हो गए. देश भर के मीडिया का ध्यान केवल मुज़फ़्फ़रनगर पर ही रहा, जबकि दंगों की शुरुआत शामली ज़िले से हुई और यही दंगों का केंद्र भी रहा. चौथी दुनिया की टीम ने शामली ज़िले के कुछ स्थानों का दौरा किया और तथ्यों को जानने की कोशिश की. प्रस्तुत है यह रिपोर्ट :

डॉ. क़मर तबरेज़

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शामली और मुजफ़्फ़रनगर ज़िला साम्प्रदायिक हिंसा की चपेट में है, जिसके कारण अब तक सैंकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों परिवार अपना घर–बार छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में पलायन कर रहे हैं. इस क्षेत्र के अधिकतर लोग मूलत: किसान हैं. हिंदू–मुस्लिम भाईचारे की ज़िंदगी जीते चले आए हैं. इस इलाक़े में कभी दंगे नहीं हुए. ऐसे में यह सवाल उठता है कि आख़िर क्या वजह थी कि यहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और दंगों ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया. मीडिया के जरिये यह पता चला कि एक समुदाय की लड़की के साथ दूसरे समुदाय के लड़के का प्रेम–प्रसंग और फिर इसके नतीजे में दोनों समुदायों के तीन लड़कों की हत्या हो जाना ही दंगे का असल कारण बना. इसी को बहाना बनाकर क्षेत्र के नेताओं ने अपनी सियासी रोटियां सेंकनी शुरू कर दी. पंचायतों और महापंचायतों का सिलसिला शुरू हुआ, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काऊ नारेबाज़ी शुरू हुई और इस तरह नफ़रत की चिंगारी धीरे–धीरे पूरे क्षेत्र में फैलने लगी, जिसने आख़िरकार ख़ूनी रूप धारण कर लिया. सिर्फ एक घटना की वजह से दंगे हो गए, यह नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हर शहर में होती हैं, लेकिन क्या वहां दंगा भड़कता है? चौथी दुनिया की तहक़ीक़ात बताती है कि शामली और मुजफ़्फ़नगर ज़िले में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच टकराव की स्थिति पिछले चार–पांच महीनों से बनी हुई थी, जिसे भाजपा से जुड़े नेता निरंतर हवा दे रहे थे. स्वयं आरएसएस के कुछ लोग पिछले कई महीनों से छोटी–छोटी घटनाओं में मुसलमानों को निशाना बना रहे थे और इस मौक़े की तलाश में थे कि कैसे एक चिंगारी को शोले की शक्ल दी जाए, ताकि बड़े पैमाने पर मुसलमानों का नरसंहार किया जा सके. वैसे चौथी दुनिया ने जुलाई महीने में ही देश की जनता को आगाह कर दिया था कि दंगे होने ही वाले हैं और शरारती तत्वों के साथ–साथ आरएसएस और भाजपा के लोग बस मौक़े की तलाश में हैं. तीन महीने पूर्व उन्हें ऐसा ही एक मौक़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले शामली में हाथ लग गया.

देश के बदलते सामाजिक, राजनीतिक माहौल को देखते हुए चौथी दुनिया ने पहले ही यह आशंका जता दी थी कि दंगे होने वाले हैं.

दंगे होने वाले हैं

देश में जिस तरह का राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, उससे साफ लगता है कि दंगे होने वाले हैं. देश का मीडिया, राजनीतिक दल और राजनेता इस देश में दंगे कराने पर आमादा हैं. दंगे कराने वालों में सांप्रदायिक ताकतों के साथ- साथ वे कथित सेकुलर ताकतें भी हैं, जिनकी निगाह उस 19 फीसद वोटों पर है, जिन्हें वे बड़ी बेशर्मी से मुस्लिम वोटबैंक कहती हैं. कोई चेहरा दिखाकर मुसलमानों को डरा रहा है, तो कोई हमदर्द होने का दिखावा करके. हैरानी इस बात की है कि मुसलमानों के वोटों के लिए तो सब लड़ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए लड़ने वाला कोई भी नहीं है. मुसलमानों की समस्याएं ख़त्म करने के लिए न तो किसी के पास ठोस नीति है और न ही इरादा. सभी राजनीतिक दलों की एकमात्र रणनीति है, मुसलमानों के साथ फरेब करना. राजनीति के ऐसे फरेबी माहौल में मुसलमानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे क्या करें और कहां जाएं?

तीन महीने पूर्व यानी जून में हरिद्वार की एक हिंदू लड़की रुड़की के एक मुस्लिम लड़के के साथ शामली आई. ये दोनों शामली के आज़ाद चौक के नजदीक एक होटल में रुके. इन दोनों के साथ उस कमरे में उसके कुछ मुस्लिम दोस्त भी थे. इस घटना के बारे में जब शामली के एक मुस्लिम पत्रकार को पता चला तो उसने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दे दी. इंस्पेक्टर आरएन यादव ने पुलिस बल के साथ होटल में छापा मारा और इन लड़कों को पकड़ लिया. इसके साथ–साथ पुलिस ने कुछ और भी मुस्लिम लड़कों को भी गिरफ्तार किया, जो इसमें शामिल नहीं थे. इसी दौरान थाने से ही

किसी ने क्षेत्र के भाजपा विधानमंडल के नेता हुकुम सिंह को फोन करके बता दिया कि थाने में एक ऐसी हिंदू लड़की मौजूद है, जिसके साथ यहां के मुस्लिम लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया है. हुकुम सिंह फौरन ही थाने पहुंच गए और पुलिस पर दबाव बनाने लगे कि वहां पर मौजूद मुस्लिम लड़कों के साथ–साथ कुछ दूसरे मुस्लिम लड़कों के ख़िलाफ़ भी बलात्कार का मामला दर्ज किया जाए. गांव के कुछ लोगों के अनुसार, हुकुम सिंह जिन दूसरे मुस्लिम लड़कों के ख़िलाफ़ पुलिस केस दर्ज कराना चाहते थे, उनका इस लड़की के साथ कोई संबंध नहीं था. हुकुम सिंह दरअसल जाटों और मुसलमानों को एक–दूसरे से लड़ाकर आगे की राजनीतिक रणनीति के तहत यह सब काम कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने जान–बूझकर कुछ निर्दोष मुसलमानों के ख़िलाफ़ पुलिस केस दर्ज कराने की कोशिश की. इंस्पेक्टर आरएन यादव ने हुकुम सिंह की बात को मानने से इन्कार कर दिया और कहा कि लड़की जिसका नाम लेगी, उसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज होगा. पुलिस के पूछने पर हरिद्वार की इस हिंदू लड़की ने रुढ़की के मुस्लिम लड़के को अपना दोस्त बताया और कहा कि वो यहां घूमने आई थी. पुलिस के सामने अपनी बात बनते न देखकर हुकुम सिंह वहां से नाराज़ होकर चले गए और उन्होंने पहले तो भाजपा कार्यकर्ताओं को भड़काया और फिर अपने अन्य साथियों की सहायता से हिंदुओं, विशेषकर जाटों में अफवाह फैलानी शुरू कर दी. अफ़वाह के कारण हिंदुओं में मुसलमानों के विरुद्ध गुस्सा फूटने लगा और उन्होंने इस घटना के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. इस घटना पर भाजपा ने शामली में तीन दिन के बंद का ऐलान भी किया. हालांकि जब शामली के एसपी अब्दुल हमीद ने विरोध करने वाले हिंदुओं पर एक जगह लाठीचार्ज का आदेश दिया तो उन पर यह आरोप लगाया जाने लगा कि वह मुसलमानों का साथ दे रहे हैं और दोषियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. इलाक़े के हिंदुओं की ओर से एसपी अब्दुल हमीद को हटाने की भी मांग ज़ोर पकड़ने लगी और आख़िरकार उनको वहां से हटना ही पड़ा.

भाजपा नेता हुकुम सिंह ने इस बीच शामली के कुछ गावों में पंचायत बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन चूंकि वहां के हिंदुओं ने जब हुकुम सिंह का साथ नहीं दिया और कोई भी हिंदू किसी भी पंचायत में शामिल नहीं हुआ तो हुकुम सिंह ने शामली छोड़कर मुजफ्फरनगर का रुख़ किया और वहां के हिंदुओं को अपने साथ मिलाने की कोशिश शुरू कर दी.

हुकुम सिंह पर शामली के मुसलमानों का यह भी आरोप है कि उन्होंने मार्च में होली से एक दिन पहले अपने पैतृक गांव बुच्चाखेड़ी (कोतवाली केराना, ज़िला शामली) में होली के मौक़े पर जलाने के लिए जमा की गई लकड़ी में स्वयं कुछ हिंदुओं से कहकर आग लगवा दी और मुसलमानों पर इसका आरोप लगा दिया. इसके बाद वहां की मस्जिद के एक इमाम को पीटा गया, एक मस्जिद की दीवार गिरा दी गई. और मस्जिद में मौजूद क़ुरआन के 40 नुस्ख़ों को आग लगा दी. उल्लेखनीय है कि बुच्चाखेड़ी (शेष पृष्ठ 2 पर)

लम्हों की खता से सदियों को बचाना होगा 03

बिहार की राजनीति में वंशवाद का ज़हर 05

संगीनों के साये में संगीत की महफ़िलें 07

साईं की महिमा 12

दंगे शुरू हो चुके हैं

पृष्ठ एक का शेष

जाट बहुल गांव है, जिसमें मुसलमानों के केवल 20 घर हैं. इसके बाद बुच्चाखेड़ी में तनाव बढ़ गया. लिहाज़ा, तत्कालीन एसपी अब्दुल हमीद और एडीशनल एसपी अतुल सक्सेना ने गांव के कुछ दोषियों को पकड़ा और उनमें से कुछ को जेल भी हुई, लेकिन मस्जिद में आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों को हुकुम सिंह ने गिरफ्तार नहीं होने दिया. ये लोग आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. इस घटना के बाद वहां के हिंदुओं और मुसलमानों ने एक अमन कमेटी गठित की और दोनों समुदायों के लोगों को समझाने की कोशिश की. कुछ दिनों तक इस गांव में शांति रही, लेकिन पुन: तनाव शुरू हो गया.

बुच्चाखेड़ी की घटना के बाद हुकुम सिंह के कहने पर भाजपा और आरएसएस से जुड़े कुछ कट्टर तत्वों ने जगह–जगह पर मुसलमानों को अकेला पाकर मारने–पीटने का सिलसिला शुरू कर दिया. ये लोग जहां भी दाढ़ी–टोपी वाले मुसलमानों को देखते, उनकी पिटाई कर देते या गालियां बकते थे. उनमें से अधिकतर या तो तब्लीग़ी जमात से जुड़े हुए थे या फिर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे थे. इसका उद्देश्य मुसलमानों को अपमानित करके उन्हें भड़काना था. दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमानों को निशाना बनाने की घटना विशेषकर दिल्ली से मुज़फ़्फ़रनगर, देवबंद या सहारनपुर जाने वाली रेलगाड़ियों में घटी और बीच रास्ते में उन मुसलमानों के साथ मारपीट की गई. इससे मुसलमानों में भी हिंदुओं के विरुद्ध गुस्सा भड़कने लगा, जिसे हुकुम सिंह और उनके साथी लगातार हवा देते रहे. दरअसल, हुकुम सिंह की शुरू से यही कोशिश थी कि क्षेत्र के हिंदू (जाट और गुर्जर) मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और पूरी तरह हुकुम सिंह या उनकी पार्टी भाजपा का साथ दें.

ट्रेन, बस, टैम्पो और मोटरसाइकिल से सफर कर रहे दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमानों को जगह–जगह पर मारने–पीटने का सिलसिला शामली और मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले में लगातार जारी रहा. इसी बीच शामली ज़िले में एक ऐसी घटना हुई, जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ज़बरदस्त टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दी. लखनऊ के रहनेवाले तीन मुसलमान जो देवबंद के एक मदरसे में शिक्षक हैं, बीते 29 अगस्त को कांधला (ज़िला शामली) के मशहूर धर्मगुरु मौलाना इतिख़ार उल हसन से मुलाक़ात करने के लिए आ रहे थे, उसी समय कुछ कट्टर हिंदुओं ने कांधला थाने के तहत आनेवाले भभीसा गांव में उन तीनों को ज़बरदस्ती टैम्पो से उतारा और उनमें से दाढ़ी और टोपी वाले दो मुसलमानों को बुरी तरह मारा–पीटा, जबकि तीसरे को इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि उसके चेहरे पर न तो दाढ़ी थी और न ही सिर पर टोपी. इस घटना की ख़बर जैसे ही कांधला पहुंची, वहां के मुसलमानों में ज़बरदस्त गुस्से की लहर दौड़ गई. उन्होंने बड़ी संख्या में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और पुलिस से दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे. स्थिति को बिगड़ता देखकर क्षेत्र के ज़िलाधिकारी (डीएम) प्रवीण कुमार ने मुसलमानों को समझाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही दोषियों को पकड़ा जाएगा, जिसके बाद मुसलमान अपने–अपने घर वापस लौट गए.

दूसरी ओर इससे दो दिन पहले ही यानी 27 अगस्त को मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के कवाल गांव में तीन लड़कों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें से एक तो मुसलमान था, जबकि दो लड़के हिंदू थे. घटना बहुत साधारण थी, लेकिन इसी ने इस इलाक़े में काफ़ी दिनों से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच चले आ रहे तनावपूर्ण माहौल को पूरी तरह बिगाड़ दिया, जिससे इस क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम फ़साद फूट पड़ा. दरअसल, विशाल और सचिन नाम के दो जाट लड़कों ने कवाल गांव के चौराहे पर शाहनवाज़ नाम के एक मुस्लिम लड़के को अपनी मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी. तीनों में तू–तू, मैं–मैं हुई और बात इतनी बिगड़ गई कि विशाल और सचिन ने शाहनवाज़ की हत्या कर दी और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागने लगे, लेकिन चूंकि कुछ फ़ासले पर मुसलमानों के कई घर हैं. लिहाज़ा, मुसलमानों ने इन दोनों जाट लड़कों की भी वहीं हत्या कर दी. इसके बाद जाटों की ओर से विभिन्न गावों में पंचायतें शुरू हुईं. मामले को बिगड़ता हुआ देख, इस पूरे इलाक़े में दफ़ा 144 लगा दी गई, लेकिन पुलिस ने इस पर सख़्ती से अमल नहीं कराया. पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण जाटों द्वारा कवाल, गंगेरू, लिसाढ़, बहावड़ी, फुगाना, बसी, पलड़ी, जांसठ, शाहपुर, लांख, खरड़ आदि विभिन्न गांवों में अवैध रूप से पंचायतें होती रहीं और पंचायतों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ न केवल नारेबाज़ी की गई, बल्कि उन्हें जान से मारने का बाक़ायदा ऐलान भी किया गया. दंगा शुरू होने के बाद मुसलमानों का सबसे अधिक जान–माल का नुक़सान इन्हीं गांवों में हुआ.

> बुच्चाखेड़ी की घटना के बाद हुकुम सिंह के कहने पर भाजपा और आरएसएस से जुड़े कुछ कट्टर तत्वों ने जगह-जगह पर मुसलमानों को अकेला पाकर मारने-पीटने का सिलसिला शुरू कर दिया. ये लोग जहां भी दाढ़ी-टोपी वाले मुसलमानों को देखते, उनकी पिटाई कर देते या गालियां बकते थे. उनमें से अधिकतर या तो तब्लीग़ी जमात से जुड़े हुए थे या फिर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे थे. इसका उद्देश्य मुसलमानों को अपमानित करके उन्हें भड़काना था. दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमानों को निशाना बनाने की घटना विशेषकर दिल्ली से मुजफ्फरनगर, देवबंद या सहारनपुर जाने वाली रेलगाड़ियों में घटी और बीच रास्ते में उन मुसलमानों के साथ मारपीट की गई.

कवाल गांव की इस घटना से आक्रोशित होकर 52 गांवों पर आधारित गठवाला खाप के चौधरी बाबा हरि किशन ने 5 सितंबर को अपने पैतृक गांव लेसाढ़ा (जो थाना फुगान, जिला मुज़फ़्फ़रनगर के तहत आता है) और फिर दो दिन बाद यानी 7 सितंबर को नांगला मंडोर में एक महापंचायत बुलाई. इस पंचायत में इन सभी 52 गांवों के जाट शामिल हुए और भाजपा और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के अलावा कई जाट प्रतिनिधियों ने भड़काऊ भाषण दिया और मुसलमानों के विरुद्ध नारेबाज़ी की. पंचायतों में जाने वाले ये लोग मुसलमानों की जिन–जिन बस्तियों से गुज़रे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ूब नारेबाज़ी की और भाले, फरसे के रूप में वे जो भी हथियार लेकर जा रहे थे, उसे हवा में लहराया. नांगला की महापंचायत में जाते हुए जाटों का जब एक क़ाफ़िला बस्सी पलड़ी गांव पहुंचा तो वहां पर स्थित एक मदरसे के बाहर चार पुलिसवाले पहले से तैनात थे, जिन्होंने इन जाटों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी करने से मना किया. इस पर वे लोग पुलिस वालों को ही मारने लगे, तब पुलिस ने मदरसे में मौजूद मुसलमानों से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई. लिहाज़ा, मुसलमानों ने इन जाटों पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए. ये जाट जब नांगला मंडूर की महापंचायत में पहुंचे तो भाजपा के नेताओं ने उन्हें स्टेज पर बुलाकर वहां मौजूद सारे लोगों को भड़काया और कहा कि देखो मुसलमान किस प्रकार हिंदुओं को मार रहे हैं. इसी के बाद इस पूरे क्षेत्र में मुसलमानों को मारने–काटने की शुरुआत हुई और यह आग गठवाला खाप के तहत आने वाले सभी 52 गांवों में फैल गई. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 29
दिल्ली, 23 सितंबर–29 सितंबर 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय	0120–6451999
	6450888
	6452888
	011–23418962
विज्ञापन व प्रसार	+91–9266627379
फैक्स न.	0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

कुशल खिलाड़ी नीतीश

संकट की घड़ी में नेतागण आमतौर पर अपने राजनीतिक सहयोगियों की जगह विश्वस्त अधिकारियों की ओर रुख करते हैं. भाजपा से कटुतापूर्ण अलगाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने को चारों ओर से सुरक्षित करने के लिए अपने विश्वसनीय अधिकारियों को खोज लिया है. ये वे अधिकारी हैं जो नीतीश की घोषणाओं को अमली जामा पहनाते हैं. बिहार में जहरीले मिड डे मील की घटना के बाद खराब प्रशासन को लेकर चौतरफा आलोचना के बाद नीतीश ने 1984 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बुलाकर मुख्यमंत्री ऑफिस में विशेष ड्यूटी पर तैनात कर दिया है. लेकिन नीतीश यहीं पर नहीं रुके. वे पूर्व गृह सचिव आरके सिंह को भी वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं जो हाल ही में उनके सलाहकार के रूप में रिटायर हुए हैं. सिंह विनिर्माण विभाग में कई सालों पहले से मुख्य सचिव थे, वे तब से नीतीश के करीबी रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि इसी तरह दूसरे अधिकारी आरके राय को ऊर्जा सलाहकार और मंगला राय को कृषि सलाहकार बनाया है. सूत्रों के मुताबिक, ये अधिकारी मंत्रिमंडल के सहयोगियों की अपेक्षा नीतीश कुमार के ज्यादा करीब हैं. ■

पंजाब में अधिकारियों की भरमार

पंजाब में 1995 बैच के कई आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारियों की संख्या 50 पहुंच गई है. हाल में परमोद बैन, गौतम चीमा, सुरिंदर सिंह और तेजिंदर पाल सिंह का प्रमोशन हुआ है. व्यवहारिक तौर पर राज्य में नियुक्त हर तीसरा आईपीएस अधिकारी इंस्पेक्टर जनरल रैंक का है. इस तरह पंजाब में 17 एडीशनल डीजीपी और चार डीजीपी हैं. पंजाब उच्च अधिकारियों की संख्या के मामले में देश में सबसे आगे है.

सूत्रों का कहना है कि यह स्थिति अचानक नहीं बनी है. इसकी नींव पड़ी 1980 के दशक में, जब पंजाब अलगाववादी आंदोलन की चपेट में था. इस समय राज्य में 172 आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति की अनुमति है और इसमें से 94 वरिष्ठ अधिकारी हैं. डीआईजी और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों की संख्या 49 है. 1980 के दशक के अंधेरे दिनों में तो ठीक था, लेकन उसके बाद लगातार पंजाब सरकार ने राज्य पुलिस में पदानुक्रम के संतुलन पर ध्यान नहीं दिया. ■

बाबुओं पर राजनीति

महाराष्ट्र में एक बाबू की सार्वजनिक निर्माण विभाग में बतौर सचिव नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अपने कैबिनेट सहयोगी और पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल के विरोध में आ गए. सूत्रों का कहना है कि मामले में मोड़ तब आया, जब साधारण और विशेषज्ञ पर चर्चा शुरू हो गई, जो कि बाबुओं के गलियारे में अक्सर होता रहता है. भुजबल का तर्क था कि नौकरशाह को ऐसे उच्चस्तरीय तकनीकी विभाग का प्रमुख नहीं बनाया जा सकता. लेकिन मुख्यमंत्री की चिंता थी कि चूंकि विभाग में तमाम घोटालों के चलते हलचल मची थी, उसे साफ–सुथरा रखा जाए. वे पीडब्ल्यूडी का प्रमुख एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त करने के पक्ष में थे. चव्हाण ने वी गिरिराज को नियुक्त करना चाह रहे थे, जो इसके पहले जल संसाधन सचिव थे. अब उनकी जगह मालिनी शंकर ने ले ली है. भुजबल ने अपने विभाग का प्रमुख एक इंजीनियर को बनाए जाने के पक्ष में थे. उन्होंने आइएएस अधिकारी की नियुक्ति का विरोध किया. अब इस राजनीतिक उठापटक में किसको महत्व दिया जाता है, यह देखना अभी बाकी है. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

प्रवीन एनएससीएफडीसी में सीएमडी नियुक्त

1998 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस प्रवीन सिन्हा को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है.

अनुज शर्मा गृह मंत्रालय गए

अनुज शर्मा को गृह मंत्रालय में निदेशक नियुक्त गया है. वे 1991 बैच के आईडीईएस हैं.

अमिय चाय बोर्ड में शामिल

अमिय कुमार दास को टी बोर्ड में वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी नियुक्त किया गया है. यह बोर्ड कोलकाता के बाहर स्थित है. चाय बोर्ड वाणिज्य विभाग की एक स्वायत्त संस्था है.

अरविंद जापान स्थित भारतीय दूतावास से जुड़े

1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अरविंद सिंह जापान के भारतीय दूतावास में मंत्री (वाणिज्य और आर्थिक) के रूप में शामिल होने के लिए जल्द ही टोक्यो जाएंगे. सिंह को 1985 बैच के आईएएस अरुण गोयल की जगह नियुक्त किया गया है.

नीरजा विद्युत प्राधिकरण में अध्यक्ष नियुक्त

नीरजा माथुर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं. वर्तमान में नीरजा (ग्रिड संचालन एवं वितरण) सदस्य हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

> 1857 की लड़ाई के दौर से मुजफ्फरनगर क्षेत्र हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक बना रहा. उस वक्त की सोच के बदलाव के साथ-साथ पास के दूसरे शहर भले ही सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आए, लेकिन मुजफ्फरनगर उनकी आंच से अछूता रहा. पास के ही जिले मेरठ ने तो सांप्रदायिक दंगों का पूरा इतिहास ही अपने भीतर समेट लिया, लेकिन मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक स्तर का यह बंटवारा बड़े पैमाने पर अभी तक नहीं पहुंचा था.

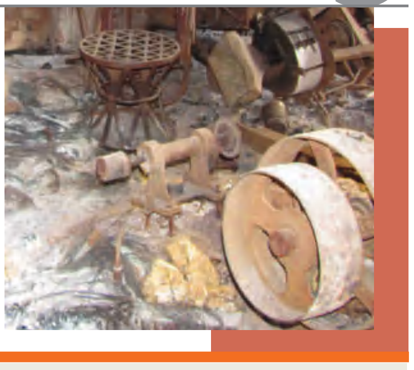

लम्हों की खता से सदियों को बचाना होगा

इन दंगों की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सामाजिक तानेबाने को चोट पहुंची है. चोट यहां की उस सामाजिक संरचना को भी पहुंची है, जो हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए मिसाल के तौर पर पेश की जाती है. एक तरफ जहां पूरे देश में हिंदू-मुस्लिम के बीच सांप्रदायिकता की खाई को बढ़ाकर वैमनस्यता के बीज बोए जा रहे हैं, वहीं इस क्षेत्र में अरसे से हिंदू-मुस्लिम सद्भाव की अनूठी तस्वीर लोगों के सामने आती रही है. यह बात सही है कि बदलते वक्त के साथ सद्भाव के ये सभी उदारण भले ही अब अतीत की ओर झांक रहे हैं और इन दंगों के माध्यम से यह समझा जाने लगा कि यहां भी सांप्रदायिक मसले सिर उठा रहे हैं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र की जातीय संरचना पर गौर करें तो ऐसी तस्वीर उभरकर आती है, जो इस दंगे को सांप्रदायिक दंगे से परे सामाजिक (जातीय) दंगे की ओर ले जाती है. ऐसा क्यों हुआ, इसे समझने की जरूरत है...

नीरज सिंह

जमीला ने ईदगाह में एक बेटे को जन्म दिया है. शामली जिले की कांदला लहसील की ईदगाह में. जबकि उसका घर मुजफ्फरनगर जिले के लिसाड़ गांव में है. दूसरे गांव में और वह भी ईदगाह में एक बच्चे का जन्म चौंकाता जरूर है. अपने घर में नहीं, ईदगाह में! क्योंकि घर अपना रहा ही नहीं. वह दंगों की भेंट चढ़ गया है. दंगों से पैदा हुई विभीषिका के मायने क्या हैं और इसका असर क्या होगा, इस नवजात को नहीं पता. लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो जिलों मुजफ्फरनगर और शामली में हुए दंगों ने देश के सामाजिक तानेबाने की बुनावट को जो चोट पहुंचाई है, जमीला के बेटे का इस तरह से जन्म लेना मौजूदा दौर का उदाहरण जरूर बनेगा.

इस पूरे क्षेत्र में विडंबनाओं की ऐसी कई तस्वीरें हैं. वक्त के साथ लोगों के मन में यह तस्वीरें धुंधली पड़ती जाएंगी. लेकिन इन दंगों ने सामाजिकता के स्तर पर जो दरार पैदा की है, उसके परिणाम लंबे समय तक लोगों के जेहन में बने रहेंगे. और यह सवाल भी बना रहेगा कि जो क्षेत्र धार्मिक सद्भाव के इतने मजबूत धागे से बंधा है, वह कैसे टूटा. और इस सवाल का जवाब खोजना ही अब सबसे मौजूं मसला है.

1857 की लड़ाई के दौर से यह पूरा क्षेत्र हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक बना रहा. उस वक्त की सोच के बदलाव के साथ-साथ पास के दूसरे शहर भले ही सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आए, लेकिन मुजफ्फरनगर उनकी आंच से अछूता रहा. पास के ही जिले मेरठ ने तो सांप्रदायिक दंगों का पूरा इतिहास ही अपने भीतर समेट लिया, लेकिन मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक स्तर का यह बंटवारा बड़े पैमाने पर अभी तक नहीं पहुंचा था. मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में अध्यापक रहे कासिम अली बताते हैं कि उनका जन्म 1937 में हुआ था, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और उनके होश संभालने तक देश आजाद हो चुका था. तब से लेकर आज तक उन्होंने इस क्षेत्र में हिंदू-मुस्लिम वैमनस्य नहीं देखा था. कासिम अली बताते हैं कि उनके पढ़ाए हुए इलाके के कई हिंदू लड़के बड़े पदों पर हैं जो कि उनका पैर छूकर उन्हें सम्मान देते हैं. फिर यह दंगा क्यों? इस सवाल के जवाब में कासिम चुप हो जाते हैं, फिर कहते हैं दंगानियों ने मेरी 12 कमरों की हवेली जला दी, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानता कि वे मेरे गांव या मेरे इलाके के लोग रहे होंगे. मेरे गांव में तो धर्म के नाम पर कोई बंटवारा नहीं था.

ऐसा नहीं है कि जिले में सांप्रदायिक सद्भाव की यह बातें बहुत पुरानी हैं और अब यह अपने ढलान पर है. कांधला प्रेस क्लब के अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार महावीर प्रसाद अग्रवाल बताते हैं कि ये बातें कुछ ही साल पुरानी हैं. हो सकता है कि आज के नौजवानों को इनकी याद न हो, लेकिन 35-40 साल की उम्र से ऊपर के लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं. उन्हें याद है कि इलाके में जनाजे और शवयात्राएं कैसे मिलजुल कर निकलती थीं. महावीर प्रसाद बताते हैं कि मंदिर-मस्जिद को लेकर देश में कितने दंगे हुए. जहां भी ऐसा संयोग हुआ कि मंदिर-मस्जिद साथ हैं, वहां भारी संख्या में फौज तैनात है, लेकिन मुजफ्फरनगर के कांधला कस्बे में स्थित जामा मस्जिद में एक तरफ अजान होती है, तो दूसरी ओर लक्ष्मी नारायण मंदिर में घंटे बजते हैं. इस सद्भाव को इतिहास के पन्नों की ओर ले जाते हुए वे बताते हैं कि 1391 में फिरोजशाह तुगलक शिकार खेलते हुए इस कस्बे में पहुंचा था, देर हो जाने के कारण उसने वहीं एक उच्च स्थान पर जुमे की नमाज अदा की और बाद में यहीं जामा मस्जिद खड़ी हुई, बाद में इसके बराबर में खाली पड़ी जगह पर जब मस्जिद को विस्तार देने का निर्णय लिया गया तो हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि यह जमीन हमारी है, हम यहां मंदिर बनाएंगे. उस समय मुस्लिम समाज के मौलाना महमूद बख्शकांधलवी ने सांप्रदायिक एकता की मिसाल कायम करते हुए कहा कि मस्जिद के बराबर में खाली जगह मंदिर की ही है, वहां पर मंदिर ही बनाया जाए. और लक्ष्मीनारायण मंदिर की स्थापना हुई. और तब से आज तक वहां पर नियमित नमाज और पूजा साथ में हो रही है. पास में ही हिंदुओं का श्मसान घाट और मुस्लिमों के ईदगाह में बस एक दीवार का फासला है. कभी कोई मुश्किल नहीं आई.

यह बात सही है कि बदलते वक्त के साथ सद्भाव के ये सभी उदारण भले ही अब अतीत की ओर झांक रहे हैं और इन दंगों के माध्यम से यह समझा जाने लगे कि यहां भी सांप्रदायिक मसले सर उठा रहे हैं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र की जातीय संरचना पर गौर करें तो ऐसी तस्वीर उभरकर आती है जो इस दंगे को सांप्रदायिक दंगे से परे सामाजिक (जातीय) दंगे की ओर ले जाती है. सांप्रदायिक दंगे और सामाजिक दंगे के फर्क को समझने के लिए हमें यहां की जातीय बुनावट को समझना होगा. समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवाम की पहचान धर्म से ज्यादा बिरादरी के आधार पर होती है, क्योंकि इनके नाम ऐसे हैं कि उस आधार पर इनमें धार्मिक विभेद करना बड़ा ही मुश्किल है. सदियों पहले मुसलमान बनी बिरादरियों की पहचान अभी तक उनके अपने ही स्वरूप में स्थापित है. जाट समुदाय के जिन लोगों ने सदियों पहले मुस्लिम धर्म अख्तियार कर लिया, उन्हें अब मूला जाट कहा जाता है. त्यागी समाज के जो लोग मुसलमान बने, उन्हें अब मसेहरा कहा जाता है. राजपूतों को रांधड़ और मुसलमानों को मुस्लिम गुर्जर. राकेश जाट और जहीर जाट, इन नामों के आधार पर गैर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता शायद ही यह विभेद कर पाए कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है.

विश्व भर में लेखक व इस्लामी चिंतक के तौर पर मशहूर मौलाना नूर-उल हसन राशिद बताते हैं कि जो राजपूत हिंदू मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हुए हैं, अब वे मुसलमान भले हों, लेकिन राजपूत होने के नाते उनकी बिरादरी में गोत्र में शादी को अच्छा नहीं माना जाता. यह बात हर स्तर पर सही नजर आती है. सामान्य जीवन में मनाई जाने वाली उनकी परंपराओं को देखिए तो आज भी वहां के मुस्लिम समाज में शादी में भात और बच्चे के जन्म पर छठी जैसे संस्कार उसी शिद्दत के साथ मनाए जाते हैं, जैसे हिंदू परिवारों में. धर्म से पहले जाति-बिरादरी को प्राथमिकता ने इस क्षेत्र को धार्मिक आधार पर विभाजित नहीं होने दिया.

यह दंगा सांप्रदायिक न होकर कुछ और मायनों में भी सामाजिक है. दंगा पीड़ितों में सबसे ज्यादा प्रभावित निचले तबके के लोग हैं. जो संपन्न मुस्लिम हैं, वे इस वैमनस्य के खामियाजे से दूर हैं. शरणार्थी शिविरों में रह रहे प्रभावित लोगों में ज्यादातर लोग अंसारी, सैफी, सलमानी जैसी निचली जातियों के मुसलमान हैं और इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो लोहार धोबी, बढ़ई जैसे पारंपरिक रोजगार से जुड़े हुए थे. आश्चर्य की बात तो यह है कि जाटों के जो धार्मिक संगठन हैं, प्रभावित मुस्लिम लोगों में अधिकांश उनके सेवादार हैं. फिर ये लोग दंगों की भेंट क्यों चढ़े. इसकी एक ही वजह नजर आती है कि जब नफरत का गुबार फैला तो उसने उन्हीं को चपेट में लिया जो लोग इसका प्रतिरोध करने में अक्षम थे. जो लोग ताकतवर थे, वे चाहे हिंदू हों या मुसलमान, वे दंगों की तपिश से दूर रहे. हां, यह सवाल जरूर है कि अगर गरीब तबके का मुसलमान दंगों की गिरफ्त में था तो उनके समर्थ मुसलमान भाई उन्हें बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आए. साफ है कि कहीं न कहीं सामाजिक एकरूपता की भूमि पर आर्थिक स्तर का विभेद जन्म ले रहा है. हालांकि, ऐसे कई उदाहरण सामने आए, जिसमें हिंदुओं ने मुसलामानों की रक्षा की और मुसलामानों ने हिंदुओं की, जो इस बात की ओर इशारा है कि जो लोग फसाद की जड़ में शामिल थे, वे किसी प्रतिरोध कि वजह से नहीं, बल्कि किसी और के द्वारा संचालित होकर इसे अंजाम दे रहे थे.

भारत के सभी गांवों में आज भी सामाजिक स्तर पर आधुनिकता और परंपरा के बीच में एक बड़ी खाई है. पश्चिमी उप्र प्रदेश में यह खाई अभी भी काफी गहरी है. इसके पीछे भी वहां की जातीय संरचना ही है. खाप और जत्थेदारों की पारंपरिक सोच नई पीढ़ी के आधुनिक विचारों को अभी भी अपनी सामाजिकता के लिए खतरा ही मानती है. यह सोच दोनों ही धर्मों के लोगों से साथ है, क्योंकि दोनों की जड़ें एक ही हैं. इसीलिए कई बार सामान्य छेड़छाड़, प्रेम-प्रसंग और अंतरधार्मिक विवाह जैसे मामले बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं. खापों की पंचायतों तक मामले पहुंच जाते हैं. देश के दूसरे हिस्सों में यह घटनाएं अब आम हो चली हैं. प्रशासनिक स्तर पर देश के अन्य हिस्सों में ऐसी घटनाओं को हल्के और चटखारे के रूप में ही लिया जाता है, लेकिन यहां पर इसे जाति-धर्म और परंपरा के ऊपर खतरे से जोड़कर ही देखा जाता है. प्रशासनिक स्तर पर ऐसी शिकायतों की अनदेखी कई बार यहां पर बड़े बवाल का कारण बनी है और ऐसी अनदेखियों ने इस बार दंगे का रूप ले लिया. ऐसे ही मसले को लेकर शुरू हुई पंचायत ने महापंचायत का रूप धर लिया और महापंचायत ने महाभारत का.

भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष तरुण अग्रवाल बताते हैं कि जिले में ऐसे सदंर्भों से जुड़े कई प्रकरण हुए. दोनों ही समुदायों द्वारा उनकी गलत व्याख्या भी की गई. और पास के जिलों जैसे मेरठ में इसे लव जिहाद की संज्ञा दी जाने लगी. इस जिले में भी धीरे-धीरे यह मान्यता हिंदू समाज के लोगों के दिमाग में मुस्लिम समाज के प्रति नफरत पैदा कर रही थी. इधर युवा हिंदुओं के मन में पारंपरिक वेशभूषा में रहने वाले मुसलमानों के प्रति एक घृणित मानसिकता जन्म ले रही थी, जिसकी वजह से इन जिलों के आस-पास से गुजरने वाले ऐसे मुसलमानों को लगातार परेशान किया जा रहा था. धीरे-धीरे यह छोटी-छोटी छड़पें एक दिन प्रतिक्रिया में बदल गईं.

दंगों के पीछे की वजह तलाशने पर एक बात और चौंकाने वाली दिखती है, जब समूचे प्रकरण में कोई आर्थिक कारण नजर नहीं आता. शामली जिले में मार्च महीने में एक समुदाय द्वारा पंचायत बुलाई गई तो अधिकांश लोगों ने उस समुदाय में सिर्फ यह कहकर शामिल होने से मना कर दिया कि एक दिन की छुट्टी लाखों का नुकसान कर देती है. पश्चिमी यूपी के समूचे देहात की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है. प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जीडीपी मुजफ्फरनगर और शामली की ही है, जिनमें मुसलमान और हिंदू दोनों बराबर के भागीदार हैं. अगर चीनी और गुड़ की मिलों में अधिकांश कब्जा हिंदुओं का है तो लोहे की बड़ी मिलें मुसलमानों के पास हैं. उप्र व्यापार मंडल के प्रांतीय मंत्री ईश्वर दयाल कंसल बताते हैं कि मिलों के अलावा जो अन्य व्यापार हैं, वह 60 प्रतिशत हिंदू और 40 प्रतिशत मुसलमानों के पास हैं. कोई बड़ा अंतर नहीं है कि उसे हासिल करने के लिए वर्चस्व की लड़ाई हो.

वास्तव में मुजफ्फरनगर और उसके आसपास फैली नफरत की आग की वजहों के बीच कई छोटे-छोटे कारण हैं. वह धार्मिक भी हैं, सामाजिक भी, प्रशासनिक और राजनीतिक भी. लेकिन यह वक्त उन वजहों को खोजने से ज्यादा उन उपायों को तलाशने का है, जो मिसाल बन चुकी यहां की सामाजिक समरसता को वापस लाएं. लम्हों की इन खताओं को बयां करता एक शेर बड़ा मौजूं है कि वह दौर भी देखा है तारीख की आखों में. लम्हों ने खता की है सदियों ने सजा पाई. वास्तव में यह आशंकाएं लम्हों की खता से ही पैदा हुई हैं, लेकिन कोशिश यह हो कि इसका असर लोगों की तकदीर में सदियों के लिए न हो. शायद यही कोशिश जमीला के बेटे का इस तरह से जन्म लेना मौजूदा दौर का उदाहरण बनने से जरूर बचा पाएगी. ■

> **भारत के सभी गांवों में आज भी सामाजिक स्तर पर आधुनिकता और परंपरा के बीच में एक बड़ी खाई है. पशिचमी उप्र प्रदेश में यह खाई अभी भी काफी गहरी है. इसके पीछे भी वहां की जातीय संरचना ही है. खाप और जत्थेदारों की परंपरिक सोच नई पीढ़ी के आधुनिक विचारों को अभी भी अपनी सामाजिकता के लिए खतरा ही मानती है. यह सोच दोनों ही धर्मों के लोगों से साथ है, क्योंकि दोनों की जडें एक ही हैं. इसीलिए कई बार सामान्य छेड़छाड़, प्रेम-प्रसंग और अंतरधार्मिक विवाह जैसे मामले बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं. खापों की पंचायतों तक मामले पहुंच जाते हैं. देश के दूसरे हिस्सों में यह घटनाएं अब आम हो चली हैं.**

feedback@chauthiduniya.com

अफसोस है कि समाजवादी सरकार बसपा राज के भ्रष्टाचार का तो खूब ढिंढोरा पीटती है, लेकिन बसपा राज में कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक दंगों या तनाव के समय बसपा सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कड़े कदमों की तरफ उसका ध्यान कभी नहीं जाता है. बसपा राज में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए तो इसकी एक मात्र वजह थी तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का ऐसे मौकों पर निष्पक्ष होकर पुलिस को सख्ती के साथ पेश आने की छूट देना.

सपा सरकार पर एक साल में 104 दंगों का कलंक

यूपी में छोटी-छोटी घटनाएं बड़े तनाव की वजह बन रही हैं, लेकिन दिल्ली की गद्दी के लिए उतावले सपा नेताओं ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. अखिलेश यादव राज्य के हालात से निपटने की बजाय अन्य राज्यों में सपा को मजबूत करने के लिए दौरे कर रहे थे. अक्सर देखने में यह आया है कि अखिलेश को जहां होना चाहिए होता है, वह वहां नहीं दिखते हैं. यह स्थिति इसलिए आती है, क्योंकि उनके ऊपर बैठे सुपर सीएम राजनीति के मैदान में उनके आका हैं. सांप्रदायिक हिंसा की वारदातों के बाद नेता मरहम लगाने के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण का खेल शुरू कर देते हैं.

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के डेढ़ वर्ष के शासनकाल में करीब सौ से अधिक बार राज्य की जनता सांप्रदायिकता की आग में झुलस चुकी है. दर्जनों लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं. हालिया दंगों में घायल हुए सैकड़ों लोग अस्पतालों में हैं. दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन, कारोबार सब ध्वस्त है. लेकिन कोई इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि क्यों रह-रहकर लोग खून के प्यासे हो जाते हैं. प्रदेश को सरकार की नाकामी की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है. क्या विपक्ष समाजवादी सरकार को बदनाम करने के लिए सूबे की आबो-हवा में सांप्रदायिकता का जहर घोल रहा है या फिर सरकार के नाकारेपन से प्रदेश बार-बार दंगों की आग में झुलस रहा है? या फिर खुद सरकार चुप रहकर दंगों को हवा दे रही है? ये सवाल अनुत्तरित हैं. सबसे दुख की बात यह है कि ऐसे मौकों पर जनता के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नेतागण आरोप-प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाते हैं. वे किसी तरह की जिम्मेदारी लेने की बजाय राजनीति शुरू कर देते हैं. अधिकारियों को जानबूझ कर कार्रवाई करने से रोका जाता है. सवाल उठता है कि जब दंगे की संभावना मात्र से एक आईएएस को निलंबित किया जा सकता है तो फिर इस सरकार को भी तो कुछ सजा मिलनी चाहिए, जिसके राज में दंगों की बाढ़ आई हुई है. यह कहकर सरकार अपने दामन के दाग नहीं धो सकती है कि यह विपक्षियों की साजिश है. हालात ऐसे ही बने रहे तो समाजवादी सरकार के लिए अपना कार्यकाल पूरा करना मुश्किल हो जाएगा.

दुखद है कि मुजफ्फरनगर में भड़के दंगों को अन्य जिलों में फैलने से रोकने में राज्य सरकार नाकाम साबित हुई. मुजफ्फरनगर की हिंसा ने तो सारे रिकार्ड ही तोड़ दिए. जिला स्तर के कुछ अधिकारियों का निलंबन या फिर तबादला करके सरकार की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती है. मुख्यमंत्री अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, वह ऐसे मौकों पर क्या कर करते रहते हैं. डीजीपी देवराज नागर, एडीजी लॉ एंड आर्डर अरुण कुमार मुजफ्फरनगर ने दंगा प्रभावित इलाके का दौरा किया था. सब कुछ ठीक-ठाक होने की बात कही जा रही थी. लखनऊ में बैठे मुख्य सचिव जावेद उस्मानी भी सरकार के सुर में सुर मिला रहे थे. केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार को सचेत कर चुका था कि छोटी-छोटी घटनाएं बड़े तनाव की वजह बन रही हैं, लेकिन दिल्ली की गद्दी के लिए उतावले सपा नेताओं ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राज्य के हालात से निपटने की बजाय अन्य राज्यों में सपा को मजबूती प्रदान करने के लिए दौरे कर रहे थे. अक्सर देखने में यह आया है कि अखिलेश को जहां होना चाहिए होता है, वह वहां नहीं दिखते हैं. यह स्थिति इसलिए आती है, क्योंकि उनके ऊपर बैठे सुपर सीएम राजनीति के मैदान में उनके आका हैं. सांप्रदायिक हिंसा की वारदातों के बाद नेता मरहम लगाने के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण का खेल शुरू कर देते हैं. अयोध्या विवाद के बाद ऐसा ही ध्रुवीकरण सपा-भाजपा के बीच देखने को मिला था, जिसका नतीजा यह हुआ कि दोनों पार्टियों ने उसका फायदा तो उठाया ही, कई वर्षों तक सूबे सियासत पर उसका असर देखा गया.

राजनीतिक हरकतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए साम्प्रदायिकता भड़काना अनिवार्य हो गया हो. जिस राज्य का मुखिया इंसाफ और सजा का पैमाना अपराधी या फिर भुक्तभोगी की जात-बिरादरी देख कर तय करता हो, वहां की जनता का भगवान ही मालिक हो सकता है. जब उपद्रवी सेना के जवानों पर भी हमला करने की ताकत करने लगे, उपद्रवी खुले आम सुरक्षाकर्मियों के सामने असलहे लहराएं तो हालात की गंभीरता को समझा जा सकता है. सरकारी नाकामी या फिर वोट बैंक की राजनीति ही है जिसके चलते दंगे की आग गांवों तक पहुंच गई, जबकि इसके पहले शायद ही कभी देखने को मिला हो. सरकार एक पक्ष मात्र बन कर रह गई है.

अफसोस है कि समाजवादी सरकार बसपा राज के भ्रष्टाचार का तो खूब ढिंढोरा पीटती है, लेकिन बसपा राज में कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक दंगों या तनाव के समय बसपा सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कड़े कदमों की तरफ उसका ध्यान कभी नहीं जाता है. बसपा राज में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए तो इसकी एक मात्र वजह थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का ऐसे मौकों पर निष्पक्ष होकर पुलिस को सख्ती के साथ पेश आने की छूट देना था. वह जिलाधिकारी और एसएसपी जैसे बड़े अधिकारियों को जरा सी घटना होने पर ही तलब कर लेती थीं. यही वजह थी इस समय छोटी-छोटी घटनाओं को निपटाने में भी अधिकारी एड़ी-चोटी का जोर लगा देते थे. बात पुरानी नहीं है, बसपा राज में उच्च न्यायालय का अयोध्या विवाद मामले में अहम फैसला आया था, लेकिन कहीं कोई हिंसा नहीं फैली. दहशत का आलम यह था कि फैसला आने के समय लोग घरों में किसी अनहोनी के डर से कैद हो गए थे, लेकिन सरकार की मुस्तैदी के चलते जनजीवन पूरी तरह से सामान्य रहा. कहीं कोई कर्फ्यू नहीं लगा. यही फैसला आज आया होता तो क्या हालात होते, यह समझा जा सकता है.

बसपा राज का केएस बीएल फार्मूला

नौसिखुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तमाम दंगों के बाद भी पूर्ववर्ती बसपा सरकार के उस फार्मूले की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके सहारे माया ने यूपी में सांप्रदायिक ताकतों को उभरने नहीं दिया. कहीं कोई दंगा नहीं हुआ. यह फार्मूला तत्कालीन डीजीपी करमवीर सिंह (केएस) और इसी समय के एडीजी लॉ एंड आर्डर बृज लाल (बीएल) ने वर्ष 2010 में इस समय ईजाद किया था, जब अयोध्या विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला आने वाला था. इस फार्मूले के आधार पर प्रत्येक गांव में लोगों को पाबंद किया गया. ऐसे लोगों से जो दंगा भड़का सकते थे, उनसे शपथ पत्र लिया गया कि वह कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, नारेबाजी नहीं करेंगे और दंगा नहीं होने देंगे. प्रत्येक गांव में कुछ संभ्रात लोगों का गुट बनाकर उनके कंधों पर शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी डाली गई थी. इस गुट में दोनों की संप्रदायों के लोग शामिल थे. ये लोग पुलिस अधिकारियों के संपर्क में रहते थे. यहां तक कि डीजीपी तक से इस गुट की मोबाइल से सीधी बात होती थी. केएसबीएल फार्मूले को 'कानून व्यवस्था में जन सहयोग' का सरकारी नाम दिया गया था. डीजीपी लॉ एंड आर्डर बृज लाल अपराधियों को संरक्षण देने के खिलाफ थे, उनसे सत्तारूढ़ दल के दागी और दबंग विधायक तक डरते थे. बृज लाल के ऊपर बसपा का ठप्पा लगाकर सपा सरकार ने किनारे लगा दिया है.

सपा सरकार की नाकामी ही है जो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी समाजवादी सरकार के मुकाबले बसपा सरकार की तारीफ करने को मजबूर हो गए. प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैले सांप्रदायिक तनाव के बाद अखिलेश सरकार के खिलाफ केंद्र को लिखना पड़ गया. राज्यपाल ने दंगों के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया. बसपा सुप्रीमो को लगता है कि ऐसे दंगे भाजपा और सपा की राजनैतिक सांठगांठ से ही होते हैं.

केंद्र पहले ही इस बात पर नाराजगी जता चुका था कि उत्तर प्रदेश में छोटी-छोटी घटनाओं को समय रहते नहीं निपटाए जाने के कारण बाद में सांप्रदायिक हालत बिगड़ जाते हैं. ऐसा ही कुछ मुजफ्फरनगर के कवाल में भी हुआ. स्कूली लड़की से छेड़छाड़ के बाद दो गुटों में हुए झगड़े को समय रहते सुलटा लिया जाता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पुलिस ने एकतरफा और वह भी गैरवाजिब कार्रवाई करके दूसरे समुदाय की नाराजगी मोल ले ली. एक के बदले दो लाशें गिराने के जुनून ने सब कुछ तबाह कर दिया. जो सरकार महिला सशक्तिकरण के बड़े-बड़े दावे करती हो, उसके निजाम में महिलाओं-लड़कियों की आबरू से खिलवाड़ किया जाए, तो स्थिति की गंभीरता को समझा जा सकता है. अब बसपा, राष्ट्रीय लोकदल सहित संपूर्ण विपक्ष राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है.

संभावना यह भी जताई जा रही है कि दंगों की आड़ में 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न दलों द्वारा चुनावी बिसात बिछाई जा रही है. सीधे तौर प्रदेश में हिंसा के लिए अखिलेश सरकार ही जिम्मेदार है, लेकिन भाजपा भी इस मौके को अपने हित में भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है. वह अखिलेश सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाकर घेर रही है. पहले 84 कोसी परिक्रमा पर रोक के बहाने भाजपा ने सपा सरकार को घेरा, अब मुजफ्फरनगर में फैली सांप्रदायिक हिंसा के बहाने वह सरकार को घेर रही है. भाजपा नेताओं पर दंगा भड़काने का अरोप लगाए जाने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं.

दरअसल, जब दंगे की राजनीति शुरू होती है तो सबसे मुश्किल कांग्रेस और बसपा को होती है. भाजपा तो यह मान कर चलती है कि मुस्लिम वोट उसके हाथ नहीं लगने वाला है, इसीलिए वह हिंदू हितों के नाम पर सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाती है, लेकिन कांग्रेस और बसपा को मुस्लिम वोटों की भी दरकार रहती है, इसलिए वह तुष्टिकरण जैसे शब्द चाहकर भी इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं. यही कारण है कांग्रेस और बसपा को प्रदेश में राजनैतिक नुकसान होते दिखता है.

बहरहाल, दंगे करवाकर वोट बटोरने की राजनीति में मरना तो आम आदमी को पड़ रहा है. सभी दलों के नेता और जनप्रतिनिधि अपने-अपने घरौंदों में महफूज थे. दिन के उजाले में विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा अखबारी बयानबाजी करके संवेदना जताई जाती हैं तो शाम को दंगों से फायदे-नुकसान का लेखा-जोखा खंगाला जाता है. मुजफ्फरनगर शहर के समाजवादी विधायक चितरंजन स्वरूप इस समय राज्य सरकार में मंत्री हैं. जिले में जब नफरत की आग फैली तो वह कोसों दूर वाराणसी में थे. पूर्व डीजीपी श्रीराम अरुण पूरे घटनाक्रम पर काफी निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखते हुए कहते हैं, नौकरशाह हों या खाकी वर्दी वाले, सरकार का रुख जानते हैं. जहां काम करने वालों को सजा और नकारा अधिकारियों को पनाह दी जाती हो, वहां के हालात तो कुछ ऐसे ही होंगे. हालत यह है कि दंगों या अन्य आपराधिक वारदातों के समय पुलिस और प्रशासन सरकार की तरफ ताकते रहते हैं. ऐसे मौकों पर कार्रवाई करके दुर्गाशक्ति नागपाल की तरह निलंबन झेलने से बेहतर मूक दर्शक बने रहना है.

अखिलेश सरकार अमन-चैन के मोर्चे पर नाकाम हो रही है या फूट डालो राज करो की अंग्रेजी शैली को आगे बढ़ा रही है, यह तो वही जाने, लेकिन इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह आज अखिलेश ने मुख्यमंत्री ने बनते ही प्रदेश को दंगों की आग में झोंक दिया, उसी तरह मुलायम सिंह भी करते रहे हैं. मुलायम ने भी 1990-91 में यूपी को दंगों के हवाले कर दिया था. एक साथ प्रदेश के 45 जिलों में कर्फ्यू लगा था. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर मुजफ्फरनगर में जिस प्रायोजित तरीके से अफवाहें फैलाई गईं और और पुलिस ने दंगाइयों को माहौल में जहर घोलने का मौका दिया गया, उससे साफ है कि दंगे सरकार की शह पर ही हुए हैं.

पिछड़ा समाज महासभा के एहसानुल हक मलिक और भागीदारी आंदोलन के पीसी कुरील और भारतीय एकता पार्टी के सैयद मोइद अहमद कहते हैं कि सपा सरकार के डेढ़ वर्षों के शासनकाल में जिस तरह लगातार दंगे हो रहे हैं और सरकार इन्हें रोक पाने में विफल साबित हो रही है. यह इस बात का इशारा है कि सपा सरकार प्रदेश को सांप्रदायिकता के आगे न केवल नतमस्तक हो चुकी है, बल्कि इन दंगों की आड़ में हो रहे धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण को अपने चुनावी लाभ के तौर पर देख रही है. इन दंगों ने साबित कर दिया है कि प्रदेश की कानून और व्यवस्था चलाने वाले पुलिस अफसरों पर से सरकार का नियंत्रण एकदम खत्म हो गया है. मुजफ्फरनगर में जो भी हुआ, उसकी पृष्ठभूमि अचानक नहीं बनी है, लिहाजा इतने बड़े पैमाने पर हुए इस जनसंघार को प्रायोजित करने में किन किन की भूमिका है,इसकी सीबीआई जांच कराई जाए.

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं मंत्री राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि मुजफ्फरनगर में अशांति फैलाने वाले तत्वों की करतूत निदंनीय है. एक पत्रकार सहित निर्दोष लोगों की मौत दु:खद है. सरकार सांप्रदायिक शक्तियों पर अंकुश लगाने और शांति तथा सद्भावना बनाए रखने को कृत संकल्प है. सरकार को निशाना बनाकर कांग्रेस, बसपा और भाजपा के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं. वे सपा सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं.

सपा के अन्य नेता कहते हैं मुजफ्फरनगर में जो कुछ घटा है, उसके पीछे वे दल हैं जो राज्य सरकार की विकास योजनाओं से चिढ़े हैं और उन्हें अपनी जमीन खिसकती नजर आती है. इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं. किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती.

साल भर में दंगों का शतक

मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगों के बाद गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की. रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 2012 में सांप्रदायिक हिंसा के 104 मामले दर्ज किए गए. गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट में लिखा है कि 100 से ज्यादा दंगों में 34 लोगों की मौत हुई और 456 जख्मी हो गए. जबकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि 2012 में उत्तर प्रदेश में मात्र 27 दंगे हुए. अखिलेश इन दंगों का सारा दोष सांप्रदायिक ताकतों के सिर मढ़ रहे हैं कि ऐसी ताकतें सपा की सरकार को कमजोर करना चाहती हैं. एक वर्ष में दंगों का शतक लगाकर सपा सरकार ने अपनी खूब किरकरी कराई है. हालांकि, सपा को इससे अपना वोट बैंक मजबूत होता दिख रहा है. सत्ता में आने के कुछ ही माह बाद शायद अखिलेश सरकार समझ गई थी कि विकास और कानून व्यवस्था के मामले में हो रही फजीहत पर सांप्रदायिकता का पर्दा डालकर ही वोट बैंक सुरक्षित किए जा सकते हैं. अखिलेश राज के शुरुआती 12 महीने कानून व्यवस्था के लिहाज से बदतर साबित हुए हैं. रिकॉर्ड दंगों के चलते प्रचंड बहुमत की सरकार सवालों के घेरे में आ गई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

जवाहर लाल नेहरू ने अपनी बिटिया इंदिरा गांधी के लिए राजनीतिक गलियारे में सुरक्षित जगह बनाई थी. यह तब था जब आजादी के बाद यह आशा जगी थी कि देश को सामंतवाद और वंशवाद से छुटकारा मिलेगा और लोकतंत्र भारी पड़ेगा. लेकिन ऐसा नहीं हो सका. कांग्रेस पार्टी में यह सिलसिला तबसे चला आ रहा है. वंशवाद की जो परंपरा कांग्रेस में पड़ी, समय के साथ इसे क्षेत्रीय दलों ने भी अमल में लाना शुरू कर दिया.

बिहार की राजनीति में वंशवाद का ज़हर

लालू यादव और रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में वंशवाद का जहर मिलाने पर अड़े हैं. पासवान के बेटे चिराग के आने के बाद पार्टी की सेहत कैसे बिगड़ रही है, इसकी बानगी अब दिखने भी लगी है. दूसरी तरफ राजद की राजनीति को समझने वाले नेता बताते हैं कि लालू प्रसाद को अपने बेटों पर दांव लगाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि लालू अपने परिवार के बाहर किसी नेता को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है.

सरोज सिंह

लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान अगर अपने पुत्रों के लिए पूरी पार्टी को ही दांव पर लगाने का दुस्साहस कर रहे हैं तो इसमें नई बात क्या है. इतिहास के पन्नों को याद दिलाते उक्त शब्द राजद व लोजपा से जुड़े ऐसे नेताओं के हैं, जिनके पास विकल्प सीमित हैं और जिन्हें हर दिशा में केवल लालू प्रसाद और रामविलास पासवान ही नजर आते हैं, लेकिन जदयू व भाजपा में टूट के बाद संभावनाओं से लबरेज राजद व लोजपा के कई दिग्गज इसे अंतिम सत्य नहीं मान रहे हैं. इन दिग्गजों का मानना है कि पुत्र मोह में ये दोनों नेता अपने-अपने दल की संभावनाओं को कम कर रहे हैं और जनता के बीच हंसी के पात्र बन रहे हैं.

फिल्मों की चकाचौंध वाली दुनिया में लंबी पारी खेलने में असफल रहे रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान इन दिनों बिहार की गलियों की खाक छान रहे हैं. इस काम में उनके हमसफर खुद उनके पिता रामविलास पासवान बने हुए हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा हो या फिर युवा सम्मेलन, रामविलास पासवान अपने पुत्र चिराग पासवान के साथ रहने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं. अभी चिराग पासवान को सूत कतवाने रामविलास पासवान साबरमती आश्रम ले गए थे. संसदीय क्षेत्र के दौरे का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है. रामविलास पासवान ने एक झटके में ही चिराग पासवान को पार्टी की धूरी बना दिया और पूरी कोशिश में लगे हैं कि उनके बाद पार्टी की कमान चिराग पासवान के ही हाथ में रहे. पूरी पार्टी अब हर दिशा-निर्देश के लिए चिराग की तरफ देखती रहती है.

चिराग पासवान बिहार की राजनीति के मन व मिजाज को कितना समझते हैं, इसकी परीक्षा तो अभी होनी बाकी है, पर पार्टी की सेहत चिराग के आने के बाद कैसे बिगड़ रही है, इसकी बानगी अब हर तरफ दिखनी शुरू हो चुकी है. नालंदा संसदीय क्षेत्र के कार्यक्रम में पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा. सूरजभान सिंह, रामा सिंह व राघवेंद्र कुशवाहा समेत कई बड़े नेताओं के नाम पोस्टरों में पटे थे, लेकिनअलग-अलग कारण बताकर ये नेता नालंदा नहीं पहुंचे. बताया जाता है कि चिराग पासवान इससे काफी नाराज हुए. चिराग बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए पार्टी के स्थापना दिवस 28 नवंबर को गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करना चाहते हैं.

बताया जा रहा है कि जब रैली करने का प्रस्ताव चिराग ने अपनी कोर कमेटी में रखा तो कई बड़े नेता बिदक गए. यहां तक कि उनके चाचा पशुपति पारस ने भी हाथ खड़े कर दिए. पारस का कहना था कि बड़ी रैली के लिए आवश्यक बजट का इंतजाम करना काफी मुश्किल है, इसलिए इस समय रैली करना उचित नहीं होगा, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि रैली हर हाल में होगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या नहीं. लोजपा में समाजवादी पृष्ठभूमि से जुड़े नेताओं का बड़ा तबका चिराग की इस तरह लॉन्चिंग के बेहद खिलाफ है. नाम न छापने की शर्त पर इन नेताओं का कहना है कि चिराग राजनीति में आए, इससे किसी को परहेज नहीं है, लेकिन जिस तरह चिराग को पार्टी में घुसाया जा रहा है, वह बर्दाश्त से बाहर की बात है. इन नेताओं का कहना है कि रामविलास पासवान के सामने भले ही नेता व कार्यकर्ता चिराग जिंदाबाद का नारा लगा देते हैं, लेकिन दिल से उन्हें अभी कोई पसंद नहीं कर रहा है. राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि रामविलास पासवान चिराग के मामले में कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं. आनन-फानन में उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाना उनकी एक बड़ी चूक है. इससे यह संदेश गया है कि रामविलास पासवान ने पार्टी व अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर अपने बेटे को तवज्जो दी. बेहतर होता कि रामविलास पासवान पहले चिराग को एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करने देते. इस दौरान चिराग कार्यकर्ताओं के दिलों में अपनी जगह बना सकते थे. ऐसा नहीं करके पहले से ही परिवारवाद का उलाहना सुनते रहे रामविलास पासवान ने अपने आलोचकों को एक और मौका दे दिया, लेकिन पार्टी में कुछ नेता ऐसे भी हैं, जो यह मानते हैं कि रामविलास पासवान कोई नई धारा नहीं बहा रहे हैं. पासवान चाहते हैं कि चिराग जल्द से जल्द उनकी विरासत को संभालें. उनका स्वास्थय ठीक नहीं रहता है और बिहार की चुनौतीपूर्ण राजनीति में सफल होने के लिए हर जगह जाकर जनता की बात सुनना उनके लिए इस उम्र में संभव नहीं है. इसलिए वह चाहते हैं कि चिराग अपनी जिम्मेदारियों को जल्द से जल्द संभाल लें.

लोजपा में नेताओं का बड़ा तबका चिराग की लॉन्चिंग के बेहद खिलाफ है. इन नेताओं का कहना है कि चिराग राजनीति में आए, इससे किसी को परहेज नहीं है, लेकिन जिस तरह चिराग को पार्टी में घुसाया जा रहा है, वह बर्दाश्त से बाहर की बात है. रामविलास पासवान के सामने भले ही नेता व कार्यकर्ता चिराग जिंदाबाद का नारा लगा देते हैं, लेकिन दिल से उन्हें अभी कोई पसंद नहीं कर रहा है. रामविलास पासवान चिराग के मामले में कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं.

लालू प्रसाद के लिए भी तेजस्वी व तेज प्रताप को आगे करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है. अपनी रैली के समय लालू यादव ने अपने बेटों को आगे किया था, लेकिन इस समय पार्टी के बड़े नेताओं का इतना दबाव बना कि गांधी मैदान से लालू के बेटों का भाषण अंतिम समय में टाल दिया गया. जगदानंद सिंह तो इतने गुस्से में थे कि वह मंच पर भी नहीं आए. यह लालू प्रसाद के लिए एक इशारा था, पर लालू कहां मानने वाले हैं.

कुछ इसी तरह की कहानी लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी यादव व तेज प्रताप की भी है. कोर्ट-कचहरी से घिरे लालू प्रसाद के लिए भी तेजस्वी व तेज प्रताप को आगे करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है. राबड़ी देवी पहले भी बिना मन से ही राजनीति में आईं थीं. अपनी रैली के समय लालू यादव ने अपने बेटों को आगे किया था, लेकिन इस समय पार्टी के बड़े नेताओं का इतना दबाव बना कि गांधी मैदान से लालू के बेटों का भाषण अंतिम समय में टाल दिया गया. जगदानंद सिंह तो इतने गुस्से में थे कि वह मंच पर भी नहीं आए. यह लालू प्रसाद के लिए एक इशारा था, पर लालू कहां मानने वाले हैं. राजद की राजनीति को समझने वाले नेता बताते हैं कि लालू प्रसाद अपने परिवार के बाहर किसी नेता को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है. ऐसे में अपने बेटों पर दांव लगाना उनकी मजबूरी है. तेजस्वी पूरे बिहार का दौरा कर भी रहे हैं, लेकिन यहां भी बात वहीं आकर अटक जाती है, जहां चिराग मामले में लटक रही है. पार्टी के कई बड़े नेता तेजस्वी को पचा नहीं पा रहे हैं. उनका विरोध करने वाले नेता कहते हैं कि युवा वोटरों को आकर्षित करने के लिए अगर युवा चेहरा चाहिए तो पार्टी में कई तपे-तपाए युवा चेहरे पड़े हैं, उनको क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा है. ऐसे युवाओं से लालू प्रसाद को क्यों परहेज है. तेजस्वी यादव में ऐसी क्या बात है, जो इन युवा चेहरों में नहीं है. यह सारा कुछ बस पुत्र मोह का मामला है. ऐसे ही चलता रहा तो महाभारत तय है और महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है.

राजद प्रवक्ता रणधीर यादव तेजस्वी व तेजप्रताप की सक्रियता को गलत नहीं मानते. वह कहते हैं कि सोनिया गांधी भी राहुल गांधी को और मुलायम सिंह यादव भी अखिलेश यादव को आगे कर रहे हैं. दोनों सफल भी हुए हैं तो फिर तेजस्वी व तेज प्रताप को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है. इन दोनों को केवल इस आधार पर पीछे नहीं किया जा सकता कि वे लालू प्रसाद के पुत्र हैं. रणधीर यादव कहते हैं कि तेजस्वी व तेजप्रताप में अपार संभावनाएं हैं. जानकार बताते हैं कि चारा घोटाला में फैसला आने के बाद राजद की राजनीति में बड़ा उलट फेर हो सकता है. तेजस्वी को चाहने वाले और न चाहने वाले बस इसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं. चूंकि राजद की राजनीति का बहुत कुछ कोर्ट के इसी फैसले से तय होना है. लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी व तेजप्रताप के आगे तो उम्र का बंधन है, पर चिराग पासवान हाजीपुर या फिर जमुई से चुनावी अखाड़े में उतर सकते हैं. रामविलास पासवान हाजीपुर के हरेक कार्यक्रम में चिराग को लेकर जा रहे हैं. अगर समर्थकों ने रामविलास को ही वहां से खड़ा होने के लिए बाध्य किया तो चिराग जमुई जा सकते हैं. उम्मीद है कि चिराग हाजीपुर को ही अपना रणक्षेत्र बनाएंगे. चुनाव का रिजल्ट जो हो, पर फिलहाल इन राजकुमारों की वजह से राजद व लोजपा दोनों ही दलों में बहुत सारे अगर-मगर जिंदा हो गए हैं और इन अगर-मगर का जवाब तो बिहार की जनता को वक्त के साथ ही मिलेगा.

वंशवाद की बीमारी पुरानी है

भारत में वंशवाद की बीमारी आज कोई नई बात नहीं है. इसकी नींव तभी पड़ गई थी जब आजादी के बाद भारत के गिने-चुने निर्माताओं में शुमार पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने अपनी बिटिया इंदिरा गांधी के लिए राजनीतिक गलियारे में सुरक्षित जगह बनाई थी. यह तब था जब आजादी के बाद यह आशा जगी थी कि देश को सामंतवाद और वंशवाद से छुटकारा मिलेगा और इन प्रवृत्तियों पर लोकतंत्र भारी पड़ेगा. लेकिन ऐसा नहीं हो सका. इंदिरा के बाद कांग्रेस पार्टी में यह सिलसिला तबसे चला आ रहा है. आज स्थिति यह है कि कांग्रेस का मतलब ही नेहरू-गांधी परिवार है. वंशवाद की जो परंपरा कांग्रेस में पड़ी, समय के साथ इसे क्षेत्रीय दलों ने भी अमल में लाना शुरू कर दिया. अब हालत यह है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय राजनीति में वंशवाद हावी है. यूपी में मुलायम सिंह का पूरा परिवार सरकार में शामिल है. नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह अब्दुल्ला परिवार के हाथ में है. पंजाब में भारतीय राजनीति का पहला अध्याय ऐसा लिखा गया कि जब प्रकाश बादल मुख्यमंत्री बने और अपने बेटे को सुखबीर बादल को उपमुख्यमंत्री बनाया. हरियाणा की राजनीति में चौटाला खानदान का दबदबा है. महाराष्ट्र में बालठाकरे और शरद यादव ने वंशवाद को खाद-पानी दिया तो कर्नाटक में देवगौड़ा और तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार डीएमके पर काबिज है. भारतीय राजनीति निकट भविष्य में वंशवाद की बीमारी से मुक्त होगी, इसके कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com चौथी दुनिया

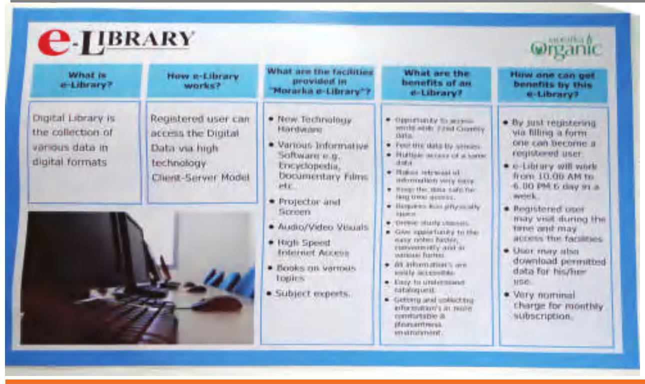

सूचना तकनीक किसी क्षेत्र का प्रभावशाली तरीके से कायाकल्प कर सकती है. शेखावटी में चल रहा ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम इसकी मिसाल है. यहां सूचना तकनीक की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आई है, उसकी कल्पना दो साल पहले किसी ने नहीं की थी. सार दर साल ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का दायरा बढ़ रहा है. इसके साथ ही सफल विद्यार्थियों की संख्या में भी इज़ाफा हो रहा है.

मोरारका फाउंडेशन ने वर्ष 2011 में राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के सीकर जिले के बेरी गांव से ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत की. बेरी का करियर सीनियर सेकेंड्री स्कूल इस प्रयोग के लिए पहली प्रयोगशाला बना. यहां सबसे पहले उन विद्यार्थियों का नामांकन किया गया, जो आगे चलकर इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते थे.

नवीन चौहान

सूचना तकनीक की देन

हाईटेक होते गांव

राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में सरकार के प्रयासों से इतर मोरारका फाउंडेशन ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के जीवन में नये आयाम गढ़े हैं. अपने कदम आगे बढ़ाते हुए मोरारका फाउंडेशन ने शिक्षा में सुधार लाने और महिला सशक्तिकरण के लिए सूचना तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसके उचित परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं.

भारत गांवों का देश है. गांधी जी ने कहा था कि जब तक गांव नहीं बदलेंगे, तब तक देश नहीं बदलेगा. पिछले एक दशक में भारत ने सूचना क्रांति के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है. बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों की वैश्विक पहचान सूचना क्रांति की वजह से ही है. सरकार लोगों को सूचना तकनीकी का फायदा देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, जिससे सरकारी सुविधाओं का फायदा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी मिल सके. सरकार ने अब तक जो भी कदम लोगों को सूचना क्रांति से जोड़ने के लिए उठाए हैं, उससे गावों में रहने वाले लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, न ही उनके रहन-सहन के स्तर में कोई सुधार हुआ. राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में सरकार के प्रयासों से इतर मोरारका फाउंडेशन ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए दो साल पहले प्रायोगिक तौर पर कुछ कार्यक्रम शुरू किए थे, जिसकी प्रारंभिक सफलता को देखते हुए उसका विस्तार भी किया गया था. इस क्रम में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए मोरारका फाउंडेशन ने शिक्षा में सुधार लाने और महिला सशक्तिकरण के लिए सूचना तकनीकी का इस्तेमाल करना शुरू किया. शेखावटी में इन दोनों क्षेत्रों में सुधार की व्यापक संभावनाएं थीं. इन क्षेत्रों में काम कर ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं और महिलाओं के जीवन में व्यापक बदलाव लाया जा सकता था. मोरारका फाउंडेशन ने शेखावटी के ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं का परिचय ऑनलाइन एजुकेशन से करवाया और उन्हें शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के बराबर ला खड़ा किया. फाउंडेशन के प्रयासों के सार्थक परिणाम निकलकर अब सामने आने लगे हैं. यहां के छात्र-छात्राएं नीत नई सफलता की कहानियां लिख रहे हैं. इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में परदे में रहने वाली राजपूत महिलाएं फाउंडेशन द्वारा चलाए गए वीरबाला कार्यक्रम की मदद से गांव-घर में रहते हुए, अपनी परंपराओं को निभाते हुए खुद को कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से सशक्त बना रही हैं. इसी तरह समाज के लोगों को दुनिया के विभिन्न रंगों से परिचित कराने के साथ ही भारत और इंडिया के अंतर को पाटने के लिए मोरारका फाउंडेशन ने ई-लाइब्रेरी की शुरुआत भी की है.

ऑनलाइन एजुकेशन कार्यक्रम

अच्छी शिक्षा किसी क्षेत्र की बपौती नहीं है. संसाधनों की कमी अथवा उसकी उपलब्धता ही शिक्षा के स्तर को अच्छा या बुरा बनाती है. शिक्षा की नई तकनीकी, नए पाठ्यक्रम, नई सोच और विश्व स्तर पर तेजी से हो रहे संचार क्रांति में बदलाव, शिक्षा का आधुनिक माहौल, आधुनिक मशीनें और न जाने कितने ही अवसर प्रदान करने वाले संसाधन ग्रामीण भारत की पहुंच से कोसों दूर हैं. ऐसे में ग्राणीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले अधिकांश मेधावी विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में शहरी विद्यार्थियों से पीछे रह जाते हैं. ग्रामीण क्षेत्र के चुनिंदा विद्यार्थियों को ही शहरों में जाकर आधुनिक शिक्षा के संसाधनों से रू-ब-रू होने का मौका मिलता है. इसके लिए भी उन्हें मोटी फीस चुकानी होती है. बेसिक शिक्षा में और कॉन्सेप्ट क्लियर न होने के वजह से उन्हें वहां भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है. इस तरह हर साल ग्रामीण क्षेत्र के हजारों युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाता है. महानगरों में बड़ी-बड़ी कोचिंग क्लास में पढ़ाने वाले शिक्षकों को गांवों तक लाना आसान नहीं है, लेकिन तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से मोरारका फाउंडेशन ने यह काम कर दिखाया है.

मोरारका फाउंडेशन ने वर्ष 2011 में राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के सीकर जिले के बेरी गांव से ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत की. बेरी का करियर सीनियर सेकेंड्री स्कूल इस प्रयोग के लिए पहली प्रयोगशाला बनाया. यहां सबसे पहले उन विद्यार्थियों का नामांकन किया गया, जो आगे चलकर इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते थे. इसके साथ ही दसवीं और बारहवीं की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल किया गया. उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित विषयों के वीडियो और ऑडियो ट्यूटोरियल, स्टडी मैटेरियल और पूर्व के परीक्षा पत्रों के सॉल्यूशन उपलब्ध करवाए. पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से अलग इस रोचक तकनीकी ने विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित किया. तीन साल बाद आज इस कार्यक्रम में 9000 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ चुके हैं. इस साल इस कार्यक्रम से जुड़े 241 बच्चों ने 85 से 100 प्रतिशत के बीच अंक हासिल किए. 603 विद्यार्थियों ने 80 से 85 प्रतिशत के बीच अंक प्राप्त किए हैं. इस कार्यक्रम की सफलता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है. वर्ष 2013 में हुई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) प्रवेश परीक्षा की मुख्य परीक्षा के लिए 103 छात्र-छात्राएं चयनित हुए, इसमें से 15 आईआईटी में प्रवेश पाने में सफल हुए, जिसमें 5 छात्राएं भी शामिल हैं. इसी तरह एनईईटी की परीक्षा में 7 विद्यार्थियों ने चयनित होकर शेखावटी के विकास में एक का नया अध्याय शुरू कर दिया. मोरारका फाउंडेशन के निदेशक डॉ. मुकेश गुप्ता ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि हम चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों के बच्चों को भी अवसर मिले, ताकि वह प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा कर सकें. बच्चों को ऐसा न लगे कि वे गांवों में रहने के वजह से पिछड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि बच्चों ने इस गैर पारंपरिक तरीके को बड़े उत्साह से अपनाया. आज इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय भी उन्हीं को जाता है. मोरारका फाउंडेशन के चेयरमैन कमल मोरारका ने कार्यक्रम की सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि गावों के बच्चों को सफल होते देखना सुखद है. इस तरह के कार्यक्रमों से देश के हर बच्चे को समान शिक्षा और समान अवसर मिलेंगे. तकनीक बड़े से बड़े अंतर को पाट देती है.

सूचना तकनीक किसी क्षेत्र का प्रभावशाली तरीके से कायाकल्प कर सकती है. शेखावटी में चल रहा ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम इसकी मिसाल है. यहां सूचना तकनीकी की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आई है, इसकी कल्पना दो साल पहले किसी ने नहीं की थी. सार दर साल ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का दायरा बढ़ रहा है. इसके साथ ही सफल विद्यार्थियों की संख्या में भी इज़ाफा हो रहा है. बेरी के करियर स्कूल से शुरू हुआ यह कार्यक्रम आज 40 स्कूलों तक पहुंच चुका है. साथ ही यह सफलता के नीत नये मुकाम तय कर रहा है. आज शेखावटी क्षेत्र का हर बच्चा अपने भविष्य को ज्यादा सुरक्षित और सशक्त समझने लगा है. गांवों में स्थित इन स्कूलों में भले ही स्मार्ट क्लासेस न हो, लेकिन उनके पास आधुनिक शिक्षण का स्मार्ट तरीका है और यह उनके सपनों को पंख देने के लिए काफी है.

वीरबाला कार्यक्रम

दुनिया भर में राजस्थान अपनी कला संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां की संस्कृति में शामिल परदा प्रथा महिलाओं के

विकास में बाधक रही है. पढ़ाई-लिखाई पूरी करने के बाद भी यहां की महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं होती है. ग्रामीण महिलाओं की स्थिति सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मोरारका फाउंडेशन ने वर्ष 2009 में ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक कंप्यूटर शिक्षा से जोड़कर बीरबाला प्रोत्साहन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था, जिसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा दी गई. इसके साथ ही महिलाओं को किसान कॉल सेंटर की भी ट्रेनिंग दी गई. इसकी वजह से आज ग्रामीण महिलाएं अपने घर पर रहकर डाटा एंट्री और कॉल सेंटर का कार्य कर आत्मनिर्भर हो रही हैं. वर्तमान में झुंझुनू, सीकर और झालावाड़ जिले के 2042 किसान इस कॉल सेंटर से जुड़े हुए हैं, जिन्हें वीरबालाएं स्थानीय भाषा में जैविक खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां सुचारू रूप से प्रदान कर रही हैं.

वीरबाला कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को जैविक खेती कर रहे किसानों को सलाह देने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की ट्रेनिंग दी जाती है. कॉल सेंटर द्वारा किसानों के खेत पर बनाए जाने वाले विभिन्न जैविक आदान, दवाइयां, फसलों में आने वाली समस्याओं की जानकारी, समस्याओं का निदान, मृदा सुधार, खेत-फसल-क्षेत्रफल-बीज के बारे में जानकारी दी जाती है और कॉल का पूरा रिकॉर्ड बीरबालाओं द्वारा रखा जाता है. इसके साथ ही खेत में पशुपालन और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी जाती है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य कर रही वीरबालाओं का कहना है कि हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमें कभी कंप्यूटर सीखने का मौका मिलेगा. वीरबालाओं ने अपने प्रयास से यह साबित कर दिया है कि घूंघट किसी के विकास में बाधा नहीं बन सकती. शेखावटी की इन महिलाओं को अपनी परंपरा पर नाज है, लेकिन इनकी सफलता भारत की हर एक नारी को संदेश देती है.

ई-लाइब्रेरी

इस साल नवलगढ़ के नवनिर्मित नगरपालिका भवन में ई-लाइब्रेरी की स्थापना की गई है. इस लाइब्रेरी का उपयोग ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के अलावा आम नागरिक भी कर सकते हैं. इस लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों की इलेक्ट्रॉनिक किताबों, विभिन्न विषयों से जुड़ी डॉक्यूमेंट्रियों का भंडार है. यहां आम जनों के साथ-साथ विद्यार्थी भी इस भंडार का उचित उपयोग कर रहे हैं. यहां हर उम्र और वर्ग के लोगों की रुचि के अनुरूप किताबें और वीडियो उपलब्ध हैं. मिसाल के तौर पर बुजुर्गों के लिए योगा और अध्यात्म से जुड़ी किताबें और वीडियो, महिलाओं के लिए खाना बनाने की रेसेपी, बच्चों के लिए कहानियां, वैदिक गणित आदि से संबंधित पुस्तकें यहां उपलब्ध हैं. इस लाइब्रेरी की मदद से बच्चों और आम जनों ने कंप्यूटर ऑपरेट करना भी सीखा है. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

जुबिन के कार्यक्रम को लेकर किसी ने फतवा तो नहीं जारी किया, लेकिन कश्मीर के मुफ्ती–ए–आजम बशीरुद्दीन ने इस कार्यक्रम का विरोध करते हुए संगीत को इस्लाम के मुताबिक नाजायज बताया. यह वही मुफ्ती हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले फतवा जारी कर कश्मीर में लड़कियों के पहले और एकमात्र रॉकबैन्ड प्रगाश को बंद करवा दिया था. इस बैन्ड को हाईस्कूल की तीन लड़कियां चलाती थीं.

जम्मू–कश्मीर

संगीनों के साये में संगीत की महफिलें

कृष्णकांत

सदियों से सूफी संगीत की अनुगूंज से भरी कश्मीर घाटी को किसकी नजर लग गई है कि आज वहां संगीत की महफिलें संगीनों के साये में सजती हैं? संगीत, धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीरी वादियों की पहचान में रचा–बसा है, लेकिन आज उन्हीं वादियों में संगीत के सुरों पर नेजे तने हैं. उसकी पहचान को ही वहां वर्जनीय कहा जा रहा है. जो कश्मीर की वादियां अपने सौंदर्य के साथ–साथ संगीत के सुरों से ओतप्रोत हैं, आज वहां पर जब तब संगीत के नाम पर फतवे जारी होना न सिर्फ हैरान करता है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करता है कि कट्टरता कैसे सदियों पुरानी लोकरंजक परंपराओं मिटाने पर तुल जाती है. सवाल यह है कि वास्तव में संगीत गैर–इस्लामिक है या अपने एजेंडे को अमल लाने के लिए संगीत एक बहाना है?

हाल ही में इस तरह के दो बड़े विवाद सामने आए, जब संगीत को न सिर्फ नाजायज कहा गया, बल्कि कई कट्टरपंथी संगठनों ने उसका विरोध किया. सात सितंबर को डल झील के किनारे विश्वप्रसिद्ध संगीतकार जुबिन मेहता का कार्यक्रम रखा गया था. कार्यक्रम को नाम दिया गया था एहसास–ए–कश्मीर. अलगाववादी संगठनों ने इसके विरोध में समानांतर एक अन्य कार्यक्रम रखा हकीकत–ए–कश्मीर. कार्यक्रम की घोषणा के बाद से ही अलगाववादियों ने इसके विरोध की घोषणा करते हुए तर्क पेश किया कि एक तो संगीत इस्लाम के लिहाज से नाजायज है. दूसरे, यदि कश्मीर में जुबिन मेहता का कार्यक्रम होता है तो दुनिया में कश्मीर को लेकर भ्रम फैलेगा. पश्चिमी देशों में यह संदेश जाएगा कि कश्मीर में शांति है और वह भारत का हिस्सा है. हम ऐसा नहीं होने देंगे. हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी ने सात सिंतबर को कश्मीर बंद और प्रदर्शनों का आह्वान किया. कार्यक्रम का विरोध करने वाले अलगावदियों और कई मानवाधिकार संगठनों ने साझा बयान जारी कर कहा कि इस कार्यक्रम को कश्मीर में इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह संगीत संध्या कश्मीर में यहूदी संस्कृति फैलाने की साजिश के तहत हो रही है. हुर्रियत नेता गिलानी और उमर फारूक ने जर्मन दूतावास से यह कार्यक्रम रद करने की अपील भी की, क्योंकि आयोजन दूतावास की तरफ से ही था. हालांकि, जर्मन दूतावास ने अपील को कोई तवज्जो नहीं दी. दूसरी तरफ लश्कर–ए–तैयबा के हिट स्क्वायड कहलाने वाले तीन संगठनों अल–नसरीन, शौहदा ब्रिगेड और फरजनदान–ए–मिल्लत की ओर से धमकी दी गई कि यदि जुबिन मेहता का कार्यक्रम होता है तो आयोजनस्थल पर धमाके किए जाएंगे. इसके अलावा इन संगठनों ने कहा कि यदि कार्यक्रम नहीं रद किया जाता तो भविष्य में कश्मीर घूमने आने वाले पश्चिमी देशों के पर्यटकों को भी निशाना बनाएंगे.

इन धमकियों और विरोध के चलते राज्य सरकार ने कार्यक्रम सुचारु ढंग से संपन्न कराने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की. बावजूद इसके, कार्यक्रम वाले दिन कश्मीर में दो जगह आतंकी हमले हुए. गनीमत यह रही कि कड़ी चौकसी के चलते श्रीनगर में आतंकी हमला नहीं कर सके.

जुबिन के कार्यक्रम को लेकर किसी ने फतवा तो नहीं जारी किया, लेकिन कश्मीर के मुफ्ती–ए–आजम बशीरुद्दीन ने इस कार्यक्रम का विरोध करते हुए संगीत को इस्लाम के मुताबिक नाजायज बताया. यह वही मुफ्ती हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले फतवा जारी कर कश्मीर में लड़कियों के पहले और एकमात्र रॉकबैन्ड प्रगाश को बंद करवा दिया था. इस बैन्ड को हाईस्कूल की तीन लड़कियां चलाती थीं. प्रदेश स्तर की एक संगीत प्रतियोगिता में प्रस्तुति देने के बाद बैन्ड चर्चा में आया और वे लड़कियां कश्मीरियों के बीच लोकप्रिय होने लगीं. इसी बीच मुफ्ती बशीरुद्दीन ने संगीत को नाजायज बताते हुए फतवा जारी किया. फतवे के बाद तीनों लड़कियों के फेसबुक पेज पर लगातार धमकियां दी गईं. शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई तो की, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत तमाम लोगों ने लड़कियों का समर्थन भी किया, लेकिन धमकियों से डरीं बच्चियों ने न सिर्फ बैन्ड बंद कर दिया, बल्कि कश्मीर छोड़ दिया. इस्लाम के लिहाज से संगीत के हराम अथवा नाजायज होने संबंधी फतवे को लेकर मुफ्ती बशीरुद्दीन का विरोधाभास तब सामने आ गया जब जुलाई के दूसरे सप्ताह में इंटरनेट पर एक वीडियो जारी हुआ, जिसमें बशीरुद्दीन डल झील में एक शिकारे में आयोजित गजल संध्या का मजा ले रहे थे. इस वीडियो में कश्मीर के स्थानीय कलाकार अमीर खुसरो का प्रसिद्ध कलाम छाप तिलक सब छीनी... और मेहंदी हसन की मशहूर गजल रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ... गाते देखे गए. मुफ्ती ने भी गजलों का जमकर लुत्फ उठाया. वीडियो जारी होने के बाद बशीरुद्दीन ने अजीबो–गरीब तर्क दिया कि वह कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं था. वहां पर जो भी कलाम गाए गए, वे खुदा की शान में गाए गए. इसके बाद भी मुफ्ती ने संगीत को गैर–इस्लामिक बताते हुए कहा कि मैं लड़कियों के गाने–बजाने के खिलाफ हूं. वीडियो जारी होने को मुफ्ती बशीरुद्दीन ने अपने खिलाफ शरारती तत्वों की साजिश बताया और इंटरनेट को भी गैर–इस्लामिक गतिविधियों का अड्डा कह डाला.

गौरतलब है कि मुफ्ती–ए–आजम बशीरुद्दीन को अलगाववादियों समेत कई संगठन स्वयंभू मुफ्ती मानते हैं. प्रगाश के बंद होने के बाद उन्हें मुफ्ती पद से हटाने की भी मांग उठी. कश्मीर के प्रमुख मानवाधिकार संगठन कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के प्रमुख एडवोकेट परवेज इमरोज ने कहा कि मुफ्ती बशीरुद्दीन को किसने मुफ्ती–ए–आजम बनाया है. वे समानांतर सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं. कश्मीर के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वे सरकार के कहने पर उल्टे सीधे फतवे जारी करते हैं. लड़कियों के समर्थन में एक ऑनलाइन याचिका भी दायर की गई, जिसमें पांच हजार लोगों ने बैन्ड का समर्थन किया. हालांकि, ऐसे विद्वानों की संख्या भी बहुतायत है जो संगीत को इस्लाम या किसी अन्य धर्म के विरुद्ध नहीं मानते. इतिहास में संगीत का इस्लाम से गहरा ताल्लुक मिलता है. सवाल उठता है कि क्या वास्तव में संगीत या अन्य कलाएं किसी धर्म में वर्ज्य हैं या किसी एजेंडे के तहत इनका विरोध किया जाता है? इस विषय पर हमने इस्लामिक विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान की राय लेनी चाही तो उन्होंने कहा यह कोई मसला ही नहीं है जिसपर बात की जाए. मैं गैर–मुद्दों पर राय नहीं देता. मैं राय उसी मुद्दे पर देता हूं, जो वास्तविक हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

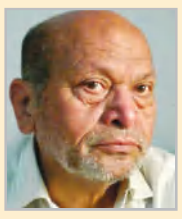

"जहां तक मेरा मानना है संगीत को जो लोग गैर–इस्लामिक कहते हैं, यह उनका अपना मत है. इस्लाम का संगीत से कोई ताल्लुक नहीं है. अरबी समाज बहुत पहले से कविता और कला का समाज रहा है और कविता का गायन से बहुत गहरा संबंध है. इसलिए यह असंभव है कि इस्लाम संगीत का विरोध करता हो. आप इस्लाम का इतिहास पढ़ें तो कई जगह संगीत के प्रसंग मिलते हैं. धर्म के आधार पर किसी कला का विरोध करना गलत है. धर्म में कलाओं का विरोध नहीं है. यह उन लोगों की अपनी राय है."

–असगर वजाहत, साहित्यकार

सच्चर रिपोर्ट

राजनीतिक हाशिये पर मुसलमान

भारत में मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण उनका राजनीतिक सशक्तिकरण न होना है. अगर वे राजनीतिक रूप से सशक्त होंगे तो उनका प्रतिनिधित्व पंचायतों से लेकर विधायिकाओं तक होगा और फिर उनकी शैक्षणिक, आर्थिक व अन्य समस्याएं हल होंगी. आइए देखते हैं कि केंद्र सरकार की वेबसाइट पर सच्चर रिपोर्ट की 76 अनुशंसाओं में पांचवें और छठवें बिंदु में क्या कहा गया है और सरकार द्वारा इस संदर्भ में किए जाने वाले दावों की सच्चाई क्या है?

डॉ. क़मर तबरेज़

भारत के संविधान ने देश के हर नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने का समान अधिकार दिया है, लेकिन पिछले 66 वर्षों से भारत की सत्ता पर वही लोग काबिज हैं, जिनका संबंध या तो उच्च जातियों से है या फिर वह अमीर और प्रभावशाली हैं. विडंबना यह कि पिछले कुछ दशकों से सत्ता में दाग़ी और भ्रष्टाचारों में लिप्त लोगों की हिस्सेदारी बढ़ने लगी है. विधायिका में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों, विशेषकर मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व न तो पहले मिला था और न ही अब. विधायिका में तमाम वर्गों का प्रतिनिधित्व इसलिए आवश्यक है ताकि लोकतंत्र में उनका विश्वास बहाल हो कि जिस वर्ग से इनका संबंध है उसके विकास से संबंधित कार्यक्रम या योजनाएं बनें तो उसकी अनदेखी न की जाए. दुर्भाग्य से मुसलमानों को उनका लोकतांत्रिक अधिकार पूरी तरह अब भी नहीं मिल सका है. शायद इसी को ध्यान में रखते हुए सच्चर कमेटी ने विधायिका के हर स्तर पर मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने की वकालत की थी.

सच्चर कमेटी तमाम जाचों व अध्ययन के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि देश के विकासीय ढांचे में मुसलमानों के पिछड़ जाने का कारण सरकारी ढांचे में उनकी कम हिस्सेदारी है. भारतीय लोकतंत्र में देश की विभिन्न जातियों और समुदायों को यह मौका मिला है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से हर स्तर पर भागीदारी कर सकें और पंचायतों से लेकर विधानसभा और संसद में निर्वाचित होकर आएं और सरकारी ढाचों में शामिल हों. इसी प्रकार संसदीय लोकतंत्र के समानांतर देश में ऐसी बहुत सी अर्द्धसरकारी संस्थाएं भी हैं जो चुनावी लोकतंत्र के सिद्धांतों पर ही चलाई जा रही हैं. उदाहरणस्वरूप किसी क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए वहां कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, जो क्षेत्र के लोगों में से ही अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करती हैं. लेकिन दुख की सच्चर कमेटी के अनुसार पिछले 60 वर्षों के दौरान इन सरकारी संस्थाओं में सांस्कृतिक, भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों को निर्वाचित होने का समान अवसर नहीं मिला है. राजनीति में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व इतना कम है कि वे अपने कल्याण के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकते. इसलिए राजनीति गलियारों में उनकी बातों को महत्व के साथ नहीं सुना जाता. सरकारी ढाचों में जब मुसलमानों की स्थिति इतनी दयनीय है तो फिर उनकी समस्याओं को को लेकर क़ानून कैसे बनेंगे और अगर बने भी तो वे कितने कारगर होंगे. आज सरकार की ओर से मुसलमानों को आत्मनिर्भर बनाने के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं. ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर पर कोई ऐसा तरीक़ा अपनाया जाए कि सरकारी संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को अवसर मिले. आइए देखते हैं कि सच्चर कमेटी की अनुशंसाओं और सरकार के दावों की रोशनी में वर्तमान स्थिति क्या है–

अनुशंसा–5

सच्चर कमेटी ने अपनी पांचवी अनुशंसा में कहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में जो पहल की है, इसी तर्ज़ पर राज्य स्तर पर उचित क़ानून बनाकर उन्हें लागू किया जाए, ताकि स्थायी सरकारी ढाचों में अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके. राज्य सरकारों को चाहिए कि इस प्रकार के क़ानूनों को लागू करते समय वह भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान रखें.

यूपीए सरकार का दावा: राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वह आंध्र प्रदेश की तर्ज़ पर ही अपने यहां अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाएं.

चौथी दुनिया का रुख़: क्या केंद्र में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार की नज़र में सच्चर कमेटी की इस पांचवी अनुशंसा पर राज्य सरकारों को सुझाव दे देने को ही हम इसका लागू होना मान लें? क्या कांग्रेस यह बता सकती है कि जिन राज्यों में उसकी सरकारें हैं, वहां पर उसने भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए क्या क़दम उठाए हैं? मूल तथ्यों का पता लगाने के बाद तो हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि कांग्रेस ने इस सिलसिले में कुछ नहीं किया. इस तरह देखा जाए तो यूपीए सरकार ने सच्चर कमेटी की पांचवी अनुशंसा को भी लागू नहीं किया है, जबकि प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि सच्चर कमेटी की तीन को छोड़कर शेष सभी अनुशंसाओं को लागू किया जा चुका है.

1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े परिवर्तन किए गए और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश की गई. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हमारा देश तभी विकास करेगा जब हम अपने गावों को अधिक से अधिक मज़बूत बनाएंगे. आज़ादी के बाद के दिनों में हमने देखा कि कैसे पंचायतों को केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन कर दिया गया था. लेकिन संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायतों को नई जिंदगी दी. इन संशोधनों के पीछे भारतीय क़ानून निर्माताओं का यह विश्वास था कि चूंकि स्थायी स्तर पर चुनावों के द्वारा गठित होने वाली संस्थाएं वहां की समस्याओं को न केवल अच्छी तरह जानती हैं, बल्कि इन समस्याओं का उचित हल भी तलाश कर सकती हैं, इसलिए उन्हें स्थानीय समस्याओं को हल करने का पूर्ण अधिकार दे दिया जाए. संविधान के ये दोनों संशोधन अब तक काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पंचायतों में स्थानीय आबादी में पिछड़े वर्गों का किस हद तक प्रतिनिधित्व हो पाया है. सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि पंचायतों में भी उन्हीं जातियों या समुदायों का दबदबा बना रहता है, जिनकी आबादी वहां पर ज्यादा है, या फिर जो वर्ग शैक्षणिक या आर्थिक दृष्टि से अधिक ताक़तवर है. इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत में लगभग हर जगह पर मुसलमान पिछड़े हुए दिखाई देते हैं और यही कारण है कि स्थायी सरकारी संस्थाओं में भी उनका प्रतिनिधित्व न के बराबर है. इसी के मद्देनज़र रखते हुए संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा मंडल (गांव स्तर की ईकाई) और जिला परिषद में और 74वें संशोधन के द्वारा कार्पोरेशन और नगरपालिका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (बैंकों) और मार्केटिंग इंस्टीटयूशन में अलपसंख्यकों को नामित करने का आयोजन किया गया है. इस दिशा में आंध्र प्रदेश सरकार की पहल की तर्ज पर प्रशंसनीय पहल के अलावा राज्य सरकारों को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करने की आवश्यकता है. आंध्र प्रदेश पंचायत के नये क़ानून के अनुसार मंडल और जिला परिषद के लिए चुनावी प्रक्रिया के पूरे होने के बाद मंडल में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखने वाले एक ऐसे व्यक्ति को नामित किया जाए, जो इस मंडल या गांव का रजिस्टर्ड वोटर हो और जिसकी उम्र 21 साल से कम न हो. इसी प्रकार जिला परिषद में भी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले दो लोगों को नामज़द किया जाए.

आंध्र प्रदेश पंचायत के इस नये क़ानून में यह स्पष्ट किया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों को नामित करने की प्रक्रिया उस समय भी होनी चाहिए, जब चुनावों के बाद नियमित प्रक्रिया में इस समुदाय के लोग निर्वाचित होकर आते हैं. हालांकि, इसी के साथ यह बात भी कही गई है कि फैसले लेने का अधिकार उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा, जो इसमें निर्वाचित होकर आए हैं और नामित होकर आने वाले लोगों को निर्णय लेने की इस प्रक्रिया में वोटिंग का अधिकार प्राप्त नहीं होगा. आंध्र प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (अमेडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2005 में भी कहा गया है कि इस प्रकार के हर बैंक में 8–9 निर्वाचित सदस्य पहले से होते हैं, अब इन बैंकों में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति को रजिस्ट्रार के द्वारा नामित करके वहां अवश्य भेजा जाए, जिसे मीटिंगों में शामिल होने का अधिकार तो प्राप्त होगा, लेकिन वोट करने का नहीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

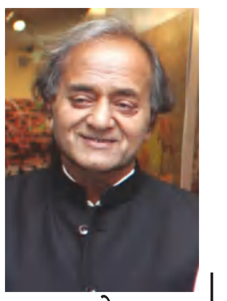

कमल मोरारका

राजनीति अब विशुद्ध राजनीति न होकर आर्थिक राजनीति में तब्दील हो गई है. यह स्थिति देश के लिए दुखद है. अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर अंतर्कलह मची हुई है और यह उसकी छवि को और ख़राब करेगी. आरएसएस ने भी जो भूमिका निभाई, उसकी भी उम्मीद नहीं थी.

मौजूदा स्थिति देश के लिए दुखद है

भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नरेंद्र मोदी का समर्थन करने और विरोध करने वाली कुछ ताकतें हैं, जिन पर पार्टी का कोई नियंत्रण नहीं है. एक दौर था, जब भारतीय जनता पार्टी और उसका पूर्ववर्ती संस्करण जनसंघ अपने अनुशासन के लिए जाना जाता था. समूचे काडर को इस बात के लिए जाना जाता था कि ये बिना किसी अनबन के पार्टी लाइन पर ही चलते रहे हैं. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी एक सम्मानित संगठन है, जहां कभी एक ही आवाज से सारी समस्याएं सुलझ जाती थीं, लेकिन इन दोनों के ही भीतर यह अनुशासन खो-सा गया है. अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अंतर्कलह मची हुई है और यह उसकी छवि को और खराब करेगी. आरएसएस ने भी जो भूमिका निभाई, उसकी भी उम्मीद नहीं थी. मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के भीतर निःसंदेह लालकृष्ण आडवाणी सबसे कद्दावर नेता हैं और पूरा देश उन्हें सम्मान भी देता है, लेकिन एक बात, जिस पर देश की जनता गौर नहीं कर रही है, वह यह कि धनबल ने बाकी सब चीजों पर कब्जा कर लिया है.

नरेंद्र मोदी के पास धनबल है. करिश्माई व्यक्तित्व का होना अपनी जगह है, लेकिन बिना धनबल के ताकतवर बने रहना संभव नहीं है. नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि को उभारने के लिए खुद का एक सिस्टम बनाया. उन्होंने ऐसे युवाओं को अपने पक्ष में किया, जो हमेशा इंटरनेट पर सक्रिय रहते हैं. उनके पास बिहार के सुशील मोदी जैसे नेता हैं, जिनका पहले नीतीश कुमार ने इस्तेमाल किया और अब उन्हें धनबल राजनीति के ब्रांड बन चुके नरेंद्र मोदी द्वारा सहारा दिया जा रहा है. नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को यह सुनिश्चित किया है कि चुनाव में जितना भी पैसा लगेगा, वह वहन करेंगे. और यह सब अब इतना बढ़ चुका है कि निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्कृति के विपरीत है. वास्तव में यह दिखाता है कि 1991 के बाद जब देश ने नव-उदारवादी मॉडल को स्वीकारा, तब देश को बड़ी मात्रा में धन लाभ का प्रलोभन मिला था.

मौजूदा समय में देश में 50 से ज्यादा औद्योगिक घराने हैं. इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे के पहले देश की समस्त पूंजी 10 या बीस घरानों के हाथों में केंद्रित थी, यही वहज थी कि बैंक उन घरानों के नियंत्रण में थे. इस अवस्था को देखते हुए उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का साहसिक निर्णय लिया. कॉर्पोरेट सेक्टर ने उनके इस फैसले का स्वागत भले ही न किया हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि इस कदम के बाद से ही देश में स्वउद्यमिता को बढ़ावा मिला. देश के भीतर कई छोटे और बड़े उद्योगपति स्थापित होने लगे और 1991 तक उद्योग जगत में यह सिलसिला चलता रहा. 1991 के बाद देश ने अमेरिकी नक्शेकदम पर चलते हुए एक नये, नवउदारवादी मॉडल को अपनाना करना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक बार फिर वही स्थितियां लौटकर आने लगीं. थापर, मोदी और साहूजी जैसे घराने की जगह नये घराने भी आने लगे. टाटा और बिड़ला तो निश्चित रूप से थे ही. आर्थिक शक्तियां फिर से उन्हीं दस घरानों के बीच सीमित होने लगीं. अगर सरकार विनिवेश करना चाहती है तो फिर से वही औद्योगिक घराने होंगे, जिनका उद्धरण दिया जाएगा. अगर कोई नई परियोजना शुरू होती है तो वही चुनिंदा औद्योगिक घराने ही उसे चलाते हैं और ये बड़ी आर्थिक ताकतें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने ढंग से नियंत्रित करने लगीं, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के लिए यह उद्यमी बड़े आर्थिक साधन बन रहे थे. इस तरह से समूची स्थितियां बदलने लगीं. ऐसे में किसी भी दल, मसलन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष खुद को असहाय महसूस करने लगा, क्योंकि आर्थिक संसाधनों के लिए वह पूरी तरह से किसी एक मुख्यमंत्री पर निर्भर हो गया. यही वजह है कि राजनीति अब विशुद्ध राजनीति न होकर आर्थिक राजनीति में तब्दील हो गई. यह स्थिति देश के लिए दुखद है. मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सत्ता में आना चाहती है और मुझे यह भी नहीं लगता कि वे इस तरह आर्थिक प्रलोभन के रास्ते पर चलकर इसे हासिल कर सकते हैं.

नरेंद्र मोदी का तथाकथित करिश्माई व्यक्तित्व दरअसल प्रचार की देन है. हालांकि, प्रचार आपको उतनी दूर तक लेकर नहीं जा सकता. इंटरनेट पर नरेंद्र मोदी के प्रशंसक कहते हैं कि यहां पर उनके प्रशंसकों की भारी जमात है, लेकिन अगर आंकड़ों पर गौर करें तो इंटरनेट की पहुंच देश की आठ प्रतिशत आबादी तक ही है और गांवो में जहां बिजली ही नहीं रहती, वो भला इंटरनेट का प्रयोग कैसे करेंगे. यही वजह है कि प्रसिद्धि के ये सभी तर्क विश्वास करने योग्य नहीं हैं, बल्कि उन्माद ज्यादा है, जबकि नेशनल मीडिया जो निश्चित रूप से बिकाऊ हो चला है, वह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनने के रास्ते पर हैं. निश्चित रूप से यह संभव नहीं है.

अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है तो उन्हें धनबल को कम महत्व देना होगा. अपने काडर के लिए काम करना होगा. ऐसी सरकार के बारे में सोचना होगा, जैसा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में थी. एक उदारवादी सरकार के बारे में सोचना होगा, न कि हिंदू अंधराष्ट्रीयता को बढ़ावा देने वाली सरकार के बारे में. ऐसा सोचने पर देश बंटेगा और हिंसा के रास्ते पर बढ़ेगा, जैसा कि उन्होंने मुजफ्फरनगर में किया.

दूसरा प्रमुख मुद्दा अर्थव्यवस्था और बाजार है. रघुराम राजन आरबीआई के नये गवर्नर बने. रुपये में कुछ मजबूती दिखी. बाजार भी संभलता दिखा, लेकिन यह सब केवल तात्कालिक है. यह तब तक नहीं संभलेगी, जब तक कि हमारा चालू वित्तीय घाटा ठीक नहीं होता. जब तक हम सोने के आयात पर रोक नहीं लगाते, तब तक हम अपने आयात-निर्यात के आंकड़ों का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे. हमें अपने आयात और निर्यात के आंकड़ों को नियंत्रित करना होगा और यह अंकगणित की तरह आसान है. हम अपने साधनों के बगैर इस उम्मीद के साथ नहीं रह सकते कि रुपये और बाजार की हालत ठीक हो. जब तक रघुराम राजन वित्त मंत्री का विश्वास नहीं हासिल कर लेते, तब तक दोनों को मिलकर हालात को काबू में रखने के लिए काम करना होगा, सरकार को नीति बनानी होगी और रिजर्व बैंक को उस पर काम करना होगा. अगर सरकार आयात पर रोक लगाती है, असंतुलन को ठीक करती है तो रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह दरों को कम करे और प्राइवेट सेक्टर को मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में प्रोत्साहित करे. जब तक यह सब होगा, तब तक काफी वक्त बीत चुका होगा और हम दूसरे देशों की तुलना में अपना प्रभुत्व खो देंगे. सरकार अपना प्रभाव खो देगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

समाचार पत्रों पर अंकुश कितना ज़रूरी

ठाकुर दास बंग

विज्ञापन की आय कम करके तथा अख़बारी क़ागज़ की क़ीमत बढ़ाने के साथ कृत्रिम कमी दिखाकर समाचार-पत्रों को कमज़ोर करने की भी कोशिश हुई हैं. समाचार पत्र बराबर यह मांग करते हैं कि उन्हें अपना क़ागज़ मांगने की अनुमति मिले, लेकिन सरकार राज्य व्यापार संगठन दावारा ही यह काम किए जाने पर ज़ोर देती रही हैं ताकि क़ागज़ के वितरण में राजनीतिक तौर पर जोड़-तोड़ की जा सके.

न्यायमूर्ति मैथ्यू ने दूसरे प्रेस आयोग की भी अध्यक्षता की थी जिसकी रपट सुक्षावों का एक समूह ही है जिसे यदि साथ लागू कर दिया जाय तो समाचार पत्र पंगु हो जाएंगे. आयोग के मतभेद प्रकट करने वाले चार सदस्यों ने इसे एक मोहक दु:स्वपन कहा है और इसे हथियारों का एक ऐसा शास्त्रागार बताया है जिसका प्रत्येक हथियार अच्छे से अच्छे समाचार-पत्र के लिए मारक है. बिहार का प्रेस विधेयक काफी बदनाम हो चुका है. इसे एक अलग-थलग तथ्य मानना भूल होगी. यह सचमुच सत्ता में स्थित पार्टी के दिमाग की उपज और एक प्रायोगिक परियोजना थी. यदि इसे बिहार में सफलता मिल गई होती तो उसे अन्य राज्यों में भी दुहराया जाता.

सार्वजनिक विरोध ने सरकार को विधेयक के सम्बंध में मुलायम बनने पर मजबूर कर दिया है. बिहार के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि विधेयक मर गया है, लेकिन केंद्रीय सरकार का कहना है यह अब भी विचाराधीन है. जब लोग धीरे-धीरे इसके तरफ से गाफिल हो जाएंगे तो केंद्रीय सरकार किसी दिन चुपके से इसे अपनी स्वीकृति दे देगी. दशकों पहले बिहार और उड़ीसा में पारित हुए ऐसे ही विधेयकों के सम्बंध में काफी कुछ कहा गया है. यदि उस समय उन विधेयकों घातक स्वरूप नहीं समझा गया तो उससे मौजूदा विधेयक कुछ कम आक्रामक नहीं हो जाता. इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने पहले चालाकी से बिहार संविधान सभा द्वारा आपराधिक दंड संहिता में एक संशोधन पारित करा लिया था. जिससे किसी पत्रकार को छह महीने तक हवालात में रखा जा सकता है. पुलिस के लिए आरोप पत्र देने की समय सीमा 180 दिन तक बढ़ा दी गई है. दूसरे संशोधन भी हैं जो पुलिस को पत्रकारों को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार देते हैं और जो कुछ अपराधों को गैर-जमानती बना सकते हैं. ये दोनों अधिनियम एक साथ मिलकर एक पूरा हथियार बन जाते हैं.

विज्ञापन की आय कम करके तथा अखबारी कागज की कीमत बढ़ाने के साथ कृत्रिम कमी दिखाकर समाचार-पत्रों को कमजोर करने की भी कोशिश हुई हैं. समाचार पत्र बराबर यह मांग करते हैं कि उन्हें अपना कागज मांगने की अनुमति मिले, लेकिन सरकार राज्य व्यापार संगठन द्वावारा ही यह काम किए जाने पर जोर देती रही है ताकि कागज के वितरण में राजनीतिक तौर पर जोड़ तोड़ की जा सके. कई राज्य सरकारों ने ऐसी विज्ञापन नीतियां अपनाई हैं जिनसे उन्हें अपने आलोचक समाचार पत्रों के खिलाफ भेदभाव बरतने का मौका मिल सके. छोटे समाचार पत्रों को, जो ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, पक्षपात दिखाकर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश हो रही है. सरकार के आलोचक समाचार पत्रों के दफ्तरों पर बिहार और कर्नाटक में छापा मारा गया है और उनकी लूट खसोट हुई है. बिहार, उड़ीसा तथा अन्य जगहों में पत्रकारों पर हमले हुए हैं और उनके प्रत्यायन पत्र को रद कर दिया गया है. उड़ीसा में सत्तारूढ पार्टी के समर्थकों द्वारा सरकार के आलोचक एक पत्रकार की पत्नी से बलात्कार कर उसे मार डाला गया. दूसरी ओर पत्रकारों के समूह को सस्ते दामों में बंगले आवंटित कर, विशिष्ट यात्राओं तथा कई अन्य उपायों द्वारा अपनी तरफ मिलाने की कोशिश हो रही है. समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखने और उन्हें अपनी ओर मिलाने के लिए इस्तेमाल की जा रही अन्य युक्तियों को एक-एक कर गिनाना उबाने वाला होगा. हमने मौलिक अधिकारों में कांट-छांट के उपायों की शुरुआत की थी. इनमें से सौ साल पुरानी डाक और तार अधिनियम की एक वह बेशर्म धारा है, जिसके अनुसार देशभर में न जाने कितने हजार लोगों के पत्र पढ़े व युक्ति द्वारा उनके टेलीफोन सुने जा रहे हैं. एक मेहनती पत्रकार ने यह पता लगाया कि कर्नाटक के शिमोगा जैसे छोटे शहर में पचास पत्रकार इन उपायों के शिकार बने. विरोधी दलों के सभी प्रमुख सदस्यों तथा बीसियों सर्वोदय कार्यकर्ताओं को चुपके से सुनी जाने वाली ऐसी टेलीफोन सूची में रखा गया है. ऐसी खबरें छपी थीं कि पिछली बार राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी न्यायमूर्ति एचआर खन्ना का टेलीफोन भी चुपके से सुना गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

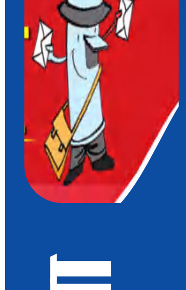

पाठकों की दुनिया

कांग्रेस सोनिया के सहारे

यूपीए 2 के घोटालों और नाकामियों से कांग्रेस की छवि जो देश में बनी है, उससे कांग्रेसी हताश एवं निराश हैं. 1998 में कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद भी यही हाल क्रांगेसियों का था, तब सोनिया ने कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भर दिया था. 2004 में कांग्रेस को जीत मिली और सोनिया ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया, लेकिन सत्ता पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के जरिए असर दिखाती रहीं. यूपीए 2 में सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में धसती चली गई और सोनिया कहीं नजर नहीं आई. कई बार मीडिया में सोनिया और मनमोहन के बीच कड़वाहट की भी खबरें आई. इस समय देश में सत्ता के प्रति जनता का मोह भंग हो चुका है और कांग्रेसियों को सोनिया का सहारा है. सोनिया कांग्रेस को पटरी पर लाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहीं हैं. सोनिया जानती हैं कि कांग्रेस के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है. अब उनके पास केवल इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा है और उसी के सहारे वैतरणी (2014 लोकसभा चुनाव) पार करना चाहती हैं. खाद्य सुरक्षा बिल और भूमि अधिग्रहण बिल पारित कराना इसी का एक हिस्सा है. कांग्रेस दिखाना चाहती है कि वह आज भी गरीबों के साथ है. सोनिया गांधी लोकसभा में खाद्य सुरक्षा विधेयक के पक्ष में कहा था कि सवाल यह नहीं है कि हम कर सकते हैं या नहीं. हमें करना ही होगा. इसी से कांग्रेसियों को भी संदेश दे दिया की चाहे जैसे चुनाव जीतना ही होगा और सोनिया गांधी क्रांगेस को एक बार भी नई उर्जा के साथ चुनाव के लिए तैयार कर रहीं हैं.

-नवीन कुमार, पटना

वाह रे नेता जी

सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2013 को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि यदि किसी सांसद और विधायक को अपराधिक मामले में दो साल की जेल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और कोई जेल में बंद है तो वह जेल से चुनाव नहीं लड़ सकता और न ही वोट दे सकता है. भला यह बात राजनीतिज्ञों को कैसे पसंद आती, क्योंकि यदि ऐसा होता तो कई नेता और मंत्री चुनाव लड़ने से वंचित रह सकते थे. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जिनके खिलाफ चारा घोटाले में फैसला आने वाला है. भाजपा के उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी अमित शाह जैसे कई सारे ऐसे नेता हैं, जिनके खिलाफ न्यायालय में केश लंबित है. इनके खिलाफ न्यायालय से फैसला आता है तो वे आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाते. अपराध पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले नेताओं के ऊपर जब संकट आया तो सभी ने एकजुट होकर कोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध किया. सरकार भी बिना देर लगाए संसद में संसोधन बिल लेकर आ गई और पहले ही दिन राज्यसभा ने इसे पास कर दिया. सरकार के रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर को मंजूर कर लिया और छह सितंबर को इस संसोधन विधेयक को संसद ने केवल 15 मिनट में ही पारित कर दिया. देश की गिरती अर्थ व्यवस्था, महंगाई, और गरीबी पर भी ऐसे ही तत्परता दिखाते शायद कोई हल निकल जाता और भारत इतने बड़े संकट से उबर जाता. नेताओं को देश की कोई चिंता नहीं, उन्हें तो केवल अपनी कुर्सी मे मतलब है.

-विजयंत, दरभंगा

सुलगता प्रदेश सोती सरकार

उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दगों से पता चलता है कि वहां कि प्रशासनिक तंत्र हर मोर्चे पर फेल हो चुका है. उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है. दंगा अखिलेश सरकार की निष्क्रियता को दर्शाती है. सरकार को पहले से इस बारे में जानकारी थी और इसके बावजूद दंगे हुए और दंगों में कई लोगों कों अपनी जानें गंवानी पड़ीं. गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री अखिलेश को सात सितंबर को फोन करके चेता दिया था कि दंगे हो सकते हैं. इसके साथ ही फर्जी वीडियो क्लिप को लेकर मिली खुफिया रिपोर्ट भी यूपी सरकार से साझा की गई थी, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट को तव्वजो नहीं दी. सरकार सारी जानकारियों के बावजूद भी दंगे रोकने में नाकाम रही. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि यह दंगे उनकी सरकार को अस्थिर करने की राजनीतिक साजिश है. राज्य में हुए दंगों पर राज्यपाल बीएल जोशी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच पूरी तरह से समन्वय नहीं होने की बात कही है. मुजफ्फरनगर में दंगा फैलने के चार दिन बाद जब मामला अधिक बिगड़ गया तो सरकार ने सेना बुलाई. इससे यही लगता है कि सरकार ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन सरकार पहले ही जाग जाती तो इतना बड़ा दंगा नहीं फैलता. जिससे यह लगता है कि प्रदेश सुलगता रहा अखिलेश सरकार सोती रही. अखिलेश सरकार ने सब कुछ जानते हुए भी मुजफ्फरपुर को सांप्रदायिक आग में झुलसने के लिए छोड़ दिया. अखिलेश जान रहे थे कि वहां पर तनाव है तो उन्होंने वहां होने वाली पंचायत पर रोक क्यों नहीं लगाई? यदि सरकार गंभीर होती तो इतना बड़ा मामला नहीं होता, इससे सरकार की नाकामियों का साफ पता चलता है.

-मनोज, सासाराम

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें:

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

यह राजनीतिक फ़ैसलों की घड़ी है

भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का झगड़ा इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि 75 साल से ऊपर के लोगों के लिए राजनीतिक फांसी का हुकुमनामा संघ द्वारा लिखा जा चुका है. इसका पालन नरेंद्र मोदी को करना है. इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम नरेंद्र मोदी को जल्लाद कह रहे हैं. हम सिर्फ राजनीति की उस व्यथा या विडंबना को उजागर करना चाहते हैं, जो कुर्सी की क्रूर लड़ाई से उपजती है. नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग राजनीति से बाहर वो लोग कर रहे हैं, जो देश को पश्चिम का गुलाम बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भीतर वो लोग कर रहे हैं, जो लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों की समझदारी का अतीत में शिकार हो चुके हैं. स्वयं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए आतुर नहीं दिखाई देते. हालांकि वे अपने भाषणों में सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बना रहे हैं. नरेंद्र मोदी न मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी कर रहे हैं और न ममता बनर्जी पर. नीतीश कुमार को तो वे किसी लायक ही नहीं समझते हैं. भाजपा के लोग नरेंद्र मोदी को उस हाथी के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, जो चींटियों को रौंदता हुआ चलता है.

लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का दर्द यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा समझते हैं. इसलिए ये तीनों लालकृष्ण आडवाणी के साथ खड़े हैं, पर इन तीनों के सामने भी यह स्पष्ट है कि इन्हें अगले चुनाव में टिकट नहीं मिलने वाला. हालांकि इस पर इन तीनों को ही विश्वास नहीं है. वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी घटनाओं पर चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं दलों में घटती रहती हैं, लेकिन जब दलों की घटनाएं देश में घटने वाली घटनाओं के पूर्व संकेत के रूप में प्रचारित की जाने लगें, तब कुछ तथ्यों के बारे में बात अवश्य करनी चाहिए.

भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार में विनम्रता का होना अति-आवश्यक है. वह स्वभाव से विनम्र भले ही न हो, लेकिन उसके शरीर की भाषा विनम्र होनी चाहिए. उसमें इतनी व्यवहार कुशलता होनी चाहिए कि वह पंद्रह दिन में एक बार देश के प्रमुख राजनीतिज्ञों से फोन पर बात कर ले. कभी-कभी उन्हें चाय या खाने पर बुला ले. जिसमें देश की समस्याओं पर अन्य दलों से बात करने की समझदारी हो. मनमोहन सिंह से पहले तक जितने प्रधानमंत्री हुए उन सबमें यह गुण मौजूद था. मनमोहन सिंह के शासन के दस साल इतिहास किस रूप में याद करेगा, यह सोच कर भी डर लगता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बिताया गया समय यह नहीं बताता कि नरेंद्र मोदी का दूसरे दलों के नेताओं को छोड़ दें, स्वयं अपने नेताओं से भी कोई अंतरंग संवाद हुआ हो. अंतरंग संवाद की सिर्फ एक घटना याद आती है, जिसमें अमर सिंह, अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी तीनों शामिल थे. नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के नेताओं को ही फोन नहीं करते और काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि विपक्षी दलों का कोई नंबर ही संपर्क की सूची में नहीं आता.

लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के साथ यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह ऐसे चेहरे हैं, जिनके देश के लगभग सभी राजनीतिक नेताओं के साथ संबंध हैं. इन्हें आडवाणी जी और जोशी जी द्वारा हमेशा सम्मान भी मिलता रहा है. इस कला में नरेंद्र मोदी अगर विश्वास नहीं करते तो फिर हमें मान लेना चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की ओर बढ़ रहा है. हो सकता है कि नरेंद्र मोदी यह मानते हों कि विपक्षी नेताओं से और अपनी पार्टी के नेताओं से ज्यादा बात करने में संशय बढ़ता है और वक्त भी बर्बाद होता है, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री पद की ख्वाहिश रखे, उसे अपने समकक्ष या अपने वरिष्ठ लोगों को सम्मान देना तो आना ही चाहिए. अगर नरेंद्र मोदी इस कसौटी पर खरे उतरते हैं, जिसका हमें ज्ञान नहीं है तो हम अपनी इस समझ के लिए उनसे क्षमा-याचना कर लेते हैं.

बीजेपी और कांग्रेस की आर्थिक नीतियां और उनके विकास का मॉडल एक जैसा है. इसलिए देश को लगता है कि एक बार फिर देश में गैर भाजपा और गैर कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए. हालांकि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि प्रधानमंत्रियों की जितनी संख्या भाजपा और कांग्रेस में है, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री भाजपा और कांग्रेस से बाहर चहलकदमी कर रहे हैं.

भारतीय जनता पार्टी में देश को लेकर अपनी समझ है, अपनी कल्पनाएं हैं. अब जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उतारने का फैसला पार्टी ने ले लिया है तो पार्टी को एक और फैसला लेना चाहिए. उसे देश में यह साफ घोषणा करनी चाहिए कि अगर वह सत्ता में आएगी तो धारा 370 खत्म करेगी. कॉमन सिविल कोड लागू करेगी और राम मंदिर बनाएगी. उसे यह भी घोषणा करनी चाहिए कि वह जीतने के छह महीने के भीतर पाकिस्तान पर हमला करेगी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कराकर भारत में मिलाएगी. उसे यह भी साफ घोषणा करनी चाहिए कि अगर उसे दो तिहाई बहुमत मिलता है तो इस देश में मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रहेंगे. वे अपने लिए कोई मांग नहीं उठा सकेंगे, उन्हें जो सरकार देगी उसी में खुश रहना पड़ेगा. यानी मुसलनाम दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रहना चाहे तो इस देश में रह सकता है. इसके साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद दलितों को सत्ता में कितनी हिस्सेदारी देगी, इसकी भी घोषणा करनी चाहिए.

पिछले साठ सालों से इस देश में भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर हमेशा चिंतित रही है. अब जब चुनाव में नरेंद्र मोदी के बहाने भाजपा अपने सिद्धांतों के आधार पर हिंदुओं को संगठित करना चाहती है और वोट लेना चाहती है तो उसे अपने मुद्दे भी देश के सामने साफ तौर पर रखने चाहिए. हमें विश्वास है कि देश इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह देश न केवल बदल जाएगा, बल्कि पूर्ण हिंदू राष्ट्र का दर्जा भी हासिल करेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भाजपा के खिलाफ वोट दे देता है तो भाजपा को और संघ को इन मुद्दों को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए और देश में भाईचारे, प्रेम-सौहार्द व विकास को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए. इसका फैसला 2014 में होने वाले चुनाव में होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि देश में बहुत सारे लोग इन मुद्दों पर देश का फैसला देखना चाहते हैं. अगर देश पहली तरह का फैसला करता है तो भारतीय जनता पार्टी के 75 साल से ऊपर के नेता अपनी आखों में खुशी लिए इस संसार से विदा होंगे और स्वर्ग या नर्क में जहां भी उनके पुराने साथी हैं, उन्हें जाकर बताएंगे कि वे उनका सपना पूरा करके आए हैं.

आजादी के बाद अब फैसले की घड़ी है. एक अजीब संयोग बन गया है कि पहले लोग कांग्रेस के खिलाफ गठजोड़ बनाते थे, अब बीजेपी के खिलाफ गठजोड़ की बात नहीं हो रही है, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ गठजोड़ की बात हो रही है. दरअसल, दोनों पार्टियों की आर्थिक नीतियां और उनके विकास का मॉडल एक जैसा है. इसलिए देश को लगता है कि एक बार फिर देश में गैर भाजपा और गैर कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए. हालांकि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि जितनी प्रधानमंत्रियों की संख्या भाजपा और कांग्रेस में है, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री भाजपा और कांग्रेस से बाहर चहलकदमी कर रहे हैं.

अभी कहानी का अंत दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ऊपर बैठा भगवान 120 करोड़ लोगों के भाग्य की पटकथा पूरी तरह लिख नहीं पा रहा है. शायद ईश्वर भी इस पसोपेश में है कि वो पटकथा का अंत सुखद करे या दुखद. ■

editor@chauthiduniya.com

अगला विश्वयुद्ध

मेघनाद देसाई

आजीवन भारत के मित्र रहे द न्यू स्टेट्समैन के मशहूर संपादक किंग्सले मार्टिन गांधी जी की हत्या के कुछ दिन पहले जब उनसे मिले तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध का गांधी जी पूरे मन से समर्थन कर रहे हैं. गांधी जी ने पहले विश्वयुद्ध के दौरान लोगों से ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होने की अपील भी की थी, क्योंकि वे ऐसा विश्वास करते थे कि ब्रिट्रिश साम्राज्य युद्ध में अपनी तरफ से न्याय के रास्ते पर है.

हम बहुत खुशनसीब नहीं हैं. कुछ युद्ध बहुत ही साफगोई से लड़े गए हैं. सीरिया में दो साल से बाहरी प्रतिनिधियों की भागीदारी से नागरिक युद्ध जारी है. इस युद्ध में एक लाख से अधिक लोगों की जान चली गई है और 70 लाख से अधिक लोग पलायन कर गए हैं. बशर अल-असद, जो कि केवल सीरियाई राजतंत्र का शासक होने का दावा करते हैं, लोकतांत्रिक नहीं हैं और हिजबुल्ला की मदद से सत्ता पर कब्जा किए बैठे हैं. दूसरी तरफ कुछ उदारवादी सुन्नी ताकतें और अलकायदा जैसे इस्लामिक आतंकवादी समूह हैं. पश्चिमी देशों ने युद्ध की निंदा की है और असद विरोधियों का समर्थन किया है, लेकिन एक दूरी बनाए रखी है. सउदी अरब और कतर ने विद्रोहियों को धन और हथियारों की आपूर्ति की.

सीरिया में जो रहा है वह नागरिक युद्ध है, लेकिन यह शिया-सुन्नी युद्ध भी है. यह लेबनान तक फैल रहा है. हिजबुल्ला को धन्यवाद कहना चाहिए कि लाखों शरणार्थी तुर्की और जॉर्डन चले गए हैं और शिया बहुल देश ईरान सीरिया का समर्थन कर रहा है. यूं तो तुलनाएं कभी भी बिल्कुल सटीक नहीं होतीं, लेकिन सीरिया का नागरिक युद्ध स्पेन के नागरिक युद्ध जैसा है, जो द्वितीय विश्वयुद्ध की पूर्वपीठिका साबित हुआ. हम जल्द ही एक पूरे मध्यपूर्व में एक युद्ध के गवाह बनेंगे, जिसमें हिजबुल्ला के साथ ईरान, इराक और सीरिया एक तरफ होंगे और सभी सुन्नी देश व अन्य इस्लामिक राष्ट्र दूसरी तरफ होंगे.

यदि ऐसा कोई युद्ध होता है तो उससे बचने का कोई पूर्वानुमान नहीं हो सकता. 1940 के

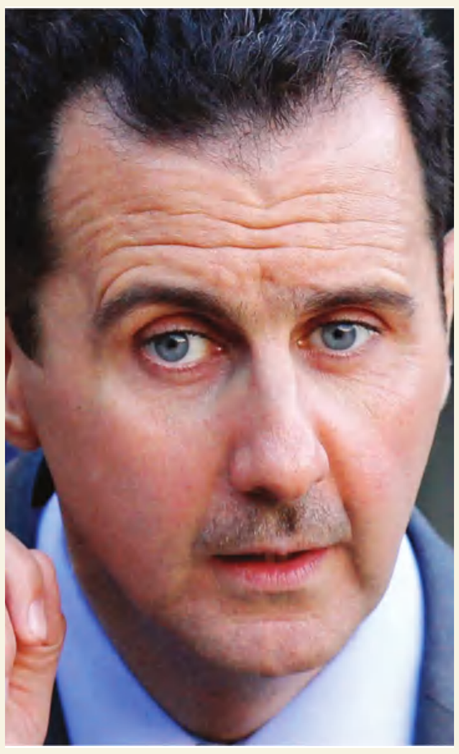

दशक में संयुक्त राष्ट्र के साथ जो विश्व-व्यवस्था बनाई गई थी, उसकी अपनी समस्याएं हैं. सुरक्षा परिषद में कभी-कभार ही कॉमन योजना पर सहमति बन पाई है. शीतयुद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र शायद ही अपनी भूमिका निभा सका. 1991 के बाद पश्चिमी देशों ने पूरी दुनिया में मानवाधिकारों को लागू कराने के लिए उदार हस्तक्षेप की नीति के तहत दखल देना शुरू किया. यूगोस्लाविया में जब भयावह मानवाधिकारों का हनन हुआ, इस नीति ने काम किया, लेकिन इराक में यह असफल हो गई.

अब जब सीरिया में सत्ता द्वारा रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, (जो कि ज्यादा विश्वसनीय लगने वाला कारण प्रतीत हो रहा है) विश्व-व्यवस्था के झंडाबरदारों को सामने बहुत ही मुश्किल विकल्पों का सामना करना है. रासायनिक हथियारों के विरुद्ध सहमति बननी चाहिए. हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसपर सहमति नहीं बनेगी, वीटो सिस्टम को धन्यवाद कहना चाहिए. ब्रिटेन की संसद ने पहले ही दखलंदाजी के विकल्प को नकार दिया है. बराक ओबामा संसद में कांग्रेस की अनुमति के लिए जोर लगा रहे हैं, जिसकी तकनीकी तौर पर उन्हें जरूरत नहीं है. यह पहले से साफ है कि कांग्रेस सैनिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगी.

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस निर्णय पर बहुत से लोग खुश होंगे. यह स्पष्ट है कि पुरानी शक्तियां-अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के पास न तो इच्छाशक्ति है, न ही ताकत है कि जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है, उसे अमल में ला सकें. बहुत से लोग भारत में और वास्तव में गैर-पश्चिमी देश दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि एक प्रभुसत्ता-संपन्न के पास अपनी ही जनता के खिलाफ बमबारी, प्रताड़ना और हत्या का आत्यांतिक अधिकार है. लगता नहीं कि किसी भी तरह का अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप पसंद किया जाएगा. लेकिन फिर, जब हमारे कोई भी सार्वभौमिक नियमों को लागू कराने वाला नहीं होगा, विश्व-व्यवस्था कैसी दिखेगी?

एक सवाल है कि क्या सभी देश एक तरह के सामान्य-सार्वभौमिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, जिसका वे खुद पालन करते हों और अपने पड़ोसी से भी ऐसा करने की अपील करते हों? यह अक्सर कहा जाता है कि मानवाधिकार केवल पश्चिमी जगत का फैशन है, यह सार्वभौमिक नहीं है. ठीक है. फिर क्या हम सद्दाम हुसैन का अपने नागरिकों पर हमले को स्वीकृति देंगे? या ईरान-इराक युद्ध के समय ईरानियों पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को स्वीकृति देंगे? क्या हमारे पास एक अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय नहीं होना चाहिए जो कि रैदवन कैरेडजिक जैसे निरंकुश लोगों पर नकेल कसे? शायद ऐसा नहीं हो सकता. पुरानी विश्व-व्यवस्था मृतप्राय हो चुकी है. यह द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बनी थी और शायद मध्यपूर्व में आगामी युद्ध नई व्यवस्था को जन्म देगा. लेकिन तब तक कितनी मौतें हो चुकी होंगी? ■

feedback@chauthiduniya.com

सवाल है कि क्या सभी देश एक तरह के सामान्य-सार्वभौमिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, जिसका वे खुद पालन करते हों और अपने पड़ोसी से भी ऐसा करने की अपील करते हों? यह अक्सर कहा जाता है कि मानवाधिकार केवल पश्चिमी जगत का फैशन है, यह सार्वभौमिक नहीं है. ठीक है. फिर क्या हम सद्दाम हुसैन का अपने नागरिकों पर हमले को स्वीकृति देंगे? या ईरान-इराक युद्ध के समय ईरानियों पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को स्वीकृति देंगे?

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

सूचना शुल्क : कैसे-कैसे लोक सूचना अधिकारी

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

चौथी दुनिया ब्यूरो

सूचना के अधिकार क़ानून की धारा-7 में सूचना मांगने के लिए शुल्क की बात की गई है. धारा-7 की उप धारा-1 में लिखा गया है कि यह फीस सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी. इसमें स्पष्ट किया गया है कि आवेदन करने से लेकर फोटोकॉपी आदि के लिए कितनी फीस ली जाएगी. देश के सभी राज्यों में अथवा केंद्र में सरकारों ने फीस नियामवाली बनाई हैं और इसमें आवेदन के लिए कहीं 10 रुपये शुल्क रखा गया है, तो कहीं 50 रुपये. इसी तरह दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी लेने के लिए भी 2 रुपये से 5 रुपये तक की फीस अलग-अलग राज्यों में मिलती है.

इसके लिए किसी लोक सूचना अधिकारी को यह अधिकार क़तई नहीं दिया गया है कि वह मनमाने तरीक़े से फीस की गणना करे और आवेदक पर मोटी रक़म जमा कराने के लिए दबाव डाले. लेकिन इस क़ानून के बनने से लेकर अभी तक ऐसे कई मामले सामने आए, जिसमें लोक सूचना अधिकारियों की मनमानी देखने को मिली. ऐसे ही कुछ उदाहरणों पर एक नज़र.

दिल्ली पुलिस ने 13949 रुपये मांगे

चोरी हुए मोबाइलों के बारे में सूचना मांगने पर सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध जैन से पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) ने पत्र के माध्यम से 13949 रुपये जमा कराने को कहा. सुबोध ने दिल्ली पुलिस से 10 ज़िलों से चोरी हुए मोबाइल, प्राप्त हुए मोबाइल आदि के बारे में जानकारी चाही थी. इसके लिए उन्होंने पुलिस मुख्यालय में आवेदन दाख़िल किया, जिसे सभी ज़िलों के डीसीपी के यहां प्रेषित कर दिया गया. पुलिस का कहना था कि सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए एक सब इंस्पेक्टर को दो दिन तक लगाया जाएगा जिसकी लागत 1546 आंकी गई है. साथ ही यह भी बताया कि दो हेड कांस्टेबलों को तीन दिन इसमें लगाया जाएगा और 13 कांस्टेबल इस काम में दो दिन के लिए लगाए जाएंगे. हेड कांस्टेबलों के लिए 1353 और कांस्टेबल के लिए 11050 रुपये जमा कराने को कहा गया.

78 लाख रुपये की सूचना

भोजपुर ज़िले के गुप्तेशवर सिंह से भोजपुर आपूर्ति अधिकारी ने आवेदन में मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिए 78 लाख 21 हज़ार 252 रुपये जमा करने को कहा. वह भी सूचना उपलब्ध कराने की 30 दिन की समय सीमा निकल जाने के बाद. गुप्तेश्वर सिंह ने 2000 से 2008 के बीच ज़िले के कुछ क्षेत्रों में जन वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए गए अनाज और मिट्टी के तेल की जानकारी मांगी थी. आवेदन में डीलर के भुगतान रसीद की छायाप्रति भी मांगी गई थी.

आवेदन के जवाब में सूचना अधिकारी ने कहा-आपके द्वारा मांगी गई सूचनाएं विवरण के साथ तैयार हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले छायाप्रति शुल्क के रूप में 7821252 रुपये जमा करने होंगे. हालांकि बाद में सूचना आयोग में अपील करने के बाद मुफ्त में सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए.

गुजरात वक़्फ़ बोर्ड ने 4.7 लाख रुपये मांगे

अहमदाबाद के हुसैन अरब द्वारा दायर आरटीआई आवेदन का जवाब देने के लिए राज्य के वक़्फ़ बोर्ड ने 474690 रुपये की मांग की. हुसैन अरब ने 6 फरवरी, 2007 को आवेदन दाख़िल कर बोर्ड पर लगे प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों का ब्यौरा और गुजरात चैरिटी कमिश्नर द्वारा 2001 में पारित योजना को लागू न करने का कारण जानना चाहा था.

आवेदन में उन्होंने मुस्लिम ट्रस्ट के अधीन अहमदाबाद, सूरत और भरूच में संपत्तियों की जानकारी भी मांगी थी. सूचना के स्थान पर उन्हें वक़्फ़ बोर्ड के लोक सूचना अधिकारी ने सूचना हासिल करने के लिए उक्त राशि जमा करने को कहा.

झज्जर अस्पताल में फोटोकॉपी शुल्क 4 लाख 92 हज़ार रुपये

हरियाणा के झज्जर अस्पताल के लोक सूचना अधिकारी ने आवेदक नरेश जून द्वारा दायर आरटीआई आवेदन का 5 महीने बाद जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि आवेदक सूचनाएं हासिल करने के लिए 4 लाख, 92 हज़ार 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में जमा करा दे. नरेश जून ने आवेदन में मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) की सूचनाएं मांगी थीं, जिसमें भारी मात्रा में घोटाले का अंदेशा था. आयोग के हस्तक्षेप के बाद जानकारी मिली जिससे स्पष्ट हो गया कि एमएलसी शुल्क के रूप में जो राशि वसूली जाती है, उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है. शुल्क के रूप में वसूली गई राशि की कैश बुक में प्रविष्टि नहीं होती थी. नरेश जून को इन सूचनाओं को हासिल करने के लिए जेल तक जाना पड़ा और उनके ख़िलाफ़ झूठा मामला तक दर्ज किया गया.

सुल्तानपुर ज़िला कार्यक्रम कार्यालय ने 70 लाख रुपये मांगे

सूचना के अधिकार के तहत सुल्तानपुर के आइमा गांव में रहने वाले रमाकांत पांडे को सूचना तो नहीं मिली, उल्टे 70 लाख रुपये जमा करने का पत्र ज़रूर मिल गया था. रमाकांत ने ज़िला कार्यक्रम अधिकारी के पूरे कार्यकाल के आवागमन (भ्रमण पंजिका), जनपद में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की सूची, केंद्र से छात्रों को शासन द्वारा निर्धारित मानक, छात्रों की भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के साथ-साथ कई और जानकारियां मांगी थीं. निर्धारित 30 दिन बीत जाने के बाद प्रथम अपील दाख़िल की गई. जवाब में सूचना के लिए निर्धारित शुल्क जमा कराने की बात कही गई. इसके बाद 70 लाख रुपये जमा करने की जानकारी देने वाले पत्र को देखकर रमाकांत हक्के-बक्के रह गए. ज़िला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय के पत्र के अनुसार, मांगी गई सूचनाओं को ब्यौरा देते हुए लिखा गया कि लाभार्थियों की संख्या 519034 और अन्य नाम पते विवरण आदि देने में अनुमानित व्यय 77 लाख 85 हज़ार 510 रुपये लगाते हुए उनसे 78 लाख 14 हज़ार 245 रुपये जमा कराने को कहा गया था. पत्र में यह भी कहा गया कि धनराशि का अग्रिम 90 प्रतिशत (70 लाख 32 हज़ार 820 रुपये) पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर जमा करने पर सूचनाओं के तैयार करने संबंधी कारवाई शुरू की जाएगी.

औरंगाबाद में सूचना देने के लिए 50 हज़ार रुपये मांगे

औरंगाबाद के सदर अनुमंडल, राजस्व के लोक सूचना अधिकारी से राशन और तेल आपूर्ति के संबंध में जानकारी मांगने पर नवल किशोर प्रसाद से 49974 रुपये की मांग की गई थी. वह भी आरटीआई आवेदन दाख़िल करने के 30 दिन बाद. अप्रैल 2008 में जनहित में दायर इस आवेदन में नवल ने माहवार वितरित किए गए तेल और राशन आदि का ब्यौरा मांगा था. सूचना हेतु मांगी गई राशि की वजह 24984 पेजों की सूचना बताई गई.

बरगढ़ में सिंचाई परियोजना की जानकारी 30 हज़ार की

ओडिसा के बरगढ़ ज़िले के तुकुरला गांव के सहदेव मेहर ने एक लघु सिंचाई परियोजना के बारे में ज़िला मुख्यालय से जानकारी मांगी तो क़रीब सात महीने बाद मिले पत्र में कहा गया- सूचना चाहिए तो 30 हज़ार रुपये जमा करा दें. सहदेव ने आवेदन में परियोजना में ख़र्च की गई राशि, इसके अंतर्गत डूबी ज़मीन आदि के बारे में जानना चाहा था. ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301 ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष

21 मार्च से 20 अप्रैल

इस सप्ताह आपके जीवन में अत्यधिक चहल-पहल रहेगी और आपका पराक्रम बढ़ेगा. स्वास्थ्य में भी हल्का उतार-चढ़ाव रहेगा. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. शत्रुओं से सावधान रहें. लम्बी यात्रा से बचें.

वृष

21 अप्रैल से 20 मई

इस सप्ताह आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन यह सप्ताह आपके लिए मिला-जुला फल देने वाला होगा. पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी और संतान का शुभ समाचार मिलेगा. भाग्य अच्छा रहेगा. भाई-बहनों और मित्र बंधु से वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं. आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए शुभ रहेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा.

मिथुन

21 मई से 20 जून

इस सप्ताह यात्रा का योग है. जीवनसाथी का पूर्ण साथ मिलेगा और समस्याओं से छुटकारा मिलेगा. व्यापारी और नौकरीपेशा वाले लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. इस सप्ताह अधिकारियों और राजनीतिज्ञों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा.

कर्क

21 जून से 20 जुलाई

इस सप्ताह आपकी धार्मिक कार्यो में रुचि रहेगी. यात्रा का योग है. ध्यान से कार्य करें, फायदा होगा. सबकी बात सुनें, लेकिन अपने मन का ही कार्य करें. आपस में प्रेम बनाकर रखें. घरेलू मामलों को ज्यादा तूल न दें. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. अपने द्वारा जमा किए गए पैसों का सदुपयोग करें.

सिंह

21 जुलाई से 20 अगस्त

इस सप्ताह किसी को भी पैसे उधार देने से बचें. जमीन-जायदाद खरीदने का मौका मिलेगा. मित्रों से प्रेम बनाकर रखें, जिससे आपको आर्थिक फायदा होगा. उत्तेजना में आकर कोई भी निर्णय न लें. व्यवसाय और नौकरीपेशा वाले लोगों के लिए समय अच्छा है. दांपत्य जीवन सुखी रहेगा.

कन्या

21 अगस्त से 20 सितंबर

इस सप्ताह आप दूसरों का ध्यान रखेंगे. आप अपने रहस्यों को किसी से न बताएं और स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पारिवारिक और व्यक्तिगत तनाव रहेगा, जिससे परेशानी हो सकती है, इससे बचें. जहां जोखिम हो, वहां पैसे का निवेश न करें. वाहन चलाते समय ध्यान दें. दांपत्य जीवन में तनाव से बचें और शत्रुओं से सावधान रहें.

तुला

21 सितंबर से 20 अक्टूबर

इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों को भी सकारात्मक ऊर्जा देगें. अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाएंगे, जिसका आपको फायदा मिलेगा. किसी नये पद के लिए मेहनत की आवश्यकता है. आप लोगों की मदद करेंगे. आर्थिक रूप से यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा. आपका स्वास्थ उत्तम रहेगा.

वृश्चिक

21 अक्टूबर से 20 नवंबर

इस सप्ताह आप व्यस्त रहेंगे. आप किसी से क्रोध में बात न करें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, जिससे आपके सारे कार्य पूरे होंगे. नौकरी में उन्नति मिलेगी. आर्थिक स्थिति थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. स्थान परिवर्तन का योग है. विरोधी पराजित होंगे.

धनु

21 नवंबर से 20 दिसंबर

इस सप्ताह कठिनाइयां आ सकती हैं. मजबूती से काम करें और तनाव से बचें. व्यापारी और नौकरीपेशा वाले लोगों पर दबाव बढ़ सकता है. कोई भी कार्य करने से पहले उस पर विचार करें. जल्दी में कोई निर्णय न लें. शत्रुओं से सावधान रहें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर

21 दिसंबर से 20 जनवरी

इस सप्ताह सामाजिक और पारिवारिक कार्यो में रुचि बढ़ेगी. नौकरी वाले लोगों के लिए यह सप्ताह दबाव वाला रहेगा और काम को लेकर चिंता बढ़ेगी. व्यापारी कार्य आगे बढ़ाने की योजना बनाएंगे. मित्रों से मुलाकत होगी, जिससे आपकी स्थिति मजबूत होगी. परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

कुंभ

21 जनवरी से 20 फरवरी

इस सप्ताह ज्यादातर आप अपने व्यक्तित्व को लेकर सतर्क रहेंगे, उसे बढ़ेगा. आपकी धार्मिक कार्यो में भी रूचि बढ़ेगी. स्वास्थ्य मिला-जुला रहेगा. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. व्यापार के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा.

मीन

21 फरवरी से 20 मार्च

इस सप्ताह आपके बने हुए कार्य बिगड़ सकते हैं. सावधानी बरतें. कार्यो को लेकर आपकी प्रशंसा होगी. आप लोगों के दुःख-सुख में हिस्सा लेंगे, जिससे आपको फायदा होगा. नौकरी वाले किसी बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं. स्वास्थ्य उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. लेन-देन करते समय सावधानी बरतें. अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसका आपको फायदा होगा.

ज़रा हट के

13 साल की उम्र में एमएसएसी

महज सात साल में हाईस्कूल पास करने वाली सुषमा वर्मा अब 13 साल की उम्र में लखनऊ विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ साइंस (एमएससी) में दाखिला ले चुकी है. हाईस्कूल पास कर रिकॉर्ड बनाने वाली वंडर गर्ल के नाम से मशहूर सुषमा इसी के साथ एक बार फिर चर्चा में है और एक नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार है. लखनऊ के कृष्णानगर निवासी श्रमिक तेज बहादुर वर्मा की बेटी सुषमा ने महज सात साल की उम्र में हाईस्कूल, नौ साल की उम्र में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की है. उसने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (सीएमएस) डिग्री कॉलेज से इसी साल बीएससी की डिग्री हासिल की. उसने एमएससी माइक्रोबायलॉजी में दाखिला लिया है. सुषमा इन दिनों लखनऊ विश्वविद्यालय के दूसरे छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. उसके सभी सहपाठी लगभग दोगुने उम्र के हैं. ऐसे में हर छात्र सुषमा से उसकी कामयाबी की कहानी जानना चाहते हैं. छात्रों का कहना है कि सुषमा हमारे लिए एक मिसाल है, जिससे हमें चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है.

सुषमा का नाम एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में दाखिले की कटऑफ सूची में आने के बाद बेहद गरीब परिवार से होने के वजह से एडमिशन फीस भरने में मुश्किलें आईं, लेकिन प्रतिभाशाली सुषमा की मदद के लिए कई हाथ आगे आए. लखनऊ विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉ. मनोज दीक्षित का कहना है कि

सुषमा किसी चमत्कार से कम नहीं. ऐसे में समाज को चाहिए कि सुषमा की हर तरह से मदद करे.

उन्होंने बताया कि गीतकार जावेद अख्तर और अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट में कार्यरत अनिवासी भारतीय रफत सरोस ने सुषमा की पढ़ाई में आने वाले खर्च में मदद का भरोसा दिया है. सुषमा के पिता तेज बहादुर का कहना हैं कि घर की माली हालत ठीक न होने की वजह से मुझे अपनी बेटी को पढ़ाने में कठिनाइयां आ रही थीं, लेकिन मैं उन सभी लोगों का बहुत आभारी हूं, जो लोग मदद के लिए आगे आए हैं. बहादुर ने कहा कि बिना लोगों की मदद के मैं अपनी बेटी की फीस भरकर उसे एमएससी में दाखिला नहीं दिला सकता था. सुलभ इंटनेशनल के प्रमुख बिंदेश्वरी पाठक ने भी सुषमा की पढ़ाई में मदद के लिए पांच लाख रुपये देने को कहा है. उन्होंने कहा अगले सप्ताह वह स्वयं लखनऊ आकर सुषमा के पिता को पांच लाख रुपये देंगे.

सुषमा कहती है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से माइक्रोबायलॉजी के बाद पीएचडी करना चाहती हूं और 18 साल की होने पर सीपीएमटी की परीक्षा दूंगी. वह कहती है कि घर की गरीबी को देखते हुए अभी तक यह सब बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन लोगों की मदद से आश जगी है कि मैं अपना मुकाम हासिल कर लूंगी. अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ने वाली सुषमा को बी एस अब्दुर्रहमान विश्वविद्यालय, चेन्नई की तरफ से मुफ्त एमएससी की पढ़ाई का भी ऑफर मिला है. ■

पांच साल के बच्चे ने उड़ाया जहाज

केवल पांच साल की उम्र में चीन के एक लड़के ने विमान उड़ाकर सबको हैरत में डाल दिया है. हे यिडे नामक इस बच्चे का घरेलू नाम डुओडुओ है और उसने बीजिंग वन्य जीव पार्क के ऊपर 31 अगस्त को 35 मिनट तक विमान उड़ाया. चीनी मीडिया इस बारे में जानकारी दी है.

जिस उड़ान क्लब में डुओडुओ विमान उड़ाना सीख रहा है, उसके प्रभारी झांग योंगहुई ने कहा कि डुओडुओ ने 30 किलोमीटर तक विमान उड़ाया. इस बच्चे ने 2012 में तब अचंभा कर दिखाया था, जब बर्फ पर दौड़ते हुए उसका अर्धनग्न वीडियो इंटरनेट पर तेजी से प्रसारित हुआ था. उसके परिवार ने न्यूयार्क में शून्य से 13 डिग्री नीचे तापमान पर यह वीडियो तैयार किया था. मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बच्चे ने एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में जलपोत भी चलाया और तूफानी बारिश के दौरान जापान के फूजियामा पर्वत पर चढ़ने में सफलता भी हासिल की. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) देशों ने इस सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में उत्पन्न संकट से ख़ुद को बचाने के लिए संयुक्त विकास बैंक की स्थापना की घोषणा कर दी है. वित्तीय अस्थिरता की स्थिति में यह बैंक ब्रिक्स देशों के लिए महत्वपूर्ण होगा.

राजीव रंजन

जी20 सम्मेलन

क्या हुआ हासिल

भारत ने जी-20 के 2008 में प्रथम शिखर सम्मेलन से लेकर अब तक के सभी सम्मेलनों में भाग लिया, फिर भी भारत जी-20 सम्मेलनों से आज तक कुछ खास हासिल नहीं कर पाया. कम से कम बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और रुपये की खराब स्थिति तो भारत का यही हाल बयां करती है. ऐसे में देखना यह है कि 5-6 सितंबर, 2013 को रूस के पिटर्सबर्ग में जी-20 देशों के सम्मेलन में भारत को क्या हासिल हुआ.

भारत ने हाल ही में जी-20 सम्मेलन में शिरकत की. यह सम्मेलन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 5 और 6 सितंबर को हुआ. जी-20 एक अहम मंच है, जिसमें सभी पांच महाद्वीपों के प्रतिनिधि शामिल हैं. इसका गठन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर विचार के लिए एक प्रमुख मंच के तौर पर किया गया है. इस बार यही सम्मेलन का एजेंडा भी था. भारत की ओर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया, विदेश सचिव सैयद अकबरूद्दीन ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से चरणबद्ध तरीके से राजकोषीय प्रोत्साहन वापस लिए जाने के फैसले के बीच इस बार का सम्मेलन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था. अमेरिका के इस फैसले से भारत और अन्य बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं नरमी की चपेट में आ गई हैं और इन्हें पूंजी निकासी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इससे इन देशों की मुद्राएं दबाव में हैं. ऐसे में ये देश इससे पड़ने वाले प्रभाव से बचने के प्रयास में हाथ-पांव मार रहे हैं. ब्रिक्स सदस्य देश ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने इस शिखर सम्मेलन में ऐसे वक्त में भाग लिया, जब उनकी अर्थव्यवस्था धीमी विकास दर और अपने यहां की गिरती मुद्रा व्यवस्था से परेशान है. वर्ष 2008 में वाशिंगटन में पहली जी-20 शिखर बैठक हुई थी. भारत के प्रधानमंत्री सभी बैठकों में शामिल हुए हैं. प्रधानमंत्री ने जी-20 के सभी सम्मेलनों में हिस्सा लेकर काफी कुछ अनुभव हासिल किया होगा. ऐसे में गर्त में जा रही भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए प्रधानमंत्री ने इस बार के सम्मेलन में क्या हासिल किया, इसे लेकर लोगों में उत्सुकता है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस सम्मेलन में कहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था अच्छी हालत में नहीं है. ऐसे में जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक मामलों के कारण प्रभावित हुई हैं, उन देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर लाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने होंगे. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि बुनियादी ढांचे का विकास आर्थिक वृद्धि और विकास प्रक्रिया को तेज कर सकता है. राहत की बात है कि सम्मेलन की कार्य योजना और विश्व बैंक के अध्यक्ष भी भारत के इन मतों से इत्तेफाक रखते हैं, जो आने वाले दिनों में भारत के लिए बड़ी मदद के रूप में सामने आ सकती है. इस सम्मेलन में भारतीय पक्ष पर चीन और रूस जैसे देशों ने काफी तवज्जो दी है, जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. भारत को इस सम्मेलन में क्या हासिल हुआ, आइए जानते हैं.

आर्थिक स्थिति सुधरी

ऐसे समय में, जब भारत की आर्थिक स्थिति डावांडोल है, वर्तमान जी-20 सम्मेलन ने भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने में सराहनीय योगदान दिया है. हालांकि पिछले सम्मेलनों से भारत को कुछ खास हासिल नहीं हो पाया था, लेकिन जिस तरह से भारत को कुछ यूरोपीय देशों ने अपना समर्थन दिया है और ब्रिक्स देशों ने एकजुटता दिखाई है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत की आने वाले दिनों में अमेरिका पर निर्भरता कम होगी. जी-20 सम्मेलन में इसके सदस्य देशों में सीरिया पर हमले को लेकर गहरा मतभेद सामने आया, जिससे फिलहाल सीरिया पर हमला टल गया है. हालांकि हमला होना या न होना अमेरिकी हितों पर निर्भर करता है, इसलिए साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि सीरिया पर अमेरिका हमला नहीं करेगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, उससे निवेशकों और व्यापारियों में विश्वास का माहौल बना है, जिसका असर भारत में भी साफ देखा गया. ऐसा नहीं कि भारतीय रुपया और सेंसेक्स सुधरने के पीछे सिर्फ सीरिया पर हमला नहीं होना ही कारण है. गौरतलब है कि सीरिया को चाय, मसाला, चावल का बड़े पैमाने पर भारत निर्यात करता है, जो हमले की संभावना के कारण काफी हद तक प्रभावित हुआ था, जिससे भारतीय आर्थिक हित प्रभावित हुए थे. फिलहाल सीरिया पर हमला टलने की संभावना की जो खबरें आ रही हैं, उससे भारतीय रुपये में भी सुधार देखने को मिला और सेंसेक्स भी पिछले चार-पांच वर्षों में सबसे बड़े उछाल के साथ सामने आया.

इन्फ्रा कार्यक्रम पर चर्चा

इस सम्मेलन में भारत का इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम भी चर्चा का विषय रहा. भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम के तहत जिस दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना होनी है, उसके अंतर्गत दिल्ली एवं मुंबई को हाई स्पीड रेल और रोड लिंक्स से जोड़ा जाएगा. इसमें 100 अरब डॉलर का निवेश होना है. इसके अलावा इसमें दो बड़े बंदरगाहों की स्थापना करना भी शामिल है.

जी-20 देश और उनका योगदान

इसके सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, इटली, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका व यूरोपीय संघ शामिल हैं. वैश्विक अर्थव्यवस्था में जी-20 का योगदान 90 प्रतिशत है. वैश्विक व्यापार में यह 75 प्रतिशत योगदान करता है. दुनिया की दो तिहाई आबादी जी-20 देशों में है.

ब्रिक्स मुद्रा कोष का गठन

ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) देशों ने इस सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में उत्पन्न संकट से खुद को बचाने के लिए संयुक्त विकास बैंक की स्थापना की घोषणा कर दी है. भारत के लिए इस बैंक की स्थापना का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की घोषणा के बाद विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजारों से अपना धन निकालने लगे थे और इसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, इस बैंक की स्थापना से अब भारत अमेरिकी आर्थिक नीतियों का करारा जवाब दे सकता है. इस सम्मेलन में इस बात पर भी ब्रिक्स देश एकमत हुए कि वे एक-दूसरे की आर्थिक सहायता करेंगे और बैंक में निवेश किए गए धन का उपयोग विकासशील देशों के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा. इस बैंक की प्रारंभिक पूंजी 50 अरब डॉलर होगी और इसका रिजर्व कोष 100 अरब डॉलर का होगा. ब्रिक्स देशों का यह कदम भुगतान को नियंत्रित रख सकेगा और पूंजी प्रवाह को संतुलित करेगा.

भारत सम्मेलन के नतीजों से संतुष्ट

भारत ने जी-20 शिखर सम्मेलन के घोषणापत्र पर संतोष जताया है. भारत को इस बात से संतोष है कि इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के बीच एक-दूसरे के हितों का ख्याल रखने और आपसी मदद करने को लेकर सहमति बनी है. इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और ऊर्जा सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया. भारत को इस बात की भी खुशी है कि जी-20 ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और चीन और रूस जैसे देशों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया. भारत इस बात से भी आश्वस्त है कि उसकी मुख्य चिंता को स्वीकार किया गया है और विकसित देश अपनी मौद्रिक नीति नपे-तुले ढंग से बनाने और विकासशील देशों को उसकी ठीक जानकारी देने पर सहमत हुए हैं. जी-20 समूह ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि जिस देश में आर्थिक गतिविधियां हुई हैं, उनके मुनाफे पर ही कर लगेगा. सच मायने में देखा जाए तो यह भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है. चूंकि हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में उन पर बकाया कर की वसूली का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में हमारी स्थिति काफी मजबूत हुई है. भारतीय प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के दौरान जापान के उपप्रधानमंत्री तारो असो से मिलकर द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय का विस्तार करने का भी फैसला किया. प्रधानमंत्री ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विकासशील देशों में बुनियादी ढांचों के विकास के लिए उन्नत वित्तपोषण योजनाएं तैयार करने पर जोर भी दिया. उन्होंने पेशेवरों के अंतरराष्ट्रीय आवागमन को सीमित करने के नये उपायों से बचने की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि यह आनेवाले वर्षों में वैश्विक विकास का दम घोंट देगा, जो किसी के हित में नहीं है. इससे पूंजी प्रवाह और मुद्रा में उतार-चढ़ाव को कम किया जा सकेगा, जिससे भारत वर्तमान तंगी से उबर सकेगा. ■

जी-20

जी-20 शिखर सम्मेलन 5 और 6 सितंबर, 2013 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया. जी-20 विश्व के बीस देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का एक संगठन है, जिसमें 19 देश तथा यूरोपीय संघ शामिल हैं. यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष तथा यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है. जी-20 की सभी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर सकल वैश्विक उत्पाद का 80 फीसद योगदान करती हैं. जी-20 का प्रस्ताव कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल मार्टिन ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से संबंधित मामलों के लिए सहयोग एवं सुझाव मंच के रूप में दिया था. इस संगठन का औपचारिक आरंभ सितंबर 1999 में किया गया था. पहली बैठक दिसंबर 1999 में हुई थी. भारत की ओर से जिन प्रमुख लोगों ने जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, उनमें प्रमुख हैं- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया, विदेश सचिव सैयद अकबरूद्दीन आदि. यह सम्मेलन पहले के सम्मेलनों से इस मायने में खास था कि विकसित देशों की आर्थिक नीतियों को करारा जवाब देने के लिए ब्रिक्स देशों में एकजुटता देखने को मिली.

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

साई

साई कुछ दिनों बाद किसी को कुछ बताए बिना शिरडी से चले गए. जब वे दोबारा शिरडी पहुंचे तो खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति ने उन्हें साई कहकर पुकारा था, तब से ही उनका नाम साई बाबा पड़ गया. साई फिर वहां से वापस नहीं गए और हमेशा के लिए शिरडी बस में गए.

एक बार...

सबके आराध्य हैं साई

चौथी दुनिया ब्यूरो

साई बाबा आज असंख्य लोगों के आराध्यदेव बन चुके हैं. साई को शरीर त्यागे हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उनका यश पूरे विश्व में फहरा रहा है. साई अपने भक्तों का आज भी मार्गदर्शन करते हैं. वे अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं और उनके हर संकट दूर करते हैं.

ऐसा माना जाता है कि साई पहली बार जब शिरडी में देखे गए थे. उस समय केवल साई 16 वर्ष के थे और वह स्वस्थ और अति सुन्दर बालक थे. साई नीम के पेड़ के नीचे समाधि में लीन रहते थे और उनको सर्दी हो या गर्मी कभी उसकी चिंता नहीं रहती थी. साई को इतनी कम उम्र में अति कठिन तपस्या करते देख लोगों को आश्चर्य हुआ. दिन में साई किसी से भेंट नहीं करते थे और रात को बिना किसी भय के एकांत में घूमते थे. गांव के लोग साई से पूछते थे कि वह कौन हैं और वह कहां से आए हैं?

साई के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग उनसे आकर्षित हो जाते थे. वह हमेशा ही नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और किसी के घर नहीं जाते थे.

साई उस समय एक नवयुवक थे, लेकिन वे साधु-संतों के तरह आचरण करते थे. साई त्याग और वैराग्य के साक्षात स्वरूप थे.

साई कुछ दिनों बाद किसी को कुछ बताए बिना शिरडी से चले गए. जब साई दोबारा शिरडी पहुंचे तो खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति ने उन्हें साई कहकर पुकारा था तब से ही उनका नाम साई बाबा पड़ गया. साई फिर वहां से वापस नहीं गए और हमेशा के लिए शिरडी में बस गए. साई का चमत्कार और उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई, उनको लोग शिरडी के साई बाबा कह कर पुकारने लगे.

साई ने अपने भक्तों के कष्टों का हमेशा निवारण किया और जो भी उनके पास आया, वह कभी भी निराश होकर नहीं गया. साई सबके प्रति एक भाव रखते थे और उनके यहां अमीर-गरीब, ऊंच-नीच, जात-पात, धर्म-मजहब का कोई भेदभाव नहीं था.

साई के पास सभी जाति-धर्म के लोग आते थे और वह बिना भेदभाव के सभी के कष्टों को दूर करते थे. साई नित्य भिक्षा मांगते थे और बहुत सादगी के साथ जीवनयापन करते थे. साई के भक्तों को उनमें सभी देवताओं के दर्शन होते थे. साई की प्रसिद्धि के कारण लोग उनसे इर्ष्या-द्वेष भी रखते थे और उनके खिलाफ कई षंडयत्र भी रचे.

साई सत्य, प्रेम, दया, करुणा की प्रतिमूर्ति थे. साई के निर्वाण के कुछ समय पहले एक शकुन हुआ, जो उनके समाधि लेने की पूर्व सूचना थी. साई के पास एक ईंट थी, जिसे वह अपने पास सदा रखते थे और वे उस पर हाथ टिका कर बैठते थे. रात में साई जब सोते थे तब उस ईंट को तकिए के जगह प्रयोग करते थे. एक बार दशहरे से कुछ दिन पूर्व एक भक्त द्वारा मस्जिद की सफाई करते समय उसके हाथ से ईंट गिरकर टूट गया. द्वारिकामाई में मौजूद सभी भक्त स्तब्ध रह गए. साई बाबा जब भिक्षा मांगकर आए तो जब टूटे हुए ईंट पर उनकी नजर पड़ी और वह मुस्कराकर बोले कि यह ईंट मेरी जीवनसंगिनी थी. साई बोले अब यह टूट गई तो समझ लो कि मेरा समय भी पूरा हो गया. साई तब से अपनी महासमाधि की तैयार करने में लग गए.

नागपुर के प्रसिद्ध धनी व्यक्ति बाबू साहिब बूटी साई बाबा के बड़े भक्त थे. उनके मन में एक बार साई बाबा को आराम से निवास करने के लिए शिरडी में एक अच्छा भवन बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई. साई ने बूटी साहिब को स्वप्न में एक मंदिर सहित बाड़ा बनाने का आदेश दिया तो उन्होंने तत्काल उसे बनवाना शुरू कर दिया. मंदिर में द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करने की योजना थी.

15 अक्टूबर, 1918 को विजया दशमी महापर्व के दिन सीमोल्लंघन करने की घोषणा की, तब उस समय लोग समझ नहीं पाए कि साई अपने महाप्रयाण का संकेत दे रहे हैं. महासमाधि के पहले साई ने अपनी प्रिय भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे को आशीर्वाद दिया और उसके साथ 9 सिक्के भी दिए. उसके बाद साई ने कहा कि उन्हें अब मस्जिद में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम लोग मुझे बूटी के पत्थर बाड़े में ले चलो, जहां मै सुखपूर्वक रहूंगा.

विक्रम संवत 1975 में विजयादशमी के दिन दोपहर के 2.30 बजे साई बाबा ने महासमाधि ले ली और तब बूटी साहब द्वारा बनवाए गए बाड़े में उनका समाधि स्थल बन गया. श्रीकृष्ण के विग्रह की जगह कालांतर में साई बाबा की मूर्ति स्थापित हुई.

महासमाधि लेने से पहले साई ने अपने भक्तों को यह आश्वासन दिया कि पंचतत्वों से निर्मित उनका शरीर इस धरती पर तो नहीं रहेगा, लेकिन उनकी समाधि भक्तों की रक्षा करेगी. साई बाबा के भक्त तब से अब तक साई के कथन का अनुभव करते चले आ रहे हैं. साई ने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अपने भक्तों को सदा अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया है और उनकी समाधिस्थल जागृत शक्ति स्थल बनी हुई है. साई बाबा आज भी अपने भक्तों को राह दिखाते हैं और भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं. साई ने जो उपदेश दिया है, उसमें संसार के सभी धर्मों का सार है. साई के दर से कभी कोई खाली नहीं जाता है और वह सभी के कष्टों को दूर करते हैं. ■

साई के ग्यारह वचन

- जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
- चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
- त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
- मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
- मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
- मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
- जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसे रूप हैं मेरे मन का.
- भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
- आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
- मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
- धन्य-धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

बीमारियों से बचना है तो खुश रहें

डॉ. अभय बंग

दिल्ली और मद्रास में किए गए 40 वर्ष से अधिक उम्र के मध्यवर्गीय पुरुषों पर सर्वेक्षण से पता चला है कि उनमें से प्रत्येक पांच व्यक्ति में से एक को मधुमेह और दस में से एक को हृदयरोग था. संसार के किसी भी देश की जनसंख्या में ये रोग इतने बड़े पैमाने पर नहीं हैं. 1970 के बाद भारतीय शहरों में अनेक सर्वेक्षण हुए, उनसे पता चला कि इन बीमारियों का अनुपात प्रत्येक दशक में बढ़ता ही जा रहा है और लोग कम आयु में हृदयरोग के शिकार हो रहे हैं. अब तो भारतीय पुरुष 30 से 40 वर्ष की आयु में मृत्यु के दरवाजे पर आ खड़ा होता है. लगभग 50 वर्ष पहले अमेरिका में भी हृदयरोग का ऐसा ही दौर आया था, जिसकी कई वजहे थीं. मसलन, दूसरे महायुद्ध के बाद की समृद्धि, जीवन स्तर में अचानक सुधार, खाने-पीने की बहुतायत और यंत्रों के कारण शारीरिक श्रम की आवश्यकता का अभाव. कार के कारण पैदल चलने की आवश्यकता नहीं रही. टीवी के सामने बैठकर मनोरंजन व विज्ञापन देखना कार से सुपर मार्केट जाकर टीवी पर विज्ञापनों में देखी हुई सारी वस्तुएं खरीद लाना और घर आकर फिर से टीवी के सामने बैठकर उन्हें खाते-पीते रहना. इस प्रकार की जीवनशैली के कारण 1950 से 1960 के दशक में अमेरिका में हृदयरोग का और उसके कारण होने वाली मृत्यु का परिणाम प्रचंड रूप से बढ़ गया था, पर बाद के 10-15 वर्षों में अमेरिकन नागरिकों ने इसके कारण खोज निकाले. धूम्रपान, आहार में प्राणिजन्य फैट की बहुतायत (दूध, मक्खन, चीज, अन्डे, मांस), खून में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ऊंचा रक्तचाप व बैठक वाली निष्क्रिय जीवनशैली, प्रमुख कारणों के रूप में उन्हें समझ में आए. बैठकवाली जीवनशैली खतरनाक है. ऑफिस, कुर्सी, ड्रॉइंग रूम, सोफा और बेडरूम, ये खतरनाक स्थान हैं, क्योंकि समृद्ध संसार के ज्यादातर लोग यहीं मरते हैं. ये सब बातें उनकी समझ में आ गईं और वहीं से उन्होंने अपनी जीवनशैली में परिवर्तन लाने के प्रयत्न शुरू कर दिए. अमेरिका में 40-50 वर्ष पूर्व जो हुआ. ठीक वही आज भारत में हो रहा है. एक बड़े समृद्ध वर्ग का भारत में उदय हो गया है. उच्च और मध्यम वर्ग मिलाकर भारत में आज करीब तीस करोड़ लोग हैं. यानी की दूसरा अमेरिका ही भारत में है. यह है भारत का अमेरिका, जो तेजी से अमेरिका की जीवनशैली, खाने-पीने की अधिकता, शारीरिक श्रम से मुक्ति, शराब और धूम्रपान वाली जीवनशैली अपना रहा है. आधुनिक जीवन में कार, टीवी, फ्रिज व होटल आदि को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है. इसके कारण बैठक वाली खाऊ-पीऊ जीवनशैली चल पड़ी है. इसके साथ ही बढ़ती हुई महात्वाकांक्षा और करियर की तीव्र स्पर्धा और दौड़-भाग के कारण मानसिक तनाव भी पश्चिम जैसा ही बढ़ता जा रहा है. अतः भारत में हृदयरोग का प्रभाव अचानक बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी कुछ कारण अविदित हैं. इस जीवनशैली को अंगीकार करने के बाद गोरों को जिस अनुपात में हृदयरोग होता है, उसकी अपेक्षा भारतीय व्यक्ति को कहीं अधिक अनुपात में होता है. भारत से जाकर लंदन, सिंगापुर, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका में बस गए हजारों कुटुम्ब हैं. ये ज्यादातर मध्यम या उच्च वर्ग के हैं. वहां की समृद्धि का उनकी जीवनशैली पर खूब असर हुआ है. समान जीवनशैली वाले इंग्लैंड के गोरे, काले और भारतीय लोगों का तुलनात्मक अध्यन जब कुछ चिकत्सकीय वैज्ञानिकों ने किया, तब पता चला कि वहां के भारतीय वंश के लोगों में मधुमेह और हृदयरोग का अनुपात अन्य वंशियों की तुलना में सर्वाधिक है. भारत के गांवो में रहते हुए भारतीयों को ये रोग नहीं थे. परन्तु समृद्ध पश्चिमी जीवनशैली अपनाते ही गोरे और काले लोगों की अपेक्षा भारतवंशी लोगों को यह रोग ज्यादा परिमाण में होते हैं. ऐसा ही चित्र सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा में भी उभरा और यही चित्र भारतीय शहरों में भी देखा गया. अतः चिकित्सा-क्षेत्र में यह निष्कर्ष निकाला गया कि कुछ आनुवंशिक अथवा जीवशास्त्रीय कारणों से भारतवंशी लोग मधुमेह व हृदयरोग का सबसे अधिक खतरा पाले हुए हैं. भारत में हृदयरोग की लहर का स्पष्टीकरण भारतवंशी लोगों की हृदयरोग के प्रति नैसर्गिक कमजोरी तथा मध्यम वर्ग की नवीन जीवन शैली में है. धन-दौलत या धन्धे की खींचतान के पीछे न भागकर आदिवासी गांवों में स्वास्थ्य सेवा तथा रिसर्च करने वाले, महत्वाकांक्षा एवं तनावरहित जीवन जीने वाले मुझ जैसे समाजसेवी को हृदयरोग क्यों हुआ?

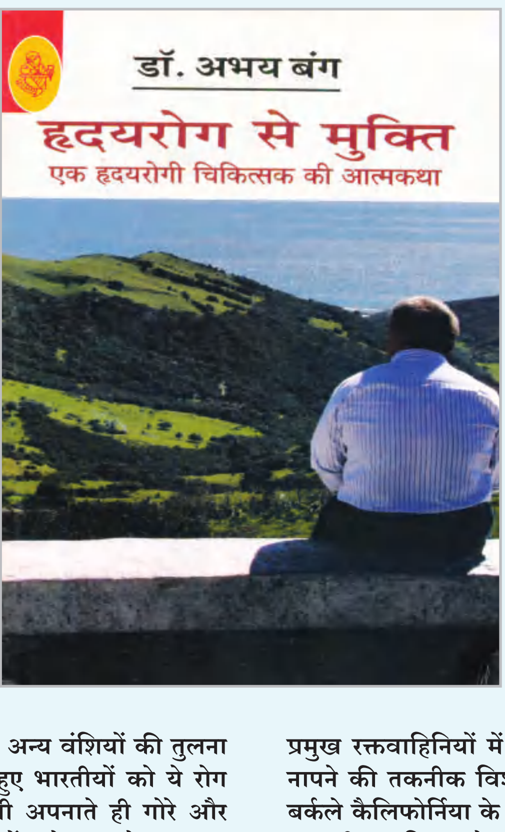

मेरे हार्टअटैक के कुछ दिन बाद डॉ. अवचट ने मेरी बीमारी में पढ़ने के लिए बर्नी सीगल नामक अमेरिकन सर्जन द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक लव मेडिसिन एंड मिराकल मुझे भिजवाई. शुद्ध इच्छाशक्ति व मानसिक प्रयोगों से कैंसर के उपचार विलक्षण अनुभवों का इसमें वर्णन है. सीगल कहते हैं कि हमारे मन का शरीर पर प्रचंड प्रभाव पड़ता है. कैंसर के अनेक रोगियों को रोग होने से पहले डिप्रेशन होता है. डिप्रेशन, चिंता, भय ये शरीर को नकारात्मक संकेत देते हैं. इस कारण शरीर की पेशियों की जीने की इच्छा व शक्ति कम हो जाती है. ऐसे समय में कैंसर तथा अन्य बड़े रोग शरीर को जकड़ लेते हैं, क्योंकि चिन्ताग्रस्त शरीर उन रोगों को बढ़ने देता है. उनसे लड़ने की शरीर में इच्छा ही नहीं बचती. बर्नी सीगल का यह प्रतिवादन मुझे संभव प्रतीत होता है. और हाल ही में एक अनुसंधान की रिपोर्ट पढ़ी. शरीर की प्रमुख रक्तवाहिनियों में निर्माण होने वाले अथरोस्किलरोसिस को नापने की तकनीक विशेषज्ञों ने विकसित की है. इस तकनीक से बर्कले कैलिफोर्निया के विशेषज्ञों ने विविध लोगों की रक्तवाहिनियों का परीक्षण किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि जो खिन्न है, जिसका मन प्रसन्न नहीं है, ऐसी मनः स्थिति वाले लोगों के शरीर की रक्तवाहिनी नलियां अन्दर से संकरी हो गई थीं. तो स्पष्ट है कि खिन्न मनःस्थिति भी हृदय रोग का कारण बनता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मेरे हार्टअटैक के कुछ दिन बाद डॉ. अवचट ने मेरी बीमारी में पढ़ने के लिए बर्नी सीगल नामक अमेरिकन सर्जन द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक लव मेडिसिन ऐंड मिराकल मुझे भिजवाई. शुद्ध इच्छाशक्ति व मानसिक प्रयोगों से कैंसर के उपचार और विलक्षण अनुभवों का इसमें वर्णन है. सीगल कहते हैं कि हमारे मन का शरीर पर प्रचंड प्रभाव पड़ता है. कैंसर के अनेक रोगियों को रोग होने से पहले डिप्रेशन होता है.

एक बार...

न्यायप्रिय राजा

एक राजा था. वह बेहद न्यायप्रिय, दयालु और विनम्र था. उसके तीन बेटे थे. राजा बूढ़ा हुआ तो उसने अपने बेटों को राज-गद्दी सौंपने का निर्णय किया. उसने तीनों की परीक्षा लेनी चाही. तीनों की परीक्षा लेने के लिए वह उन्हें अपने पास बुलाकर एक काम सौंपा और कहा कि आप सभी इस काम को अपने सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने की कोशिश करेंगे. राजा के कहने पर तीनों ने प्रसन्न होकर कार्य स्वीकार कर लिया. राजा ने उन तीनों को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दीं और कहा कि इन मुद्राओं से कोई ऐसी चीज खरीद कर लाओ, जिससे कि पूरा कमरा भर जाए और वह वस्तु काम में आने वाली भी हो. यह सुनकर तीनों राजकुमार स्वर्ण मुद्राएं लेकर अलग-अलग दिशाओं में चल पड़े. बड़े राजकुमार ने सोचा कि इसके लिए रूई उपयुक्त रहेगी और उसने उन स्वर्ण मुद्राओं से काफी सारी रूई खरीद कर कमरे में भर दी. मंझले राजकुमार ने ढेर सारी घास खरीदकर कमरा भर दिया. उधर, छोटे राजकुमार ने तीन दीये खरीदे. उसने क्रमशः पहला दीया कमरे में जलाया, जिससे कमरे में रोशनी फैल गई. दूसरा दीया अंधेरे चौराहे पर रख दिया, जिससे वहां भी रोशनी हो गई और तीसरा दीया उसने अंधेरी चौखट पर रख दिया, जिससे वह जगह भी जगमगा उठा. बची हुई स्वर्ण मुद्राओं से उसने गरीबों को भोजन करा दिया. राजा ने तीनों राजकुमारों की वस्तुओं का निरीक्षण किया. अंत में छोटे राजकुमार के सूझबूझ भरे निर्णय को देखकर वह बेहद प्रभावित हुआ और उसे ही राजगद्दी सौंप दी.

शिक्षा : व्यक्ति की योग्यता उसके जनहित कार्यों से आंकी जाती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अभिव्यक्ति पर हमला

सुष्मिता बनर्जी प्रगतिशील विचारों वाली साहसी महिला थीं. उन्होंने अफगानिस्तानी कारोबारी जांबाज खान से शादी की थी और वहीं बस गई थीं. अफगानिस्तान में सैयदा कमाला के नाम से जानी जाने वाली सुष्मिता एक स्वास्थ्यकर्मी के रूप में काम कर रही थीं और वहां की महिलाओं की ज़िंदगी पर फिल्में बना रही थीं.

स्यापा नहीं पहल की ज़रूरत

यह बात लंबे समय से कही जाती रही है कि हिंदी में पाठकों की कमी है. साहित्य अकादमी में हिंदी भाषा से पहली बार अध्यक्ष बने विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को भी इस बात का दुख है कि हिंदी में पाठकों का टोटा है. सवाल यह है कि जब हिंदी का कोई प्रतिनिधि साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बना है, क्या कोई ऐसा प्रयास किया जाएगा कि हिंदी में साहित्यप्रेमियों की संख्या बढ़े? इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि क्यों प्रकाशक कविता-कहानी-उपन्यास छापना ही नहीं चाहते.

अनंत विजय

साहित्य अकादमी के इतिहास में पहली बार हिंदी भाषा से अध्यक्ष बने विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को इस बात का दुख है कि हिंदी में पाठकों की संख्या बेहद कम है, जबकि अन्य भाषाओं में पाठक बड़ी तादाद में मौजूद हैं. उन्हें इस बात का भी मलाल है कि हिंदी प्रदेशों में बंगाल, महाराष्ट्र और केरल जैसा साहित्यक माहौल नहीं बन पाया. साहित्य अकादमी का अध्यक्ष अगर इस तरह के बयान देता है तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है. इस वजह से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के पाठकों की कमी के विलाप पर विचार होना चाहिए और इसकी पड़ताल भी होनी चाहिए. साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जब हिंदी में पाठकों की कमी की बात कर रहे हों तो उनके अवचेतन मन में साहित्य के पाठकों की बात रही होगी. उनकी यह आशंका बिल्कुल ठीक है कि हिंदी में साहित्य के पाठक कम हुए हैं. यह बात हिंदी के तमाम प्रकाशक भी मानते हैं कि कविता-कहानी-उपन्यास के पाठक कम हुए हैं. आलोचना के पाठक तो पहले ही कम थे. साहित्येत्तर विषयों की किताबें धड़ाधड़ बिक रही है. हिंदी के कई शीर्ष प्रकाशकों ने तो साहित्य छापना ही कम कर दिया है. साहित्य अकादमी के अध्यक्ष होने के नाते विश्वनाथ तिवारी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे हिंदी साहित्य के नये पाठक वर्ग के निर्माण में अकादमी के मंच का इस्तेमाल करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं.

पाठकों तक पहुंचने का काम साहित्य अकादमी कर भी रही है. लेकिन अभी तक इस तरह के जो भी काम हो रहे हैं, वे सिर्फ रस्म अदायगी के तौर पर हो रहे हैं. अकादमी लेखकों से मिलिए-जैसे जो भी कार्यक्रम आयोजित करती है, वह लेखकों से मिलिए कम, अकादमी के कर्मचारियों का गेट-टुगेदर ज्यादा होता है. दिल्ली के रवींद्र भवन में आयोजित इस तरह के कार्यक्रमों में वही-वही चेहरे नजर आते हैं जो कभी भी आपको साहित्य अकादमी में दिख जाते हैं. साहित्य अकदामी का जब गठन हुआ था तो उसका उद्देश्य था कि सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की समृद्ध परंपरा और विरासत का एक साझा मंच बने, जहां साहित्य पर गंभीर विचार-विनिमय और विमर्श हो सके. साहित्य अकादमी के गठन के पीछे एक भावना यह भी थी कि अकादमी सेमिनार, सिंपोजिया, कांफ्रेंस और अन्य माध्यमों से एक दूसरे भाषा के बीच संवाद स्थापित करेगी. यह सारी चीजें साहित्य अकादमी कर रही है, लेकिन करने के तरीके में घनघोर मनमानी और अपनों को उपकृत करने का काम हो रहा है. अपने गठन के दशकों बाद साहित्य

अकादमी अपने इस उद्देश्य से भटकती नजर आ रही है. सत्तर के शुरुआती दशक से ही अकादमी मठाधीशों के कब्जे में चली गई और वहां इस तरह की आपसी समझ बनी कि हर भाषा के संयोजक अपनी-अपनी भाषा की रियासत के राजा बन बैठे. साझा मंच की बजाए यह स्वार्थसिद्धि का मंच बनता चला गया. अब से कुछ सालों पहले तक अकादमी पर वामपंथी विचारधारा का कब्जा था और यह बात जगजाहिर है कि वामपंथियों ने किस तरह अपनी विचारधारा वाले लेखकों को आगे बढ़ाया और विरोधियों को निबटाया. वामपंथी विचारधारा के लेखकों के कमजोर होने के बाद एक खास किस्म के अवसारवादी लेखकों का कब्जा अकादमी पर हो गया जो प्रतिभाशाली लेखकों से आक्रांत रहते थे, लिहाजा उन्होंने एक ऐसी व्यूह रचना रची कि प्रतिभाशाली लेखक अकादमी के अंदर नहीं आ पाएं. आमसभा से लेकर हर जगह प्रतिभा को रोकने का षडयंत्र शुरू हो गया. रचनात्क लेखकों के बजाय विश्वविद्यालयों के बुजुर्गों का क्लब बनता चला गया. उदाहरण के तौर पर हिंदी के वरिष्ठ लेखक उपन्यासकार रवींद्र कालिया को लेकर साहित्य अकादमी ने अबतक कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया, जबकि कालिया सालों से दिल्ली में रह रहे हैं. जबकि हिंदी के कई प्रतिभाहीन लेखकों को साहित्य अकादमी ने मंच मुहैया करवाया. सवाल यह उठता है कि जबतक पाठकों के सामने किसी भी भाषा का सर्वश्रेष्ठ लेखक और उसका लेखन नहीं आएगा, तब तक हमें पाठकों की कमी का रोना रोते रहना पड़ेगा. कमलेश्वर जी को भी अकादमी पुरस्कार तब तक नहीं मिल पाया, जबतक कि डील नहीं हो गई. राजेंद्र यादव को तो अबतक नहीं मिल पाया है. अकादमी की इस मठाधीशी का फायदा अफसरों ने भी उठाया और वे लेखकों पर हावी होते चले गए. अकादमी के पूर्व सचिव पर जांच भी चल रही थी, इस बीच वे रिटायर हो गए. जांच के नतीजे का पता नहीं.

इसके अलावा हिंदी में एक और समस्या है, जिसकी वजह से पाठकों की संख्या का आकलन होना मुमकिन नहीं है. वह है हिंदी में किताबों की बिक्री का सही आंकड़ा सामने नहीं आ पाना. कई बार यह सवाल उठा है कि हिंदी के प्रकाशक लेखकों को उनकी किताबों की बिक्री का सही आंकड़ा नहीं बताते हैं. प्रकाशकों का दावा यह होता है कि किताबें बिकती ही नहीं हैं. साहित्य अकादमी के पचास साल पूरे होने के मौके पर उस वक्त के अकादमी अध्यक्ष गोपीचंद नारंग ने अकादमी की स्वयत्तता को लेकर जवाहरलाल नेहरू का एक वक्तव्य उद्धृत किया था. लेकिन अकादमी जवाहरलाल नेहरू के 13 मार्च, 1954 के उस पत्र को भूल गई, जिसमें उन्होंने हिंदी प्रकाशन की दशा और दिशा की ओर इशारा किया था. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बदहाली के मद्देनजर उनके लिए मासिक धन की योजना बनाने के बाबत नेहरू जी ने साहित्य अकादमी के तत्कालीन सचिन कृष्ण कृपलानी को एक पत्र लिखा था. उस पत्र में उन्होंने लिखा कि निराला की किताबें जमकर बिक रही हैं और प्रकाशक मालामाल हो रहे हैं, लेकिन निराला को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है और वे लगभग भुखमरी की कगार पर हैं. अपने उस पत्र में नेहरू जी ने कृपलानी से कॉपीराइट एक्ट को दुरुस्त करवाने के लिए कोशिश करने का भी आग्रह किया था. लेकिन अकादमी ने नेहरू जी के उस पत्र से कोई सीख नहीं ली. अबतक अकादमी ने इस दिशा में कोई पहल या काम किया हो, ज्ञात नहीं है. हिंदी में अबतक लेखकों प्रकाशकों के बीच का अनुबंध पत्र का भी मानकीकरण नहीं हो पाया है. किताबों की बिक्री के आंकड़ों के लिए कोई मैकेनिज्म बनाने का भी प्रयास नहीं हो पाया है. जब साहित्यक किताबों की बिक्री जानने की कोई व्यवस्था ही नहीं बन पाई है तो पाठकों की संख्या का पता कैसे चल पाएगा. इस बार के साहित्य अकादमी की आम सभा में हिंदी प्रकाशन जगत का एक नुमाइंदा भी चुना गया है. अकादमी का अध्यक्ष भी हिंदी का ही है. अपेक्षा इस बात की है कि बजाय पाठकों की कमी का स्यापा करने के इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं. साहित्य अकादमी के कार्यक्रमों को भाषा के संयोजकों के चंगुल के मुक्त करना होगा और कार्यक्रमों के आयोजन में पूर्वग्रहों से ऊपर उठकर लेखकों और साहित्यप्रेमियों की भागीदारी बढ़ानी होगी. अगर ऐसा हो पाता है तो साहित्य के पाठकों का एक नया वर्ग संस्कारित होगा और अखबारों के पाठकों की तरह साहित्य के पाठकों में भी इजाफा होगा. यह सब कर पाना तिवारी जी के लिए बड़ी चुनौती है. अगर वे इन दोनों काम को कर पाने में सफल हो जाते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, वर्ना अन्य अकादमी अध्यक्षों की तरह वे भी इतिहास के बियाबान में गुम हो जाएंगे और हिंदी साहित्य में पाठकों की कमी का स्यापा होता रहेगा. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं.)

anant.ibn@gmail.com

कविता

अनगढ़ मिट्टी

अनिन्ध्या तोगडे

अनगढ़ मिट्टी
समेटे होती है
ढेरों संभावनाएं
अनंत सामर्थ्य

कोई एक आकर यदि
मिट्टी धर ले जो
तो वह विवश हो जाएगी
परिभाषा होने के लिए
सीमित हो जाएगी
मिट्टी मूरत होने के लिए

किसी विषय
किसी नियम से परे
कण-कण होकर भी मिट्टी
कर लेती है काज
धन्य धरा को करने का

कैसा अच्छा लगता है न
मिट्टी जैसे लोगों की
सोहबत में आना
वहां निश्छल प्रेम की बूंदें गिरें तो
खुशबू आने लगती है
एक बीज के बदले
फलों से लदकद पेड़ मिल जाता है

मूरत के इस युग में
कुछ बन जाने की होड़ में
डूबी-डूबी दुनिया में
कुछ आज़ाद कणों से
रूबरू होना
मिट्टी होना लगता है...

अभिव्यक्ति पर हमला

कृष्णकांत

बोलने की आज़ादी पर बढ़ते ख़तरे

एशियाई देशों में कट्टरपंथी संगठनों द्वारा लेखकों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़ रहे हैं. अफगानिस्तान में भारतीय लेखिका सुष्मिता बनर्जी की हत्या इसी सिलसिले की एक कड़ी है. आतंकी, तालिबानी, कट्टरपंथी संगठन और यहां तक की सरकारें भी अपनी जायज आलोचना बरदाश्त नहीं करती हैं. अन्याय के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है. बढ़ती संकीर्णता और असिष्णुता के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करने की जरूरत है.

अन्याय के खिलाफ एक और आवाज को दबा दिया गया. यह आवाज थी अफगानिस्तान में रह रहीं भारतीय लेखिका सुष्मिता बनर्जी. बनर्जी की हत्या ने अभिव्यक्ति और न्याय के पक्ष में खड़े लोगों पर आसन्न खतरे के सवालों को पुन: उठाने पर विवश किया है. बनर्जी की हत्या कोई पहला घटना नहीं है. ऐशियाई देशों में, खासकर, भारत, पाकिस्तान, बाग्लांदेश और अफगानिस्तान में लेखकों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हाल में हमले बढ़े हैं. आतंकी, तालिबानी, कट्टरपंथी संगठन और यहां तक की सरकारें भी अपनी जायज आलोचना बरदाश्त नहीं करती हैं. उनके द्वारा बरते जा रहे अन्याय के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को वे दबा देना चाहते हैं. आज जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र, वैयक्तिक स्वतंत्रता और बोलने की आजादी के स्वर बुलंद हो रहे हैं, इस तरह न्यायप्रिय आवाजों को दबाने की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं. आज कट्टरता और अलोकतांत्रिक कृत्यों के खिलाफ एकजुट होकर इससे निपटने के सवाल हमारे सामने फिर से जीवंत हो उठे हैं. हालांकि, तालिबान ने सुष्मिता की करने से इन्कार करते हुए कहा कि हमें बदनाम किया जा रहा है. लेखिका की हत्या में तालिबान शामिल नहीं हैं. लेकिन तालिबान ऐसी गतिविधियों को लगातार अंजाम देते रहे हैं. इसने पहले भी फरमान नहीं मानने वाली महिलाओं की हत्या की है. हाल ही में पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई को गोली मारी गई थी. वह भी महज इसलिए कि वह अपनी हमउम्र बच्चियों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर रही थी.

सुष्मिता बनर्जी प्रगतिशील विचारों वाली साहसी महिला थीं. उन्होंने अफगानिस्तानी कारोबारी जांबाज खान से शादी की थी और वहीं बस गई थीं. अफगानिस्तान में सैयदा कमाला के नाम से जानी जाने वाली सुष्मिता एक स्वास्थ्यकर्मी के रूप में काम कर रही थीं और वहां की महिलाओं की जिंदगी पर फिल्में बना रही थीं. सुष्मिता ने काबुलीवालार बंगाली बोउ (काबुलीवाले की बंगाली पत्नी) नाम से किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में पति के साथ अपनी रहनवारी और तालिबान से बचने की कहानी लिखी थी. यह किताब 1995 में आई थी. 2003 में इस पर आधारित एस्केप फ्राम तालिबान नाम से एक फिल्म भी बनी. किताब में उन्होंने तालिबान से बचकर भागने और पकड़े जाने और फिर बचने की लंबी जद्दोजहद की कहानी लिखी थी. सुष्मिता 1989 में खान से शादी करके अफगानिस्तान गईं थीं. बाद में उन्होंने एक पत्रिका में लिखा कि 1993 तक उनकी जिंदगी सुचारु चल रही थी. इसके बाद तालिबान सत्ता पर काबिज हुए और उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई. बनर्जी की हत्या के पहले तालिबान ने उन्हें कमजोर नैतिकता वाली महिला होने का आरोप लगाते हुए उनका दवाखाना बंद करने का फरमान सुनाया था. हाल ही में भारत से फिर अफगानिस्तान लौटी थीं और स्वास्थ्यसेवा संबंधी

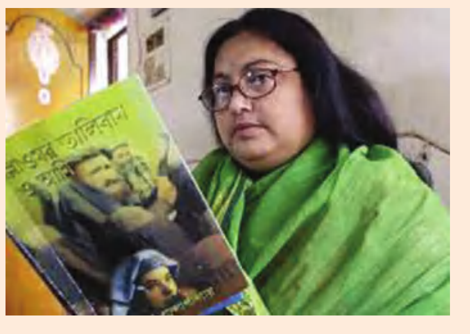

अपना काम दोबारा शुरू किया था. अफगानिस्तानी पुलिस के अनुसार पिछले बुधवार की रात उनके परिजनों को बंधक बनाकर कुछ नकाबपोश बंदूकधारियों ने उन्हें घर से बाहर निकाला और गोलियों से छलनी कर दिया।

सुष्मिता की हत्या पूरे एशिया में मानवाधिकार, लोकतंत्र और आजादी पर बढ़ रहे हमले का एक उदाहरण है. इस हत्या ने सांप्रदायिक ताकतों और उनको शह देने वाली सरकारों के खिलाफ उठ खड़े होने की आवश्यकता को एक बार फिर से प्रासंगिक बना दिया है. एक तरफ मध्यपूर्व के कई देशों में सरकारों के खिलाफ जनांदोलन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कट्टर सांप्रदायिक शक्तियां अपनी सत्ता कायम रखने की कोशिशों में लगी हुई हैं. पूरे भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिण एशिया में भी ऐसी कट्टर ताकतें सक्रिय हैं. बांग्ला लेखिका तस्लीमा नसरीन को लगातार मौत की धमकियों के बीच इस देश से उस देश भटकना पड़ रहा है. बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरपंथियों के खिलाफ उभरे जनांदोलन में साथ देने वाले एक युवक ब्लॉगर की भी हत्या कर दी गई. आस्ट्रेलियाई ईसाई मिशनरी के फादर स्टोंस की भारत में ही हत्या हुई. 20 अगस्त को अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी गई. भारत में इस तरह की असहिष्णु हरकतें बार-बार हो रही हैं. शिवसेना के पूर्व प्रमुख बाल ठाकरे की मौत के बाद मुंबई बंद को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी करने वाली लड़की और उसे लाइक करने वाली उसकी दोस्त की गिरफ्तारी, कार्टून बनाने को लेकर असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी, ममता का कार्टून बनाने वाले प्रोफेसर की गिरफ्तारी, हाल में सरकार की विफलता को लेकर टिप्पणी करने को लेकर लेखक कंवल भारती की गिरफ्तारी आदि इसके उदाहरण हैं.

हाल ही में दुष्कर्म के आरोप में जेल गए आसाराम बापू के समर्थकों ने लगभग हर शहर में पत्रकारों पर हमले किए. इस तरह की सांप्रदायिक और धार्मिक कठमुल्लापन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आज व्यापक स्तर पर जनचेतना को जागृत करने की जरूरत है. ■

feedback@chauthiduniya.com

असल में एशियाई समुदाय संकीर्णता में जकड़े हुए हैं, इसलिए वे यह नहीं सोच पाते कि लेखक, रचनाकार आदि हमारे समाज के जरूरी स्तंभ हैं. बुद्धिजीवियों से कट्टरपंथियों को खतरा महसूस होता है, क्योंकि इनकी वजह से उनके संकीर्ण उद्देश्यों में बाधा खड़ी होती है. अंध धार्मिक मतों वाले लोग अंधेरी दुनिया में रहते हैं. वे न किसी धर्म यकीन रखते हैं, न ही किसी आस्था में. वे निर्दोष और निहत्थे बुद्धिजीवियों को निशाना बनाते हैं. यह बहुत खतरनाक है. समाज में इतनी उदारता होनी चाहिए कि इस तरह मत-मतांतरों की लड़ाई को लेकर हत्याएं न की जाएं. दूसरी चीज कि हमें अंधभक्तों, अंधश्रद्धा वाले लोगों को तवज्जो देना बंद करना चाहिए.
-गंगा प्रसाद विमल, साहित्यकार

जब कभी, जहां कहीं सर्वसत्तावादी शक्तियां प्रभुत्व में आती हैं, हर स्वतंत्र लेखक, बुद्धिजीवी खतरों में घिर जाता है. कहावत है कि जब धार्मिक सत्ता कायम होती है तो सबसे अधिक सूफी और सच्चे संत मारे जाते हैं. जब समाज में उग्र, हिंसक अस्मितावादी, राजनीतिक या धार्मिक-जाति-वर्णवादी तत्त्व अति-सक्रिय होते हैं और सब कुछ उनके इशारों पर चलने लगता है, यह खतरा और बढ़ जाता है. दक्षिण एशियाई देशों में उग्रवादी, प्रतिगामी, कट्टर जाति-धर्म के तत्व ही राजनीति और भाषा-संस्कृति का संचालन करते हैं. जिस राजस्थान में अमिताव कुमार जैसे प्रतिष्ठित लेखक को गिरफ्तारी से बचने को भागना पड़ता है, आशीष नंदी के महज़ एक वाक्य के लिए पुलिस गिरफ्तारी को फ़ौरन हाज़िर हो जाती है, उसी राजस्थान में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न पर आसाराम नामक अपराधी को पुलिस ऍफ़आईआर दर्ज कर 6 दिन तक छूती नहीं. लेखक-विचारक कंवल भारती को फेसबुक टिप्पणी पर गिरफ्तार कर लिया गया. अभी परसों ही हेनरी जेरो ने लिखा है कि नब्बे के दशक के बाद से जिस कारपोरेट पूंजी तंत्र का प्रभाव सारी दुनिया में बढ़ा है, उसमें बुद्धिजीवी ही उसका शिकार (आब्जेक्ट) और शिकारी (सब्जेक्ट) है. वही कर्ता और भोक्ता है. वे तथाकथित बुद्धिजीवी, जो शासन-प्रशासन की कृपा पर आश्रित हैं, वे यह समझने में असमर्थ हैं कि उनके द्वारा ऐसे कितने लेखकों-कलाकारों, बुद्धिजीवियों का जीवन संकट में घेर दिया गया है, जो स्वतंत्रता के साथ लिखते और सोचते हैं. उदहारण सिर्फ मकबूल फ़िदा हुसैन, तसलीमा नसरीन या रश्दी ही नहीं हैं, जिन्हें जलावतनी का दुःख झेलना पड़ा. बहुत से लेखक-बुद्धिजीवी आतंरिक जलावतनी में हैं. कहते हैं की इस नयी उदारवादी अर्थनीति ने समाज से मध्यवर्ग को चालाकी से नव-धनाढ्य वर्ग में बदल दिया और फिर उन सबको उनकी कट्टर लघु अस्मिताओं में, ऐसे समय में हर वह लेखक और बुद्धिजीवी असंख्य संकटों, अवमानानाओं, प्रताड़नाओं से घिरा हुआ है. हम सब एक भयावह पोलराइज्ड सामाजिक समय में रह रहे हैं. ***-उदय प्रकाश, साहित्यकार***

परंपरागत स्मार्टवॉच की तरह दिखने वाली निसान निस्मो चालक के दिल की धड़कन, तापमान और शरीर से जुड़ी दूसरी गतिविधियों पर निगरानी रखने में सक्षम है. साथ ही यह स्मार्टवॉच कार की औसत रफ्तार और ईंधन खपत पर नजर रखने में भी चालक की मदद करती है.

आसुस का स्टाइलिश फोनपैड

आसुस ने अपना फोनपैड नोट 6 पेश किया है. देखने में यह काफी स्टाइलिश है. यह 367 पीपीआई (पिक्सल/ईंच) का है. इसकी खास खुबियां हैं 1080-1920 पिक्सल्स रिजॉल्यूशन वाला 6 ईंच का फुल-एचडी सुपर आईपीएस+ डिस्प्ले. इसमें हाइपर-थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी वाला इंटेल ऐटम एन2580 ड्यूल-कोर प्रोसेसर और 2 जीबी रैम है. पीछे की तरफ फुल-एचडी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए 8 मेगापिक्सल्स का ऑटो-फोकस कैमरा भी इसमें दिया गया है. फ्रंट कैमरा 1.2 मेगापिक्सल्स का है. यह ऐंड्रॉयड 4.2 जेली बीन पर काम करता है. इसमें 16 और 32 जीबी स्टोरेज के ऑप्शंस हैं. कनेक्टिविटी ऑप्शंस के लिए इसमें वाई-फाई, ब्लूटुथ, एज, जीपीआरएस और 3जी शामिल हैं. इसमें 3200 एमएच की बैटरी लगी है. सिम कार्ड लगाकर इससे वॉइस कॉल की जा सकती है. यह फोनपैड 23 घंटे तक का टॉकटाइम और 6.5 घंटे तक का एचडी वीडियो प्लेबैक देगा. यह डिवाइस काले और सफेद दो रंगों में उपलब्ध है. ■

भारतीय सड़कों पर दौड़ेगी हार्ले डेविडसन

हार्ले डेविडसन, भारत में अपनी नई बाइक 500 सीसी को उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है. हाल ही में यहां के सड़कों पर इस बाइक की टेस्ट ड्राइव भी किया गया. हार्ले डेविडन ने अगस्त, 2009 में भारत में अपनी बाइक्स उतारी थी.

ज्यादातर बाइकर्स की पहली पसंद हार्ले डेविडसन ही होती है, ताकि इस बाइक पर बैठकर वे हवा से बातें करें, लेकिन आसमान छूने वाली कीमतों के कारण यह बाइक प्रेमियों के लिए सिर्फ चाहत बन कर रह जाती है. बाइक प्रेमियों की चाहत को देखते हुए कंपनी भारत में सबसे सस्ती हार्ले डेविडसन की शानदार बाइक लॉन्च कर रही है. हार्ले डेविडसन, भारत में 500 सीसी की बाइक उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है. हाल ही में देश की सड़कों पर इस नई बाइक की टेस्ट ड्राइव भी हो चुकी है. हार्ले डेविडन ने अगस्त, 2009 को भारत में अपनी बाइक्स उतारी थी. अभी तक देश में हार्ले डेविडसन की 883 सीसी बाइक मौजूद है. आज भारत में हार्ले डेविडसन के कई मॉडल्स मौजूद हैं. कंपनी को यहां अच्छी कामयाबी मिली है. कंपनी की 500 सीसी बाइक की कीमत अन्य बाइक्स की तुलना में काफी कम होगी. ऑटो कार इंडिया के अनुसार, इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपये से शुरू होगी. हार्ले ने 2009 में भारत में अपना बिजनेस शुरू किया था. यह अब तक 10 डीलरशिप के जरिये 2,000 से ज्यादा बाइक बेच चुकी है. कंपनी के दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में डीलर्स हैं. यह भारत में 13 मॉडल बेचती है, जिनकी कीमत 5 लाख रुपये से शुरू होती है. ■

सोनी का सुपरफास्ट मोबाइल

कमियां

फ्लैश नहीं.
कैमरे का परफॉर्मेंस ऐवरेज.
साइज काफी बड़ा.

खूबियां

शानदार डिस्प्ले
बैटरी बैकअप बेहतरीन
परफॉर्मेंस सुपरफास्ट

सोनी एक्सपीरिया ज़ेड अल्ट्रा में 2.2 गीगाहर्ट्ज क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 800 क्वॉड कोर प्रोसेसर लगा है. इसमें एड्रिनो 330 जीपीयू का है, जो 4 के कॉन्टेंट को सपोर्ट करता है. इसका डायमेंशन 6.5 मिलीमीटर है. डिस्प्ले काफी बड़ा है, जिससे इसे एक हाथ से इस्तेमाल करना अनकंफर्टेबल सा लगता है.

इसे हाथ में लेकर चलना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो बड़े स्क्रीन वाले फोन इस्तेमाल करते हैं, उनको यह पसंद आएगा. यह आईपी58 सर्टिफाइड वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंट है. इसके 6.4 ईंच के डिस्प्ले के लिए सोनी की ट्राइलुमिनस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है. इस तकनीक का इस्तेमाल सोनी ब्राविया टीवी में भी करती है. इसका डिस्प्ले पिनशार्प डीटेल के साथ चटख रंग दिखाता है. डिस्प्ले का दूसरा दिलचस्प फीचर यह है कि इस पर पेंसिल और पेन से ड्रॉइंग भी की जा सकती है. इसका कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, लेकिन एलईडी फ्लैश लाइट नहीं है, जिससे कम रोशनी में ठीक फोटो नहीं लिया जा सकता. इसकी 3050 एमएच बैटरी की लाइफ बहुत बढ़िया है. ■

तेंदुलकर ने लॉन्च की बीएमडब्ल्यू की नई सीरीज

लग्जरी कार बनाने वाली जर्मन कंपनी बीएमडब्ल्यू ने भारत में लग्जरी कॉम्पैक्ट कार सेक्शन में कदम रखते हुए एक नई सीरीज पेश की. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इस कार को लॉन्च किया, जिसकी कीमत 20.90 लाख रुपये से 29.90 लाख रुपये के बीच है. बीएमडब्ल्यू-1 सीरीज पेट्रोल (बीएमडब्ल्यू 11 एसआई) और डीजल मॉडल (बीएमडब्ल्यू 118डी, 118 डी स्पोर्ट्स व 118डी स्पोर्ट्स प्लस) में उपलब्ध है. तेंदुलकर के साथ रेस कार ड्राइवर अरमान इब्राहिम भी स्टेज पर नजर आए. तेंदुलकर द्वारा पेश की गई नई बीएमडब्ल्यू कारों का मैनुफैक्चर, कंपनी के चेन्नई प्लांट में किया जाएगा. कंपनी अपने चेन्नई कारखाने में इस साल के अंत तक निवेश बढ़ाकर 390 करोड़ रुपये करेगी. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बीएमडब्ल्यू-1 सीरीज को सचिन तेंदुलकर ने लॉन्च किया. इसकी कीमत 20.90 लाख रुपये से 29.90 लाख रुपये के बीच है. बीएमडब्ल्यू-1 सीरीज पेट्रोल (बीएमडब्ल्यू 11 एसआई) और डीजल मॉडल (बीएमडब्ल्यू 118डी, 118 डी स्पोर्ट्स व 118डी स्पोर्ट्स प्लस) में उपलब्ध है.

स्मार्टवॉच बनाए ड्राइविंग आसान

तकनीक की दुनिया में स्मार्टवॉच पर कंपनियां काफी तेजी से काम कर रही हैं. सैमसंग और क्वालकॉम के बाद कार बनाने वाली कंपनी निसान ने भी स्मार्टवॉच बाजार में उतारी है, जो कार के साथ-साथ चालक की सेहत पर भी नजर रखती है. परंपरागत स्मार्टवॉच की तरह दिखने वाली निसान निस्मो चालक के दिल की धड़कन, तापमान और शरीर से जुड़ी दूसरी गतिविधियों पर निगरानी रखने में सक्षम है. साथ ही यह स्मार्टवॉच कार की औसत रफ्तार और ईंधन खपत पर नजर रखने में भी चालक की मदद करती है. विशेषज्ञों का कहना है कि कार में कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है. दरअसल, अब कार निर्माताओं का जोर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर है. निसान ने इस मामले में बाजी मार ली है और दोनों को एक साथ मिला लिया है. निस्मो वॉच को कार में मौजूद कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा जा सकता है, ताकि कार के टेलीमैट्रिक्स और परफॉर्मेंस डेटा पर नजर रखी जा सके. साथ ही निस्मो का इस्तेमाल करने वाले इस गैजेट के जरिये निसान से संदेश हासिल कर सकते हैं. माना जा रहा है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स फर्मों की तुलना में कार कनेक्टेड घड़ियां ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं. इसकी खास विशेषता यह है कि यह सर्दी के दिनों में भी कार में बैठने से पहले ही कार को गर्म रखेगा. निसान लीफ इलेक्ट्रिक कार में पहले ही चालक को मोबाइल फोन के जरिये कनेक्ट होने की सुविधा मौजूद है और कंपनी की अगली पीढ़ी की घड़ियों में यह सुविधा उपलब्ध रहेगी. कंपनी की योजना आनेवाले दिनों में ऐसी घड़ियां बनाने की है, जो चालक की थकान, उसके ध्यान के स्तर, भावनाओं और हाइड्रेशन स्तर का पता लगा सकेंगी. निस्मो तीन रंगों में मिल सकती है और इसकी बैटरी एक हफ्ते तक चल सकती है. इसे स्क्रीन पर लगे दो बटनों से नियंत्रित किया जा सकता है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

जीत के बाद पेस ने कहा कि उम्र तो महज एक आंकड़ा है, जिसे देखकर मैं मुस्कुराता हूं. उनकी यह जीत उन लोगों के लिए एक संदेश है, जो महज उम्र को पैमाना मानकर खिलाड़ियों की अनदेखी कर देते हैं. इस तरह की उपलब्धि केवल शारीरिक सुदृढ़ता की वजह से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए मानसिक सुदृढ़ता भी जरूरी होती है. भारत में बढ़ती उम्र के साथ खिलाड़ियों को चुका हुआ मान लिया जाता है और उन पर सन्यास लेने का दबाव डाला जाता है.

उम्र तो महज़ एक आंकड़ा है...

नवीन चौहान

लिएंडर पेस ने इस साल के यूएस ओपन का पुरुष युगल खिताब जीतने के साथ ही एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. पेस इस जीत के साथ सबसे अधिक उम्र में ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. पेस ने यह कारनामा उम्र के चालीसवें पड़ाव पर पहुंच कर दिखाया. इस जीत के बाद पेस ने कहा कि उम्र तो महज एक आंकड़ा है, जिसे देख कर मैं मुस्कुराता हूं. उनकी यह जीत उन लोगों के लिए एक संदेश है, जो महज उम्र को पैमाना मानकर खिलाड़ियों की अनदेखी कर देते हैं. इस तरह की उपलब्धि केवल शारीरिक सुदृढ़ता की वजह से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए मानसिक दृढ़ता भी जरूरी होती है. भारत में बढ़ती उम्र के साथ खिलाड़ियों को चुका हुआ मान लिया जाता है और उन पर सन्यास लेने का दबाव डाला जाता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर, लिएंडर पेस, महेश भूपति और विश्वनाथन आनंद जैसे खिलाड़ियों ने उम्र के इस पैमाने को अर्थहीन साबित कर दिया है. यदि कोई खिलाड़ी शारीरिक और मानसिक रूप से विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं में अपने खेल के स्तर को बरकरार रख सकता है और वह किसी भी विश्वस्तरीय प्रतियोगिता में सफलता हासिल कर सकता है तो वह युवा है. सफलता जज़्बे और मेहनत से मिलती है. सफलता कोई संयोग नहीं होती. दुनिया उम्र को धता बताकर नये-नये कारनामे करने वाले खिलाड़ियों से भरी पड़ी है. आइए, ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों पर नज़र डालते हैं. ■

सर डॉन ब्रैडमैन

क्रिकेट की दुनिया के सबसे सफल और महान खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन ने 19 साल की उम्र में टेस्ट में पदार्पण किया था. वह 20 साल तक टेस्ट खेलते रहे. उन्होंने 39 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 100वां शतक लगाया था. वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बने थे. ब्रैडमैन ने 52 टेस्ट मैचों में 99.94 की औसत से 6996 रन बनाए और कुल 29 शतक लगाए. ब्रैडमैन ने अपने करियर का आखिरी शतक 1948 में इंग्लैड के एतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर 39 वर्ष की उम्र में लगाया था. उम्र कभी भी उनके करियर में बाधा नहीं बनी. उन्होंने अपने करियर के आखिरी साल में कुल पांच शतक लगाए थे. साथ ही करियर के आखिरी कैलेंडर वर्ष में महज आठ टेस्ट मैचों में 114 की औसत से 1000 से ज्यादा रन बनाए थे. वह अपने अंतिम टेस्ट पारी में शून्य पर आउट हो गए थे, अन्यथा उनका टेस्ट औसत 100 से ज्यादा का होता. उनका टेस्ट औसत 99.94 का है. उनके सन्यास लेने के 65 साल बाद भी कोई खिलाड़ी उनकी बल्लेबाजी औसत के आस-पास भी नहीं फटक पाया है. ■

सचिन तेंदुलकर

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 15 वर्ष की उम्र में टेस्ट कैप पहनी थी. आज वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ किक्रेट का ताज बन चुकी है. सचिन तेंदुलकर 1989 से लेकर आज तक पिछले 23 सालों से क्रिकेट के मैदान पर अपना जौहर दिखा रहे हैं. उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में जो उपलब्धियां हासिल कीं, वहां तक पहुंचना आगे वाली पीढ़ी के लिए असंभव सा दिखाई पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बल्लेबाजी के अधिकांश रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के ही नाम दर्ज हैं. उम्र के 39वें पड़ाव पर पहुंचकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सौ शतक बनाने का अनोखा कारनामा कर दिखाया. एक दिवसीय क्रिकट में 18000 और टेस्ट क्रिकेट में 15000 से ज्यादा रन सचिन की महानता की कहानी खुद-ब-खुद बयां कर देते हैं. सचिन 200वां टेस्ट मैच खेलने से महज 2 कदम दूर हैं. वह 200 टेस्ट मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी होंगे. सचिन यहां तक अपने बल्ले के कारनामे से पहुंचे हैं. बावजूद इसके, उन पर सन्यास लेने का दबाव अभी से बनाया जाने लगा है, जबकि वह अभी भी युवा खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. ■

मार्टीना नवरातिलोवा

टेनिस की दुनिया में मार्टीना नवरातिलोवा का नाम जाना-पहचाना है. मार्टीना ने अपने करियर में कुल 59 ग्रैंडस्लैम खिताब जीते. उन्होंने साल 2006 में 49 वर्ष की उम्र में बॉब ब्रायन के साथ यूएस ओपन का मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता था. यह उनका 59वां ग्रैंडस्लैम खिताब था. एक समय पेस की मिक्स्ड डबल्स पार्टनर रहीं मार्टीना के खेल और उनके जुनून के बार में पेस ने कहा था कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उम्र तो महज एक आंकड़ा है. यह बात मुझे उन्होंने ही सिखाई. यदि आज मैं 40 वर्ष की उम्र में ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने में कामयाब हुआ हूं तो यह उनकी वजह से ही है, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा करते देखा है. जिस पैशन के साथ वह टेनिस खेलती हैं और जिस जीवन शैली के साथ जीवन-यापन करती हैं, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित और प्रेरित हुआ हूं. पेस ने नवरातिलोवा के साथ मिलकर 2003 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन और विंबलडन खिताब जीता था. ■

जॉर्ज फॉरमेन

फॉरमेन के नाम 48 वर्ष की उम्र में बॉक्सिंग का हैवीवेट टाइटल जीतने का रिकॉर्ड है. जॉर्ज एक प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में 29 साल तक रिंग में डटे रहे. उन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग के कुल 81 मुक़ाबलों में भाग लिया, जिसमें से 76 में वह विजयी रहे और केवल पांच मुक़ाबलों में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा. 76 में से 68 मुकाबले फॉरमेन ने नॉकआउट जीते थे. उन्होंने वर्ष 1969 में अपना बॉक्सिंग करियर आरंभ किया था, जिसका अंत 1997 में हुआ. ■

लुइजी फजौली

इटली के फॉर्मूला वन डाइवर लुइजी फजौली के नाम सबसे अधिक उम्र में फॉर्मूला वन रेस जीतने का रिकॉर्ड है. लुइजी ने 1951 में 53 वर्ष की उम्र में फ्रेंच ग्रां प्री जीत कर यह रिकॉर्ड बनाया था. आज भी उनका यह रिकॉर्ड कायम है. ■

रिचर्ड पेटी

रिचर्ड पेटी जाने-माने ऑटो कार चालक हैं. उन्हें कार रेसिंग की दुनिया में किंग के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने अपने करियर में 2000 से भी ज्यादा रेसों में भाग लिया, जिसमें से 200 रेसों में वे विजयी रहे और 123 पोल पोजीशन हासिल की और 712 बार टॉप टेन फिनिश किया. वह सात बार नेसकार चैंपियनशिप जीतने में सफल रहे. आंकड़ों के हिसाब से वे कार रेसिंग के सबसे सफल और सम्मानीय ड्राइवर हैं. पेटी ने अपना रेसिंग करियर 1958 में शुरू किया और 1992 में सन्यास लिया. 1991 में वह आखिरी बार अंतिम दस में जगह बनाने में कामयाब रहे थे. उस वक्त उनकी उम्र 54 वर्ष थी. ■

ऑस्कर स्वान

ऑस्कर स्वान के नाम ओलंपिक में सबसे अधिक उम्र में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है. उन्होंने 1912 में हुए ओलंपिक खेलों में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था. इस वक्त उनकी उम्र 64 साल 280 दिन थी. उन्होंने अमेरिकी खिलाड़ी गैलेन कार्टर स्पेंसर के रिकॉर्ड को 9 महीने के अंतर से मात दी थी और रिकॉर्ड अपने नाम किया था. गैलेन कार्टर स्पेंसर ने 1904 में हुए ओलंपिक में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था. इस वक्त उनकी उम्र 64 वर्ष थी. स्वान के नाम सबसे अधिक उम्र में किसी भी तरह का ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी है. उन्होंने 1920 में हुए ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था. उस वक्त उनकी उम्र 72 साल 281 दिन थी. लगभग सौ साल बाद भी यह रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हैं. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

शिवाजी राव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे. उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में बस कंडक्टर तक का काम किया. साउथ के निर्देशक बालाचंदर ने उन्हें अपनी फिल्म में ब्रेक दिया था. उनकी पहली ही फिल्म को नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला. इसके बाद उन्होंने पिछे मुड़कर नहीं देखा. साउथ में उनके फैंस उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं.

जन्मदिन मुबारक...

सुरों की मल्लिका

लता मंगेशकर के बारे में दिलीप कुमार ने कहा था कि जिस तरह फूल की खुशबू का कोई मस्क या रंग नहीं होता, वो महज़ खुशबू होती है, जिस तरह बहते हुए पानी के झरने या ठंडी हवाओं का कोई घर, गांव या वतन नहीं होता, वैसे ही लता मंगेशकर की आवाज़ कुदरत का एक नायाब करिश्मा है. सचमुच लता की अदम्य प्रतिभा के सामने अलफ़ाज़ छोटे पड़ने लगते हैं, तुलनाएं और मिसालें बौनी नज़र आती हैं.

यूनुस खान
feedback@chauthiduniya.com

उनके बारे में उस्ताद बड़े गुलाम अली ख़ां साहब ने कहा था-कमबख्त, कभी बेसुरी नहीं होती. पंडित कुमार गंधर्व ने कहा था-मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं. लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई. यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत को देखने का दृष्टिकोण भी बदला. तीन घंटों की रंगदार महफ़िल का सारा रस लता की तीन मिनट की रचना में आस्वादित किया जा सकता है. क्या पहली श्रेणी का कोई गायक तीन मिनट की अवधि में कोई चित्रपट गीत इतनी कुशलता और रसोत्कृष्टता से गा सकेगा. लता मंगेशकर चित्रपट संगीत क्षेत्र की अनभिशिक्त साम्राज़्ी हैं. गानेवाले कई हैं, लेकिन लता की लोकप्रियता उन सब से कहीं अधिक है. उनकी लोकप्रियता का शिखर अचल है. ऐसी कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है.

लता मंगेशकर के बारे में दिलीप कुमार ने कहा-जिस तरह फूल की खुशबू का कोई मस्क या रंग नहीं होता, वो महज़ खुशबू होती है, जिस तरह से बहते हुए पानी के झरने या ठंडी हवाओं का कोई मस्क या कोई घर, गांव या कोई वतन-देश नहीं होता, वैसे ही लता मंगेशकर की आवाज़ कुदरत की तख़लीक का एक करिश्मा है. सचमुच लता की अदम्य प्रतिभा के सामने अलफ़ाज़ छोटे पड़ने लगते हैं, तुलनाएं और मिसालें बौनी नज़र आती हैं. हमें समझ नहीं आता कि हम लता को सुनने के अनुभव को कैसे बयां करें. यहां तक पहुंचने के लिए लता को लंबा संघर्ष करना पड़ा है. कई संगीतकारों ने लता की आवाज़ को पतला कहा. कभी ये कहा गया कि उनकी आवाज़ ऊंचे सुरों पर कारगर साबित नहीं होती, लेकिन लता नहीं डिगीं और आज वो एक जीता-जागता करिश्मा हैं. लता का पहला कामयाब गीत था-आएगा आने वाला. आज से तकरीबन पैंसठ साल पहले आई फिल्म महल का ये गाना लिखा था जे. नक्शएब ने और संगीत था खेमचंद प्रकाश का. अभी भी ये गीत सुनें तो लगता है कि लता शुरू से ही चिर-उदासी का स्वर थीं...हैं और रहेंगी. यूं भी लगता है कि लता के भीतर एक एकाकी बाला छिपी है, अतल उदासी में डूबी एक अकेली यौवना. तभी तो उदास गानों में उनका उच्छलवास कलेजे को चीरकर रख देता है. ज़रा सन 1964 में आई फिल्म, वो कौन थी का गीत सुनिए, जिसे राजा मेंहदी अली ख़ां ने लिखा और स्वरबद्ध किया मदनमोहन ने. गाना है-जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए. चलिए थोड़ी देर के लिए हम लता और मदनमोहन की उंगली थामकर उदासी के स्वंरों की एक सुरीली यात्रा पर निकलते हैं. सन् 1964 में लता ने मदनमोहन के लिए वो गीत गाया-जो बिछड़े प्रेमियों की जिंदगी का नग़मा बन चुका है. आज भी न जाने कितने बिछड़े प्रेमी-प्रेमिका आधी रात के सायों में इस गाने की गोद में सिर रखकर रतजगा करते हैं. फिल्म वही है, वो कौन थी-और गाना राजा मेहदी अली ख़ां का-लग जा गले कि फिर वो हंसी रात हो ना हो/शायद इस जनम में मुलाक़ात हो ना हो. इसी फिल्म में लता ने एक और गहरी उदासी वाला गीत गाया-नैना बरसे रिमझिम रिमझिम. ये गाना गहरी विकलता वाले लता के आलाप से शुरू होता है. और बस फिर तो दिल बैठ जाता है. मदन भैया के साथ लता ने अपने बेहतरीन उदास नग़मे दिए हैं. सन् 1962, फिल्म संजोग. वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई. इसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा.

लता और मदनमोहन का संयोग मणिकांचन है और इस संयोग ने उदासी की धूसर छाया वाले ऐसे गाने दिए हैं जो हमारी तन्हाइयों को रोशन करने वाले जुगनू हैं. आइए अब एक ऐसा गाना सुनें-जो बहुत ज्याादा सुनाई नहीं देता. सन 1953 में आई फिल्म बाग़ी का मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत-हमारे बाद महफिल में अफ़साने बयां होंगे/ बहारें हमको ढूंढेंगी ना जाने हम कहां होंगे. मुझे लगता है कि ये उदासी कहीं से उधार नहीं ली जा सकती. इसे पैदा नहीं किया जा सकता.

लता में ये उदासी शायद अपनी जिंदगी के संघर्षों की वजह से कूट-कूटकर भरी है. वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग़ जलते हैं (जहांआरा/राजेंद्र कृष्ण /सन 1964), माई री मैं का से कहूं पीर (दस्तक/ मजरूह/ सन 1970), नैनों में बदरा छाए (मेरा साया/ राजा मेहदी अली खां/ 1966), मेरी वीणा तुम बिन रोए (देख कबीरा रोया/राजेंद्रकृष्ण/ 1957),आज सोचा तो आंसू भर आए (हंसते जख्म/ कैफी आज़मी/ 1973), हम प्यार में जलने वालों को (जेलर/ राजेंद्र कृष्ण 1958), ना हंसो हम पे जमाने के ठुकराए हुए हैं (गेट वे ऑफ इंडिया/राजेंद्र कृष्ण/ 1957)............हम इस फेहरिस्त को जाने कितना लंबा कर सकते हैं. उदासी जिंदगी का एक रंग है. एक बहुत ज़रूरी रंग. लता ने हमारी जिंदगी में इस रंग को और गहरा किया है. हमने सिर्फ मदनमोहन और लता की जोड़ी के उदास गानों की बात की. पर अन्य संगीतकारों के साथ भी लता ने बेमिसाल उदास गाने दिए हैं. उन्हें सालगिरह की शुभकामनाएं. ■

बड़ा दिलवाला

गुरु के लिए इससे बड़ी गुरुदक्षिणा क्या होगी कि उसका शिष्य कामयाबी की बुलंदियों को छू लेने के बाद भी उसे याद रखे. उसका शिष्य पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन जाए, इससे बड़ी उपलब्धि किसी गुरु के लिए क्या होगी. ऐसी ही खूशनसीब गुरु हैं बीएन शनथम्मा. जी हां, उन्होंने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को स्कूल में पढ़ाया था. 50 साल बाद जब रजनी को अपनी टीचर की बदहाली का पता चला तो वह तुरंत उनकी मदद के लिए आगे आए. 78 साल की शनथम्मा के लिए इस बार टीचर्स डे बेहद ख़ास रहा. इस दिन रजनीकांत अचानक अपनी टीचर शनथम्मा के घर पहुंच गए. दरअसल, करीब दो महीने पहले रजनीकांत को पता चला कि उनकी टीचर शनथम्मा इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. उन्होंने तभी अपनी टीचर को कॉल किया और उनके हाल-चाल पूछे. रजनी ने टीचर्स-डे का दिन चुना उनसे मुलाकात के लिए और अपनी टीचर को इसकी भनक तक नहीं लगने दी. टीचर्स-डे के दो दिन बाद शनथम्मा को पता चला कि उनके अकाउंट में रजनीकांत ने तीन लाख रुपये क्रेडिट किए हैं. शनथम्मा के लिए रजनी से मिलने से भी बड़ा सरप्राइज यह था कि उनकी जिसने मदद की, वह और कोई नहीं, बल्कि उनके ही स्टूडेंट रजनीकांत थे. गौरतलब है कि शनथम्मा ने रजनीकांत को तीन सालों तक पांचवीं, छठी और सातवीं क्लास में गविपुरम के गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया था. उनके करीबी लोगों का कहना है कि वह लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं और इसकी किसी को कानोंकान ख़बर नहीं होने देते. ऐसा वो मीडिया और पब्लिक की नज़रों से दूर रहने के लिए करते हैं. चूंकि यह मामला उनकी टीचर का था, इसलिए वह आगे आ गए. शनथम्मा ने रजनीकांत को स्कूल में इंग्लिश, कन्नड़ और साइंस पढ़ाई थी. उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका स्टूडेंट एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाएगा और तब भी उन्हें न सिर्फ याद रखेगा, बल्कि उनके मुश्किल समय में उनकी मदद करेगा. शनथम्मा अपने घर का किराया तक चुका पाने की स्थिति में नहीं थीं. उन्होंने रजनीकांत से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन रजनीकांत ने उन्हें बुलाने के बजाए खुद बेंगलुरु आकर उनसे मिलने का वादा किया.

64 साल के रजनीकांत अपने माता-पिता के चार बच्चों में से एक हैं. जब वे छोटे थे तो उनके परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. शिवाजी राव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे. उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में बस कंडक्टर तक का काम किया. साउथ के निर्देशक बालाचंदर ने उन्हें अपनी फिल्म में ब्रेक दिया था. उनकी पहली ही फिल्म को नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला. इसके बाद उन्होंने पिछे मुड़कर नहीं देखा. साउथ में उनके फैंस उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सलमान की फिल्म में राम

इन दिनों साउथ के ऐक्टर्स को बॉलीवुड से काफ़ी ऑफर्स मिल रहे हैं. इससे पहले भी साउथ के कई अभिनेताओं ने बॉलीवुड में किस्मत आजमाई, लेकिन वे साइड ऐक्टर के किरदार तक ही सीमित हो कर रह गए, लेकिन रांझना फेम धनुष के बाद अब लीड रोल के लिए भी साउथ के ऐक्टर्स को काम मिलने लगा है. साउथ के सुपरस्टार राम चरण तेजा की पहली हिंदी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी कि उन्हें बॉलीवुड से दूसरा

प्रोजेक्ट भी मिल गया. कहा जा रहा है कि सलमान ने राम को अपने घर बुलाया और उन्हें अपने फिल्म का ऑफर दिया. इस फिल्म की शूटिंग अगले साल ही शुरुआत में होगी. देर तक सलमान राम से प्रोजेक्ट पर बात करते रहे. गौरतलब है कि राम चरण तेजा जंजीर की रीमेक से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं. राम के साथ इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा हैं. जंजीर वह फिल्म है, जिससे अमिताभ को ऐंग्री यंग मैन का खिताब मिला था. इस फिल्म में राम और प्रियंका विजय और माला की भूमिका में हैं. फिल्म में संजय दत्त शेरखान की भूमिका में दिखेंगे. इस किरदार को पुराने जंजीर में प्राण ने निभाया था. ■

प्रीव्यू

सुपर मॉडल

फिल्म सुपर मॉडल ऐसी लड़कियों की कहानी है, जो किसी भी क़ीमत पर सुपर मॉडल बनना चाहती हैं. किसी भी लड़की के दिलोदिमाग़ पर अगर एक बार सुपर मॉडल बनने का जुनून सवार हो जाए तो वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है. ऐसी ही महत्वाकांक्षी लड़कियों को इस फिल्म में दिखाया गया है, जिन्हें सुपर मॉडल बनने के लिए अपने प्रतिस्पर्धी की जान लेने से भी परहेज नहीं है. वे टैलेंट के साथ ही साथ अन्य रास्तों पर भी चलकर किसी तरह अपने महत्वाकांक्षा के शिखर को छूना चाहती हैं. शराब व्यापारी हर्ष छाया अस्मित पटेल को फोटोग्राफर हायर करता है. वह एक सुपर मॉडल की तलाश में है, जो उसके शराब के नये लेबल को मार्केट में लॉन्च करे. इसकी ज़िम्मेदारी वह अस्मित पटेल को सौंपता है. अस्मित फिजी में एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता कराता है. वीना मलिक इस फिल्म में एक मॉडल की भूमिका में हैं. वह भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाती हैं, लेकिन वहां एक के बाद एक मॉडल्स की रहस्यमयी तरीक़े से मौत होने लगती है. इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, हर्ष छाया, बॉबी डार्लिंग भी मुख्य भूमिका में हैं. वीना और अस्मित पर फिल्माया गया गाना तुझसे अलग तुझसे जुदा ...दिल को छूने वाला है. ■

बैनर	:	मारुति मूविज, फिजी पीवीटी एलटीडी पीएनसी एन कैमरा इंटरनेशनल
प्रोड्यूसर	:	रवि अहलावत, प्रेम गुप्ता
स्टार कास्ट	:	वीना मलिक अस्मित पटेल जैकी श्रॉफ हर्ष छाया बॉबी डार्लिंग एडी इरानी
म्यूजिक डारेक्टर	:	डीजे शेजवूड
भाषा	:	हिंदी
डायरेक्टर	:	नवीन बत्रा
गायक	:	तरन्नुम मलिक नमन शास्त्री उजाला जाधव शबाब साब्री
लिरिक्स	:	कुंवर जुनेजा हरि शंकर श्रॉफ
म्यूजिक कंपनी	:	रेड ऐंड येलो म्यूजिक
रिलीज डेट	:	27 सितंबर, 2013

चौथी दुनिया

23 सितंबर-29 सितंबर 2013

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार - झारखंड

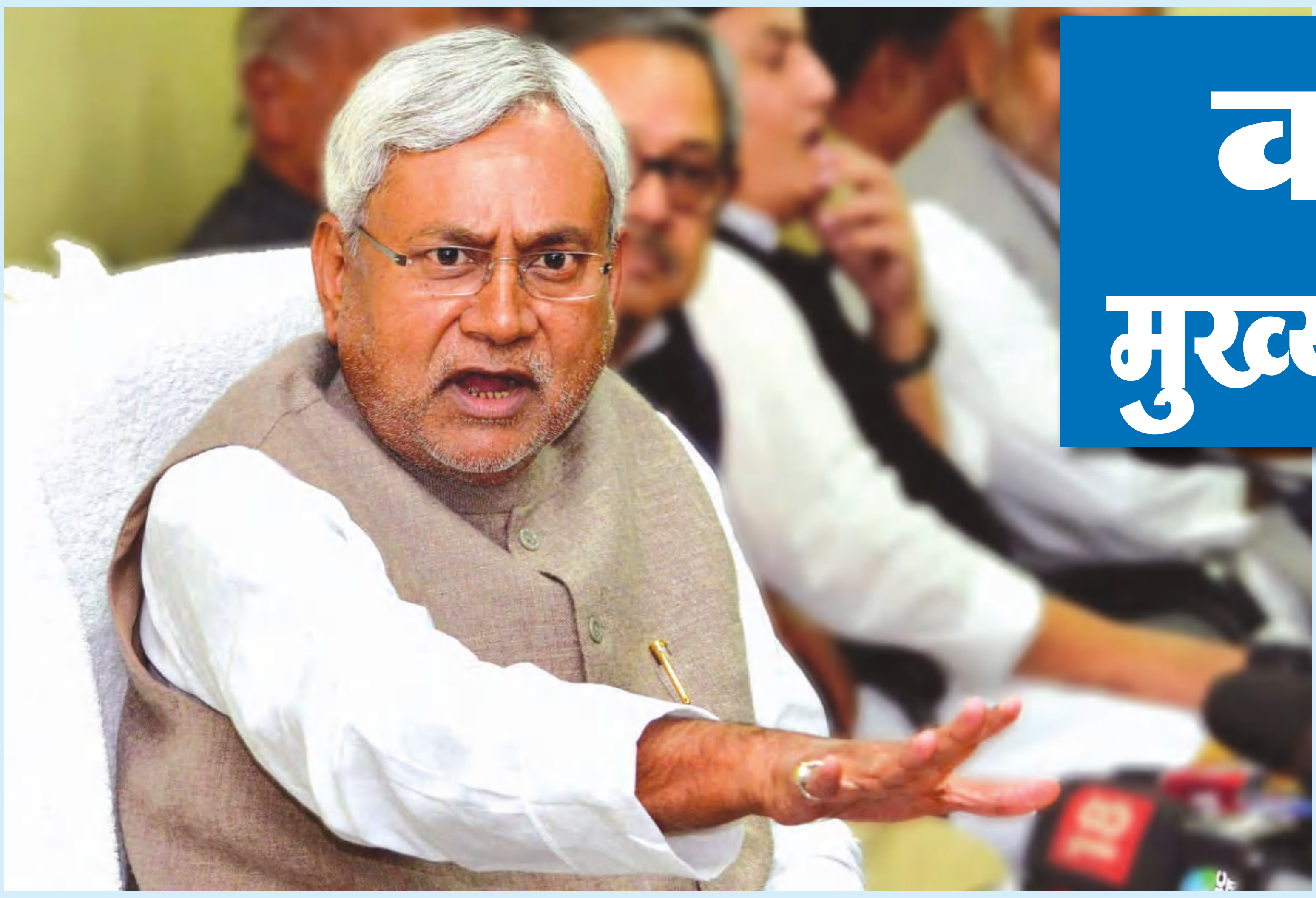

कमजोर मुख्यमंत्री हैं नीतीश

कहते हैं सत्ता व शासन इकबाल से चलता है, लेकिन जब इकबाल ही ख़त्म हो जाए तो फिर सत्ता, शासन और इसे चलाने वालों की हैसियत का अंदाज़ा सहज लगाया जा सकता है. क्या सचमुच नीतीश सरकार का इकबाल अब ख़त्म हो रहा है? भाजपा के नीतीश सरकार से अलगाव के बाद सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार फ़ैसला तो ले लेती है, लेकिन उसे अमल में लाने की कवायद या तो वह करना नहीं चाहती या फिर कोशिशों के बाद थक -हार कर अपने क़दम वापस खींच लेती है. अब सवाल उठने लगे हैं कि भाजपा का साथ छूटने के बाद आख़िर इस सरकार को क्या हो गया है?

सरोज सिंह

सरकार की कमजोरी का ताजा उदाहरण भाजपा के पूर्व मंत्रियों से आवास खाली कराने का प्रकरण है. 17 साल तक साथ-साथ काम करने वाले भाजपा के पूर्व मंत्रियों का आवास खाली कराने का नोटिस जारी कर सरकार ने यह संदेश दिया कि नियम हर एक के लिए बराबर है, चाहे वे पूर्व मंत्री हों या फिर आम आदमी. भाजपा के पूर्व मंत्रियों का इस मसले पर साफ़ कहना था कि उन्हें वैकल्पिक मकान दे दिया जाए तो बंगला खाली कर देंगे, लेकिन सरकार ने साफ़ कर दिया था कि जो होगा, वह नियम के तहत होगा. सभी को नियमों का पालन करना होगा. कुछ दिन बाद सरकार फिर एक क़दम आगे बढ़ी और सक्षम प्राधिकार ने बंगला खाली कराने के लिए दूसरा नोटिस भी जारी कर दिया. इसके बाद, भाजपा के कुछ मंत्री कोर्ट के शरण में चले गए. सरकार के स्तर पर तैयारी थी कि हर हाल में बंगला खाली कराया जाएगा, ताकि सही संदेश जनता के बीच जा सके, लेकिन अचानक जनता दरबार में नीतीश कुमार ने यह कहकर सारे मामले का पटाक्षेप कर दिया कि भाजपा के पूर्व मंत्री जब तक मन करे, मंत्रियों वाले बंगले में रह सकते हैं. मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद तो बंगले वाले प्रकरण का नाटकीय पटाक्षेप हो गया, पर इससे दो तरह के संदेश एक साथ निकले. पहला संदेश तो यह गया कि सरकार अपने लिए गए फ़ैसलों पर अमल नहीं कर पा रही है. अगर सरकार यह मान रही थी कि बंगला खाली करना नियम सम्मत है, तो मुख्यमंत्री ने भाजपा के पूर्व मंत्रियों को जब तक चाहें रहने की इजाजत आख़िर कैसे दे दी? इससे एक और सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसे लोगों का मनोबल और बढ़ेगा जो सालों से सरकारी आवासों में अवैध तरीक़े से रह रहे हैं, तो सरकार उनका मकान किस आधार पर खाली कराएगी. भाजपा के पूर्व मंत्रियों से बंगला खाली नहीं करना था, तो इतना दिखावा करने की क्या ज़रूरत थी. ऐसा लगता है कि

इस मामले में नीतीश से कहीं न कहीं चूक हुई है. नीतीश के बयान पलटते ही राजनीति भी शुरू हो गई और राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना है कि नीतीश कुमार के बयान से हमारे आरोप सही साबित हुए हैं. हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जदयू व भाजपा का रिश्ता टूटा नहीं है, बल्कि और भी मजबूत हुआ है. सुशील मोदी का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार लोकसभा चुनाव के बाद होगा और नीतीश कुमार केवल मुसलमानों को भ्रम में डालने के लिए भाजपा के विरोध का नाटक कर रहे हैं. आख़िर तालमेल नहीं है तो फिर भाजपा के पूर्व मंत्रियों से बंगला खाली क्यों नहीं कराया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव के बाद ये सारे पूर्व मंत्री एक बार फिर नीतीश सरकार में मंत्री बन जाएंगे. सिद्दीकी ने कहा कि मुसलमानों को बरगला कर उनका वोट नहीं लिया जा सकता है. जदयू व भाजपा में तालमेल था, है और रहेगा. हालांकि नीतीश कुमार बार-बार कहते हैं कि भाजपा के साथ अब उनकी पार्टी का कभी गठबंधन नहीं होगा, लेकिन उनके हाल ही में लिए गए फ़ैसले से एक भ्रम की स्थिति तो बन ही गई है. जो लोग सोच रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा, उनको निराशा हुई है. जब मुख्यमंत्री ने भाजपा के मंत्रियों को बंगला खाली करने से मना कर दिया है, तो अभी नए मंत्री बनाने की गुंजाईश कहां बनती है.

नीतीश द्वारा लिए गए इस फ़ैसले से जदयू के अंदर एक बेचैनी देखी जा सकती है और जिन निर्दलीय विधायकों ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया था, उनके हाथ केवल निराशा लगी है. राजद के विधायक सम्राट चौधरी कहते हैं कि मैंने आज तक इतना कमजोर मुख्यमंत्री नहीं देखा, जो मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट का विस्तार नहीं कर सकता वह बिहार जैसे प्रदेश का शासन क्या चलाएगा. कोई एक आदमी 18 विभागों को कैसे देख सकता है और बाढ़ व सुखाड़ से जनता मर रही है, पर सरकार चैन की नींद सो रही है. साफ है कि राजनीतिक कारणों से विकास व जनता के हितों के साथ समझौता किया जा रहा है. चौधरी का आरोप है कि भाजपा व जदयू आपस में मिले हुए हैं और लोकसभा चुनाव के बाद यह सच जनता के सामने भी आ जाएगा. भाजपा प्रवक्ता संजय मयूख कहते हैं कि नीतीश सरकार की कमजोरी का पता इसी बात से चलता है कि कोर्ट के आदेश को भी वह अमल में नहीं ला पा रही है. गंगा किनारे बसे अपार्टमेंट के मामले में क्या हो रहा है, इसे सब जानते हैं. क़ानून व व्यवस्था की स्थिति में गिरावट किसी से छिपी नहीं है. विकास का पैसा ख़र्च नहीं हो रहा है. लगता है मार्च लूट के लिए पैसे को जमा कर रखा गया है. नीतीश कुमार इतने कमजोर हैं कि किसी भी घटना के बाद घटनास्थल पर नहीं जाते, शायद जनता और सच का सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं रही. विधान पार्षदों का मनोनयन नीतीश कुमार इस डर से नहीं कर रहे हैं कि कहीं पार्टी में विद्रोह न हो जाए. मंत्रिमंडल विस्तार के साथ तो इस सरकार का जाना तय है. भाजपा के लोगों को तरह-तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं. यह सब एक कमजोर मुख्यमंत्री की निशानी है, लेकिन जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार दूसरी बात कहते हैं. नीरज कहते हैं कि बंगले वाले मामले में तो भाजपा का दोहरा चरित्र पूरी तरह बेनकाब हो गया. एक बंगले के लिए त्याग और तपस्या वाली पार्टी का दावा करने वाली भाजपा इतने नीचले स्तर तक चली जाएगी. इसे सोचा भी नहीं जा सकता. मुख्यमंत्री का बयान कमजोरी का नहीं, बल्कि शालीनता का परिचायक है. जदयू इस प्रकरण में बेवजह हो रही राजनीति को तूल नहीं देना चाहती. हम जनता के बीच इस मसले को लेकर जाएंगे और उसे बताएंगे कि भाजपा के लोग एक बंगले के लिए किस हद तक गिर सकते हैं. भाजपा इस प्रकरण का राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहती थी. मुख्यमंत्री ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और किसी भी पार्टी के नेता व प्रवक्ता जो भी कहें, पर यह समय ठहर कर कुछ सोचने का ज़रूर है.

देखकर आश्चर्य होता है कि दो तिहाई जनादेश लेकर दोबारा सत्ता में आई नीतीश सरकार इतनी जल्दी इतनी कमजोर कैसे हो गई. किसी भी शासन में सरकार फ़ैसले को टाल नहीं सकती और एक बार अगर फ़ैसला हो गया तो उस पर अमल करती है. ऐसा नहीं होता कि एक क़दम आगे चलकर दो क़दम पीछे हट जाएं. नीतीश सरकार का नाम बेहतर राजनीतिक और प्रशासनिक फ़ैसले और उस पर नीयत समय में अमल के लिए हुआ था, न कि लचीले फ़ैसले लेने और फिर उसे वापस लेने के लिए. उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार तमाम राजनीतिक बंदिशों के बावजूद नियम- क़ानून पर चलते हुए बेहतर प्रदर्शन का अपना रिकॉर्ड फिर दोहराएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

नेहा किडनी प्रकरण

डॉक्टर सच बोल रहे हैं या नेता

बिहार में धरती के भगवान हैवान बन रहे हैं. जी हां, डॉक्टर मरीजों की जान बचाने के बजाये उनकी जान की कीमत पर रुपये ऐंठने में लगे हैं. बिहार ही नहीं, पूरे देश से मानव अंगों की तस्करी की खबरें आ रही हैं, लेकिन सरकार इस मामले पर तनिक भी गंभीर नहीं लगती.

बिहार में पिछले कुछ सालों से मानव अंगों की तस्करी जोरों शोर से हो रही हैं. आये दिन इस तरह की खबरे समाचार पत्रों की सुर्खियों में होती हैं. पिछले दिनों एक खबर आई थी कि यहां के डॉक्टरों ने पुरुष तक का गर्भाशय निकाल कर स्वास्थ्य बीमा की राशि ऐंठ ली. अभी हाल ही में पटना के एक नर्सिंग होम में एक नवप्रसूता 20 वर्षीया नेहा देवी की किडनी निकालने की घटना प्रकाश में आई है.

- शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

» एक नज़र «

कला सदन की दरकार

सीतामढ़ी में ख्याति प्राप्त शिल्पी फणी भूषण विश्वास की कला साधना अब भी अनवरत जारी है. पूर्वी रिंगबांध स्थित अपने आवासीय परिसर में दर्जनों महापुरुषों के अलावा अन्य मनोहारी मूर्तियों में जीवंतता देने का हर संभव प्रयास उनकी दिनचर्या बनी है. विश्वास के आवासीय परिसर में मौजूद दुष्यंत–शकुंतला, साईं बाबा, स्वामी विवेकानंद, डॉ. हेडगवार, वीर सावरकर, शरतचंद्र चटोपाध्याय, लोक नायक जय प्रकाश नारायण, गांधी–नेहरू के मुस्कान के पल, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दूल कलाम, रवींद्र नाथ टैगोर, सरदार बल्लभ भाई पटेल समेत दर्जनों मूर्तिया लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी हैं. विश्वास की मंशा उक्त मूर्तियों को अब एक कला सदन में सजा कर भावी पीढ़ी के लिए समर्पित करने की है. कहते है कि इस कार्य के लिए अगर सरकारी अथवा प्रशासनिक स्तर पर अगर जगह के साथ एक भवन उपलब्ध कराया जाए तो सीतामढ़ी ज़िले के लिए एक अद्वितीय संग्रहालय साबित हो सकता है. *– ब्रजेश*

प्रतिमा का अनावरण

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पिछले दिनों स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर में सीता उद्भव प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की. सीतामढ़ी शहर के ख्याति प्राप्त शिल्पी फणी भूषण विश्वास के इस कृति के निर्माण में तक़रीबन 41 लाख रुपये ख़र्च किये गये. इनमें महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के अलावा पर्यटन विभाग बिहार सरकार, मां जानकी जन सेवा ट्रस्ट एवं रीगा सुगर कंपनी ने अहम योगदान दिया है. कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के नाम पर किये गये प्रशासनिक ताम–झाम के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. हद तो तब हो गई, जब सीएम के कार्यक्रम के कवरेज के लिए गये स्थानीय मीडिया कर्मियों को भी प्रतिमा अनावरण स्थल तक जाने पर पाबंदी लगा दी गई. बाद में मंच का कवरेज के लिए प्रवेश करने दिया गया.

बैंक शाखा का उद्घाटन

सीतामढ़ी शहर स्थित मेहसौल चौक के समीप डुमरा रोड में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की नई शाखा खुली. शाखा का विधिवत उद्घाटन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहिद अली ख़ान व विधान पार्षद सह पूर्व मंत्री देवेशचंद्र ठाकुर ने फीता काट कर की. मौक़े पर बैंक के सहायक महाप्रबंधक अरुण कुमार सिंह, शाखा प्रबंधक सरफराज नवाज अहमद, वरिष्ठ प्रबंधक कृष्ण प्रसाद सिंह, उप प्रबंधक विद्यानंद व जदयू नेता शादाब अहमद खा के अलावा दर्जनों लोग मौजूद थे.

तिरहुत स्नातक क्षेत्र का होगा विकास

पूर्व विधान पार्षद सह तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के घोषित प्रत्याशी राम कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा के कुशल मार्गदर्शन में स्नातक क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा. सिंह ने कहा कि वर्तमान परिवेश में देश व बिहार के विकास के लिए भाजपा को शासन का कमान सौंपना अति आवश्यक है. उन्होंने कहा कि अब तक तिरहुत स्नातक क्षेत्र का वाजिब विकास नहीं हो सका है, जिसका मुख्य कारण प्रतिनिधियों की उदासीनता रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सूबे में तिरहुत क्षेत्र विकास के शीर्ष पर होगा.

– बाल्मीकि

बसपा ही विकल्प

आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा कार्यकर्ता एकजुटता का परिचय देने को तैयार है. सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी डॉ. महेश कुमार ने पुपरी में कहा कि वर्तमान में बिहार में बसपा से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है. बिहार की जनता तक़रीबन सभी प्रमुख दलों के शासन को झेल चुकी है. अब सबकी नज़र बसपा पर टिकी है. पार्टी संगठन के तत्वावधान में ज़िले के अलग–अलग स्थानों पर लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को जागरुक करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आम जनता झूठी घोषणा करने वालों को सबक सिखायेगी. ■ *– गोविंद कुमार*

जमकर खाएं मेथी

ariskon Pharma Pvt.Ltd.

डॉ. के. एस. आनन्द
हड्डी रोग विशेषज्ञ पूर्णिया

सीमांचल की चिकित्सक नगरी पूर्णिया में डॉ. के. एस. आनन्द पड़ोसी देश नेपाल से लेकर बंगाल तक में प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। इनके यहाँ सीमांचल से लेकर बंगाल तक के रेफर किये गये मरीज पहुँचते हैं। उनका कहना है कि आस्टियोपरोसिस रोग अधिकतर महिलाओं में होने का कारण मासिक चक्र में गड़बड़ी और कैलसियम और प्रोटीन युक्त भोजन की कमी है।

हड्डी के टूटने पर तत्काल उसे सपोट की सहायता से बाँध देना चाहिए और चिकित्सक से तुरंत सम्पर्क करना चाहिए। कैलसियम मेथी में प्रर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लोगों खासकर महिलाओं को मेथी का सेवन जरूर करना चाहिए। कैलसियम युक्त भोजन के लिए लोगों को दूध, सोयाबीन, मछली, मांस और ड्राई फ्रूट का सेवन करना चाहिए। पुरूषों की तुलना में महिलाओं को कैलसियम युक्त भोजन का अधिक सेवन करना चाहिए।■ प्रस्तुति:नीरज सिंह

ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident

Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.

AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.

ASRFEN-P
Acedofenac+Paracetamol Serratiopeplidase Tab.

ECTALOPAM
Escilalopram oxalate & Clonazepam Tablets

SILIPLEX
Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Cap/Syp

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

गया संसदीय क्षेत्र

मांझी जाति के प्रत्याशियों के बीच मुक़ाबला

सुरक्षित संसदीय क्षेत्र गया में जीत किसी भी पार्टी की हो, लेकिन वहां लोकसभा चुनाव में असली लड़ाई मांझी जाति के प्रत्याशियों के बीच होगी, क्योंकि भाजपा, राजद, और जदयू से लोकसभा चुनाव के लिए जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनमें से अधिकांश(मांझी) भूइयां जाति के ही हैं.

सुनील सौरभ

मगध के राजनीतिक–सांस्कृतिक केंद्र सुरक्षित संसदीय क्षेत्र गया में पिछले दो दशक से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच चुनावी लड़ाई हो रही है. यदि दो दशक पीछे की बात करें तो जीत किसी भी पार्टी की हुई हो, लेकिन यहां अधिकांश बार मांझी (भूईयां) जाति का ही प्रत्याशी जीता है. 2014 लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर यहां मांझी जाति के प्रत्याशियों के बीच चुनावी लड़ाई होने की संभावना है, क्योंकि भाजपा, राजद, और जदयू से लोकसभा चुनाव के लिए जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनमें से अधिकांश(मांझी) भूईयां जाति के ही हैं. इसके साथ ही अनेक दलों में पासवान जाति के प्रत्याशियों का नाम दूसरे स्थान पर है. पिछले 2009 लोकसभा चुनाव में भी मांझी जाति के प्रत्याशियों के बीच ही टक्कर हुई थी, जिसमें भाजपा के हरि मांझी ने राजद के रामजी मांझी को पराजित किया था और तीसरे स्थान पर कांग्रेस के संजीव प्रसाद टोनी रहे थे. दलीय और जातीय समीकरण के आधार पर जिस राजनीतिक दल का वोट बैंक सबसे अधिक मजबूत होगा, उसी की जीत होगी. कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाला गया संसदीय क्षेत्र जब से सुरक्षित हुआ है, तब से कांग्रेस की स्थिति यहां कमजोर हुई है. 1989 के बाद से इस संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस हालत बिगड़ती ही जा रही है. पिछले ढाई दशक से कभी भाजपा तो कभी राजद का गया संसदीय क्षेत्र पर क़ब्ज़ा रहा है. यहां पर कांग्रेस की यह स्थिति हो गई है कि वह स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवार नहीं खोज पा रही है या कांग्रेस किसी मजबूत उम्मीदवार को टिकट ही नहीं दे रही है.

यदि देखा जाए तो कांग्रेस के पास क्षेत्रीय स्तर पर गया में स्थानीय और मजबूत प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस उन लोगों को प्रत्याशी नहीं बना पा रही है. स्व. रामस्वरूप राम गया संसदीय क्षेत्र से दो बार सांसद रह चुके थे और वे कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे. गत विधान सभा चुनाव में कांग्रेस ने उनके पुत्र शंकर स्वरूप को जहानाबाद ज़िले के मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया था, लेकिन वे जदयू प्रत्याशी जीतन राम मांझी से चुनाव हार गए थे.

संयोग ऐसा इस बार गया सुरक्षित संसदीय क्षेत्र से जदयू से जीतन राम मांझी और कांग्रेस शंकर स्वरूप दमदार संभावित प्रत्याशी हैं. शंकर स्वरूप अपने पिता के बाद विरासत में मिली राजनीति और अब कांग्रेस से लोकसभा टिकट के मजबूत दावेदार हैं. अपने पिता स्व. रामस्वरूप राम के संसदीय क्षेत्र के लोगों से संबंधों को बरक़रार रखते हुए कांग्रेस से लोकसभा टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं. स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की नई नीति युवा को आगे लाओ के तहत भी कार्य कर रहे हैं. इस संसदीय क्षेत्र से भाजपा के टिकट के लिए सबसे अधिक दावेदार हैं और वर्तमान सांसद हरि मांझी भाजपा से ही हैं. अन्य संभावित भाजपा प्रत्याशियों को उम्मीद है कि हरि मांझी का टिकट कटता है, तो उन्हें ही टिकट मिलेगा. पूर्व विधायक रामस्वरूप पासवान की पुत्रवधू और पूर्व गया ज़िला परिषद अध्यक्ष कुमारी शोभा सिन्हा का भी नाम टिकट के दावेदरों में है. इनके अलावा, बोधगया के भाजपा विधायक श्यामदेव पासवान, बिहार सरकार में अनुसूचित जाति–जनजाति कल्याण मंत्री जीतनराम मांझी के पुत्र संतोष कुमार मांझी भी भाजपा टिकट के लिए दावेदार हैं. मजेदार बात तो यह है कि जीतनराम मांझी जदयू में हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन गया संसदीय क्षेत्र से उन्हें जदयू प्रत्याशी का प्रबल उम्मीदवार माना जा रहा है. जबकि उनकी समधन बाराचट्टी की जदयू विधायक श्रीमती ज्योति देवी भी जदयू की प्रत्याशी मानी जा रही है, लेकिन अपने पिता और सास ज्योति देवी से अलग वर्षों से भाजपा में सक्रिय संतोष कुमार मांझी को भी गया संसदीय क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी माना जा रहा है. लोगों का मानना है कि वर्तमान सांसद हरि मांझी का टिकट कटा तो भाजपा में टिकट को लेकर विवाद हो जाएगा और राजद में तो ऐसे कई दावेदार हैं, लेकिन सबसे मजबूत दावेदार पूर्व सांसद रामजी मांझी है. राजद के परम्परागत वोट बैंक के अलावा जातीय वोट बैंकों पर मजबूत पकड़ रखने वाले रामजी मांझी की व्यक्तिगत कारणों से अगड़ी जातियों के वोट बैंक पर भी अच्छी पकड़ मानी जाती है. सांसद रहते उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों का लाभ उनको मिल सकता है. लोगों ने मान लिया है कि राजद का टिकट रामजी मांझी को ही मिलेगा, क्योंकि राजद के पूर्व सांसद राजेश कुमार मांझी की सांसद रहते बहुत ही ख़राब छवि रही तथा क्षेत्र में इस 5 सालों में सक्रियता भी नहीं के बराबर रही. ऐसे तो राजद लोजपा में गठबंधन है.

> » दलीय और जातीय समीकरण के आधार पर जिस राजनीतिक दल का वोट बैंक सबसे अधिक मजबूत होगा, उसी की जीत होगी. कभी कांग्रेस का गढ़ रह चुका गया संसदीय क्षेत्र जब से सुरक्षित हुआ है, तब से कांग्रेस की स्थिति यहां कमजोर हुई है. 1989 के बाद से इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की हालत बिगड़ती ही जा रही है. पिछले ढाई दशक से कभी भाजपा तो कभी राजद का गया संसदीय क्षेत्र पर कब्ज़ा रहा है. यहां पर कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो गई है कि वह स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवार नहीं खोज पा रही है या कांग्रेस किसी मजबूत उम्मीदवार को टिकट ही नहीं दे रही है. «

लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान गया में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान पूर्व सांसद स्व. राजेश कुमार के पुत्र पूर्व विधायक कुमार सर्वजीत को गया संसदीय क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन गठबंधन में हमेशा गया संसदीय क्षेत्र राजद के खाते में रहा है. जातीय आधार पर मांझी (भूईयां) का वोट बैंक सर्वाधिक क़रीब साढ़े तीन लाख है, तो दूसरे स्थान पर यादव तथा तीसरे स्थान पर राजपूत, मुस्लिम, भूमिहार तथा कोईरी का वोट क़रीब बराबर–बराबर ही हो सकता है. गया संसदीय क्षेत्र से 1952 में ब्रजेश्वर प्रसाद, 1957 में भी ब्रजेश्वर प्रसाद, 1962 में बृजकिशोर सिंह, 1967 में आर. दास, 1971 में ईश्वर चौधरी, 1977 में ईश्वर चौधरी, 1980 में रामस्वरूप राम, 1984 में रामस्वरूप राम, 1989 में ईश्वर चौधरी, 1991 में राजेश कुमार, 1996 में भगवती देवी, 1998 में कृष्ण कुमार चौधरी, 1999 में रामजी मांझी, 2004 में राजेश कुमार मांझी तथा 2009 में भाजपा के हरि मांझी सांसद चुने गए. 2009 में गया सुरक्षित संसदीय क्षेत्र से कुल 16 उम्मीदवार थे. इस चुनाव में हरि मांझी भाजपा को 2,46,255, रामजी मांझी राजद को 1,83,802, संजीव प्रसाद टोनी को 64,902, कलावती देवी बसपा को 22,854, निरंजन कुमार सीपीआई एमएल को 6704, श्यामल मांझी को 6178, दिलीप पासवान को 6025, राजेश कुमार को 4650, रामदेव आर्यपाल 2156, अमरनाथ प्रसाद 2548, शिवशंकर कुमार को 3448, रामू पासवान को 3022, रामकिशोर पासवान को 4366, कृष्ण कुमार चौधरी को 2020, कईल दास को 20882 तथा दीपक पासवान को 20371 मत मिले थे. गया संसदीय क्षेत्र की वर्तमान राजनीतिक स्थिति से यह स्पष्ट है कि यहां विभिन्न दलों के मांझी जाति के प्रत्याशियों के बीच ही चुनावी दंगल होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

पृष्ठ 17 का शेष

डॉक्टर सच बोल रहे हैं या नेता

राजधानी के पाटलिपुत्र इलाक़ा स्थित कमला नर्सिंग होम में एक बच्ची को जन्म देने के बाद उक्त प्रसूता की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे एक दूसरे निजी नर्सिंग होम राजेंद्र नगर के चाणक्य हॉस्पिटल में रेफर कर दिया. यहां उसकी हालत और बिगड़ती गई. इसके बाद उसे एक अन्य नर्सिंग होम पटना बाईपास स्थित निर्मल हॉस्पिटल भेज दिया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतका के पति सोनू कुमार ने बताया की प्रसव के बाद नेहा की स्थिति बिगड़ने लगी थी. इसके बावजूद कमला नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया. मृतका नेहा के पति और उसके पिता बिहारी लाल साह ने आरोप लगाया कि कमला नर्सिंग होम में उसकी किड़नी चोरी कर ली गई थी. यहां के लोगों का कहना है कि चिकित्सक और चिकित्सा संगठनों के जबर्दस्त दबाव के कारण सब चुप्पी साधने में ही भला समझते हैं. इस मसले पर लोजपा आगे आई. लोजपा ने लंबे अर्से के बाद जनता के मौलिक मुद्दे पर आंदोलन को एक मुक़ाम दिया. इस आंदोलन का नेतृत्व लोजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य सह प्रदेश महासचिव रोहित कुमार सिंह कर रहे थे. हालांकि इस पूरे संघर्ष की पटकथा पर्दे के पीछे से लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. सत्यानंद शर्मा ने लिखी थी. सत्यानंद आरोप लगाते हैं कि नीतीश शासन में सत्तासंपोषित आपराधिक घटनाएं घट रही है. राज्य के कई ज़िलों में ग़रीबों की किडनी निकालने का मामला सामने आया है. कई मामलों में तो रोगी की मृत्यु भी हो गई, लेकिन ऐसे दोषी चिकित्सकों और नर्सिंग होम पर कोई कारवाई नहीं हुई. पटना की नेहा देवी के मामले का उल्लेख करते हुए कहते हैं इलाज के दौरान 20 साल की कम उम्र की महिला मरीज को 45 यूनिट ख़ून चढ़ाया गया. यहां गौर करने वाली बात यह है कि औसतन 350 मिली ख़ून का एक यूनिट होता है. इस प्रकार किसी मरीज को 16 लीटर ख़ून चढ़ाया गया, जबकि औसतन एक मानव शरीर में 5–6 लीटर ख़ून ही होता है. इलाज की ऐसी प्रक्रिया अपने आप में ही पूरे इलाज पर गंभीर प्रश्न खड़ी करती है. मरीज के परिजनों के अनुसार पूरे इलाज के दौरान उनसे 4 लाख रुपये से अधिक की वसूली की गई. मरीज की मौत के बाद पहले लोजपा की स्थानीय नेत्री मीना देवी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नर्सिंग होम के पास ख़ूब उधम मचाया. इसके बाद रोहित कुमार सिंह के नेतृत्व में लोजपा कार्यकर्ताओं ने पटना के जिलाधिकरी एन. श्रवण कुमार के आवास का घेराव किया. कार्यकर्ताओं ने अति उत्साह में जिलाधिकारी के आवास का गेट तोड़ दिया. निश्चय ही प्रतिरोध का यह लोकतांत्रिक तरीक़ा नहीं है. इसके बावजूद पुलिस–प्रशासन के रवैया को भी उचित नहीं ठहराया जा सकता, यह अजीबोगरीब है. इसका दोहरा नजरिया भी उजागर हो गया है. धरना–प्रदर्शन करने वालों पर त्वरित कारवाई करती है. उन्हें जेल भेजने में जरा भी विलंब नहीं करती है. चार डॉक्टरों कमलेश तिवारी, अनिल कुमार तिवारी, राजेश कुमार और अंजली तिवारी पर मृत प्रसूता नेहा देवी के परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस आरोपित चिकित्सकों को गिरफ्तार करने के नाम पर उन्हें ढूंढ़ने का बहाना कर रही है. वहीं इस मामले को लेकर आंदोलन करने वाली लोजपा नेत्री सोनी देवी समेत मृतका के रिश्तेदारों को दबोचकर जेल भेज दिया. नवप्रसूता की किडनी निकालने जैसे संगीन मामले में प्रशासनिक लापरवाही के ख़िलाफ़ पटना के जिलाधिकारी का आवास घेरने गए लोजपा के प्रदेश महासचिव रोहित कुमार सिंह, प्रदेश सचिव उपेन्द्र यादव, कामेश्वर यादव, वासुदेव महतो, महेंद्र महतो एवं महेन्द्र दास पर नामजद एवं पच्चीस अन्य अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. डीएसपी मनोज कुमार तिवारी उनके ख़िलाफ़ शीघ्र कारवाई का दावा करते हैं. चर्चा है कि पुलिस उन्हें लाल हवेली का सैर करवाने को आमादा है. रोहित कुमार सिंह पर पहले भी गर्भाशय घोटाला के विरोध में प्रदर्शन के दौरान राजभवन में जबरिया घुसने के प्रयास के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. रोहित कुमार सिंह का कहना है राज्य सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लोजपा कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी करवा रही है. पूर्व में भी कई कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया. लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने वाले नीतीश कुमार से लोजपा के जुझारू कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है. किडनी और गर्भाशय निकालने वालों को संरक्षण देने वाली इस सरकार और इसके प्रशासन के ख़िलाफ़ पार्टी का यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा. उनके सहयोगी एवं लोजपा के प्रदेश सचिव उपेन्द्र यादव कहते हैं कि हमें बेल नहीं जेल चाहिए. नीतीश सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है. इस शासन में जान बचाने वाले डॉक्टर भी हैवान बन गए हैं. इस स्थिति में कम–से–कम जेल में इतनी सुरक्षा तो होगी कि किडनी निकालकर जान नहीं ली जायेगी.

हालांकि लोजपा द्वारा बवाल मचाने के बाद किडनी निकाले जाने के गंभीर आरोप के तूल पकड़ने पर प्रशासन हरकत में आई और पटना के जिलाधिकारी के आदेश पर मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया. शव का पोस्टमार्टम भी बोर्ड के डॉक्टरों की निगरानी में किया गया. परीक्षण की पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी भी करा ली गई, लेकिन डॉ. सत्यानंद इससे खुश नहीं है. वह इस मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और उच्चतम न्यायालय तक ले जाएंगे. इस मामले में लोजपा कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे थे, तब उन पर लाठी चार्ज किया गया. उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया गया. जब तक पटना के डीएम, एसएसपी को मुअत्तल नहीं किया जाएगा, मृतक के परिजनों को दस लाख मुआवजा नहीं मिलेगा, लोजपा के नेता और कार्यकर्ता पर बिना शर्त मुक़दमा वापसी और जेल से रिहाई नहीं होगी, तब तक आंदोलन अनवरत चलता रहेगा. हालांकि चिकित्सकों के संगठन बिहार राज्य आईएमए के अध्यक्ष डॉ. राजीव रंजन प्रसाद और उपाध्यक्ष डॉ. सहजानंद प्रसाद सिंह ने डॉक्टरों पर लगे तमाम आरोपों को तथ्य से परे बताया. उनके अनुसार असामाजिक तत्वों ने किडनी निकालने की अफवाह फैला नर्सिंग होम पर हमला बोल दिया और तीनों नर्सिंग होम्स को बदनाम करने की कोशिश की. वैसे भी डेथलेस अस्पताल की कोरी कल्पना के आधार पर डॉक्टरों को दोषी ठहराना नाजायज है. सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक क़दम उठाना चाहिए. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

वाल्मीकि कुमार

बिहार में एनडीए में मचे घमासान के बीच सीतामढ़ी ज़िले की राजनीति करवट लेने लगी है. शह-मात के इस खेल में एक दूसरे दल के नेताओं को अपने पाले में लाने की कवायद सभी दल यहां कर रहे हैं...

नीतीश ने पिंटू पर पासा फेंका

नीतीश कुमार ने चार सितंबर को सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित सीता उद्भव प्रतिमा अनावरण समारोह के दौरान मजाकिया लहजे में नगर भाजपा विधायक सह पूर्व पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू को अपने पाले में लाने का पांसा फेंका. सीएम नीतीश कुमार के आगमन ने ज़िले की राजनीतिक तपिश को कई गुणा बढ़ा दिया. ख़ासकर इसका असर भाजपा खेमे में देखने को भी मिला. प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम से महज एक दिन पूर्व यानी 3 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में जदयू के विश्वासघात के ख़िलाफ़ एक जनाक्रोश सभा का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम को लेकर भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा वृहद स्तर पर शहर में जगह-जगह तोरण द्वार बनाया गया था. कमल निशान वाले भाजपा के झंडा के साथ नरेंद्र मोदी के बड़े-बड़े फोटो भी लगाये गये थे, लेकिन महज रात का अंधेरा छंटने के साथ ही अगले दिन कमल निशान लगा झंडा वाले तमाम स्थानों पर जदयू का तीर तना नज़र आने लगा. इसे देखते ही भाजपा नेता व कार्यकर्ता अपना आपा खोने लगे. मुख्यमंत्री के आगमन से महज डेढ घंटा पूर्व ज़िला मुख्यालय डुमरा स्थित शंकर चौक के समीप भाजपा के विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद, विधायक राम नरेश प्रसाद यादव, मोतिलाल प्रसाद, जिलाध्यक्ष मनोज कुमार, क्रीडा मंच के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार शक्ति के साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एनएच-77 पर प्रदर्शन कर रोश का इजहार किया. विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद व विधायक द्वय ने तो यहां तक कह डाला कि इस कार्य में प्रशासनिक तंत्र ने जदयू के कुछ गुंडों का भरपूर मदद किया है.

उन्होंने चेताते हुए कहा कि अगर ऐसा ही खेल होता रहा तो ज़िले में भाजपा कार्यकर्ता अपने सम्मान व स्वाभिमान को लेकर सड़क पर उतरने से बाज नहीं आयेंगे. इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी रोष था, तभी भाजपा के नगर विधायक सह पूर्व पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू रेलवे स्टेशन स्थित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पहुंच गये, जहां उन्होंने प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में भागीदारी के क्रम में पूरा समय भी दिया. कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कुछ पार्टी कार्यकर्ता मूक दर्शक बने रहे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि नगर विधायक पिंटू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ऐसे समय में एक मंच पर हो सकते हैं, जब सूबे में भाजपा-जदयू आमने-सामने है. हालांकि नगर विधायक पिंटू ने विकास योजनाओं की भावना की परत को सीएम के सामने रख कर मंच पर अपनी उपस्थिति के संदर्भ में जवाब देने का आग्रह किया. उन्होंने पूर्व में अपने कार्यकाल में स्वीकृत किये गये पर्यटन विकास की योजनाओं को पूर्ण कराने का आग्रह करते हुए प्रतिमा अनावरण के लिए उन्हें बधाई भी दी.

मुख्यमंत्री ने विधायक की बातों को मजाकिया लहजे में लेते हुए कहा कि हम आपको अपना मानते रहे हैं. राजनीति में कुछ मजबूरियां जरूर होती हैं. ऐसी स्थिति में किसी भी बात को बुरा नहीं मानते हैं. पर्यटन के क्षेत्र में पूर्व मंत्री सुनील कुमार पिंटू के योगदान की चर्चा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पर्यटकों के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया जायेगा. अंत में सीएम ने कहा कि राजनीतिक माहौल में आए बदलाव के कारण हम अलग हुए हैं, लेकिन आप हमारे करीब हैं और आगे भी रहेंगे. बताते चलें कि इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री के सेवा यात्रा के क्रम में सीतामढ़ी आगमन के दौरान पिंटू के आवास पर मुख्यमंत्री द्वारा रात का भोजन करने के बाद भी ज़िले में तरह-तरह की राजनीतिक अफवाहों का बाजार गर्म हुआ था. इस बार भी एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता व कार्यकर्ता सड़क पर नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते रहे, वहीं दूसरी ओर नगर भाजपा विधायक मंच पर मुख्यमंत्री के भाषण पर ताली बजाते रहे. इन तमाम पहलुओं पर गौर करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं की माने तो बतौर पर्यटन मंत्री नगर विधायक सुनील कुमार पिंटू ने उक्त प्रतिमा निर्माण को लेकर अहम योगदान दिया था. बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से पिंटू ने तक़रीबन 18 लाख रुपये भी योजना को पूर्ण करने को लेकर उपलब्ध कराया था. यही कारण था कि कार्यक्रम में भागीदारी के निमंत्रण को पिंटू नहीं टाल सके.

अब राजनीतिक बयार की दिशा मापने वाले पार्टी कार्यकर्ता से लेकर आम लोगों के बीच राजनीतिक चर्चा का केंद्र आगामी लोकसभा चुनाव बना है. इतना तो है कि ज़िले में पूर्व से अघोषित गुटबाज़ी का शिकार भाजपा एक बार फिर अंदर ही अंदर प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम की आड़ में पार्टी की राजनीति को दिशा देने में कोई कसर शायद ही छोड़ेगी. फिलहाल नीतीश-पिंटू प्रसंग ने ज़िले की राजनीति में बदलाव की आशंका को मझधार में फंसी नौका के समान छोड़ दिया है. अब देखना यह है कि कुशल केवट की तरह नौका को मझधार से निकाला जाता है अथवा दिशा बदल कर कमल का नौका तीर का शिकार होता है.■

feedback@chauthiduniya.com

राजेश कुमार

जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी छिनी

राजनीतिक गठजोड़ के इस वातावरण में जमुई ज़िले के ज़िला परिषद अध्यक्ष की सीट ब्रह्मदेव रावत से छिन गई. बिना किसी हलचल के ज़िला पंचायत अध्यक्ष ब्रह्मदेव रावत पद से हटा दिए गए. सत्ताधारी दो राजनीतिक पीठों के प्रिय पात्र होने के बावजूद आख़िर ऐसा क्यों हुआ? ब्रह्मदेव रावत की माने तो उनकी इस दशा के पीछे अपनो का ही हाथ है, जिस कारण बिना किसी हलचल के ज़िला परिषद अध्यक्ष के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और बैठक के दौरान बड़े ही सरल तरीक़े से वह पारित हो गया.

जमुई की राजनीति में रसूख रखने वाले मंत्री नरेंद्र सिंह व दामोदर रावत भी इस परिवर्तन पर अब तक चुप्पी साधे हैं. हालांकि ब्रह्मदेव रावत को जिप अध्यक्ष बनाने के लिए दोनों मंत्रियों ने अपने-अपने स्तर पर पूर्व में प्रयास किया था और वे निर्विरोध ज़िला परिषद अध्यक्ष चुने गये थे, लेकिन बीते एक महीने में ब्रह्मदेव रावत से आख़िर क्या ग़लती हो गई कि दोनों राजनीतिक शक्तिपीठों ने संकट आने पर मुंह मोड़ लिया. युवा जदयू के नेता सह पूर्व उप प्रमुख पवन सिंह कहते हैं कि नाराज़ सदस्यों की लामबंदी हुई और विरोध की गतिविधि पूर्व से ही चल रही थी, जिसे समय रहते नहीं परखा जा सका. इसी का परिणाम है कि जिप अध्यक्ष की कुर्सी ब्रह्मदेव रावत से छिन गई. राजनीति के इस बदलाव में विपक्षी दल राजद भी राजनीति करने से नहीं चुक रहा है. राजद ज़िला अध्यक्ष अशोक राम की माने तो पिछड़े वर्ग का ज़िला परिषद अध्यक्ष सत्ताधारियों को पिछले कुछ दिनों से रास नहीं आ रहा था, जिस कारण अन्य जिप सदस्य उनके विरोध में लामबंद होने लगे और जिप अध्यक्ष को अपनी कुर्सी गवानी पड़ी.

नए जिप अध्यक्ष के लिए कई जगहों पर बैठक व जोड़-तोड़ का प्रयास शुरू हो चुका है. वहीं ज़िला परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव, विकास प्रसाद सिंह व अलीगंज की जिप सदस्या सावित्री देवी भी अपनी गिनती बढ़ाने में जुटी हैं. यह भी चर्चा है कि अति पिछड़ा वर्ग से किसी उम्मीदवार को कुर्सी सौंपी जा सकती है. ■

राजद जिला अध्यक्ष अशोक राम की माने तो पिछड़े वर्ग का जिला परिषद अध्यक्ष सत्ताधारियों को पिछले कुछ दिनों से रास नहीं आ रहा था, जिस कारण अन्य जिप सदस्य उनके विरोध में लामबंद होने लगे और जिप अध्यक्ष को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी.

feedback@chauthiduniya.com

चर्चा में हुज़ूर

मोदी के लिए जुटेंगे साधु-संत

इस बात की चर्चा ज़ोर पकड़ रही है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में पटना में साधु संतों का एक बड़ा जमावड़ा लगेगा. बताया जा रहा है कि देश भर के कई नामी गिरामी साधु संत इस आयोजन में भाग लेने पटना आएंगे. कहा जा रहा है कि धर्म जागरण के लिए यह आयोजन हो रहा है, पर अंदरखाने से यह बात सामने आ रही है कि ये साधु संत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए माहौल तैयार करेंगे और हो सकता है कोई अपील भी करें. चर्चा है कि इस आयोजन के पीछे भाजपा के एक बड़े नेता काफी सक्रिय हैं. दो दिनों के इस आयोजन से भाजपा को लगता है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक बहुत ही सकारात्मक संदेश लोगों के बीच जाएगा. गौरतलब है कि इलाहाबाद में कुंभ के दौरान भी साधु संतों की ओर से इस तरह की एक कोशिश की गई थी, पर नरेंद्र मोदी के नहीं आने से यह कोशिश परवान नहीं चढ़ पाई. बहरहाल पटना में होने वाले आयोजन को लेकर तैयारी जोर-शोर से चल रही है.■

राजद में टूट के आसार

राजद में इन दिनों हर बड़े नेता एक दूसरे को शक़ की निगाह से देख रहे हैं. चारा घोटाले में आने वाले फ़ैसले के बाद बनने वाली परिस्थितियों को लेकर पार्टी काफ़ी सशंकित है. पार्टी के पुराने लोग कहते हैं कि प्रतिकूल फ़ैसला आने के बाद भी लालू कोई नई व्यवस्था नहीं बनाएंगे और पुराने ढर्रे पर पार्टी चलती रहेगी. बहुत होगा तो राबड़ी देवी की सक्रियता बढ़ जाएगी. अभी बाढ़ को लेकर राबड़ी देवी अखबारों में दिखने भी लगी हैं. चर्चा है कि पार्टी का एक बड़ा तबका चाहता है कि पार्टी की कमान किसी दूसरे नेता को सौंपा जाए. ऐसा न होने पर नीतीश कुमार के साथ ऐसे नेताओं की नजदीकियां बढ़ सकती हैं. नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता उनके साथ जुड़े. विधानसभा में तो कई बार नीतीश इस ओर इशारा भी कर चुके हैं. नीतीश कुमार को लगता है कि अगर सिद्दीकी जैसा मुस्लिम चेहरा उनके साथ आता है, तो उनके ऑपरेशन मुस्मिल वोट को काफ़ी मदद मिलेगी. गौरतलब है कि सिद्दीकी की न केवल मुसलमानों में, बल्कि समाज के हर तबके में काफी इज्जत है. इस प्रकरण पर सिद्दीकी कहते हैं कि ऐसा चाहने वाले या फिर ऐसा अनुमान लगाने वाले, लगता है मुझे ठीक से जानते ही नहीं हैं. चर्चा है कि जदयू की नज़र शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी, ललित यादव व अख्तारुल इमान जैसे नेताओं पर भी है. इंतज़ार चारा घोटाले पर कोर्ट के फ़ैसले का हो रहा है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

» एक नज़र «

छात्रवृत्ति राशि का वितरण

नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत एसआर उच्च विद्यालय खगड़िया में छात्रवृत्ति राशि का वितरण किया गया. राशि का वितरण विद्यालय के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मनोनित सदस्य सह वार्ड पार्षद विजय कुमार यादव ने की. यादव ने उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों की मेहनत से ही राष्ट्र और समाज का विकास होता है. उन्होंने कहा कि विद्यालयों में चलाए जा रहे छात्रवृत्ति योजनाओं से शिक्षा को बढ़ावा मिला है और छात्र-छात्राएं विद्यालय से जुड़ने लगे हैं. वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक छोटेलाल शर्मा ने बताया कि 270 नवम एवं दशम वर्ग के छात्रों के बीच छात्रवृति राशि का वितरण किया गया, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 199 एवं अनुसूचित जाति के 71 छात्रों के बीच 18-18 सौ रुपये प्रति छात्र के दर से 4 लाख, 86 हज़ार रुपये का वितरण किया गया. इस अवसर पर शिक्षक वोकिल साह, मो. महमूद आलम, पवन कुमार, रामकृष्ण आनंद, मीरा कुमारी, रेखा कुमारी, मंजू झा एवं वार्ड सदस्य श्रवण गोयनका सहित अन्य लोग उपस्थित थे.

शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम

ज़िले के विभिन्न विद्यालयों में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई. इस मौक़े पर इंडियन पब्लिक स्कूल बाज़ार समिति गुलाब नगर के प्रांगण में बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया. वहीं विद्यालय के बच्चों ने चित्रकला एवं क्वीज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया. चित्रकला क्वीज में प्रथम स्थान सज्जन कुमार, द्वितीय स्थान हर्षराज तथा तृतीय स्थान कमल कुमार ने प्राप्त किया. सभी विजयी प्रतिभागी को विद्यालय के प्राचार्य विकास कुमार के द्वारा पुरस्कार एवं अन्य प्रतिभागी को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया. इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक विकास कुमार ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि डॉ. राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक एवं कुशल शिक्षक थे.

विश्वासघात दिवस मनाया

राज्य सरकार के वादा ख़िलाफ़ी पर नियोजित शिक्षकों ने राज्यस्तरीय कार्यक्रम के तहत शिक्षक दिवस को विश्वासघात के रूप में मनाया. इस मौक़े पर नियोजित शिक्षकों ने पंचायत, प्रखंड, नगर, प्रारंभिक शिक्षक संघ के ज़िला सचिव मनीष कुमार सिंह के नेतृत्व में 13 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया. सचिव मनीष कुमार सिंह ने विभिन्न मांगों सहित समान काम के लिए समान वेतन, आंदोलन के दौरान दर्ज मुक़दमे को वापस लेने, बिहार के विभिन्न जेलों में बंद शिक्षकों को बिना शर्त रिहाई एवं हड़ताल तथा जेल अवधि का वेतन भुगतान किये जाने की मांग की. सिंह ने 27 सितंबर के अधिकार यात्रा के दौरान हुई घटना सीबीआई से जांच कराने की बात कही. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2005 का याद दिलाते हुए कहा कि बिहार की जनता जंगल राज से छुटकारा पाने के लिए आपके द्वारा दिखाये गये, विकास वायदे में फंस कर मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया, लेकिन आपने बिहार की जनता को जंगल राज से निकाल कर महाजंगल राज में ला दिया है. इस अवसर पर शिक्षक पंकज राय, रवि शंकर कुमार, अनुज कुमार, श्याम नारायण, उपेंद्र कुमार, रजनीकांत, बशी आलम, मनोज कुमार, मीरा कुमारी, रंजना कुमारी, ललिता कुमारी, रेखा, सुधा, सुभाष, प्रवीण, मुकेश, जवाहर यादव सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित थे.

बाढ़ राहत जारी

बिहार के 20 ज़िले के लोग गंगा के किनारे बसे हैं, जो बाढ़ से प्रभावित हैं. राज्य सरकार इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है. उक्त बातें आपदा मंत्री डॉ. रेणू सिंह कुशवाहा ने खगड़िया परिसदन में प्रेस वार्ता के दौरान कही. उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी बाढ़ पीड़ितों के बीच भोजन के शिविर लगाकर पीड़ितों को भोजन कराया जायेगा. साथ ही पशुओं के लिए पशुचारा की व्यवस्था की जायेगी. प्रेस वार्ता के बाद आपदा मंत्री श्रीमति कुशवाहा ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर, बाढ़ पीड़ित परिवारों से मिलीं. कटाव स्थल का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ के पूर्व ही अगर बांध की मरम्मत की गई होती, तो आज यह नौबत नहीं आती. इस अवसर पर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, ज़िला जनसंपर्क पदाधिकारी दिलीप सरकार, बीडीओ सुनील कुमार, जदयू प्रवक्ता अरविंद मोहन, जदयू उपाध्यक्ष बब्लू कुमार मंडल, पुरुषोत्तम अग्रवाल सहित दर्जनों जदयू नेता उपस्थित थे.

– नंदकिशोर शर्मा

प्रतिनिधि ने किया सम्मानित

हंटरगंज प्रखंड के मुखिया संघ अध्यक्ष चंद्रदेव यादव के द्वारा डाहा पंचायत के उ.म. विद्यालय अहियापुर में शिक्षक दिवस का समारोह पूर्वक मनाने का एक नया तरीक़ा अपनाया. मुखिया चंद्रदेव यादव ने शिक्षकों को शॉल व पुस्तक देकर शिक्षकों को सम्मानित किया. वहीं सभा को संबोधित करते हुए उ. उच्च विद्यालय अकौना के शिक्षक किशोर कुमार ने बताया कि शिक्षक त्रिभुज का एक कोण है, जिसमें विद्यार्थी-शिक्षक एवं अभिभावक मिलकर ही राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं. वहीं उन्होंने बताया कि शिक्षक को केवल शिक्षण कार्य के लिए ही रखें. असैनिक कार्यों में शिक्षक को लगाकर शिक्षण कार्य को बाधित किया जा रहा है. वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह, हंटरगंज प्रमुख, दीपा भारती, शंभु यादव, फेकू दास, अरुण कुमार, रूपम यादव एवं विभिषण यादव ने सभा को संबोधित किया.

– अमरेन्द्र सिंह

मोटरसाइकिल जुलूस

मोतिहारी ज़िला जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए युवा जदयू के जिलाध्यक्ष साजिद रजा के नेतृत्व में युवा जदयू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल जुलूस निकाला और शहर का परिभ्रमण कर नगर भवन के मैदान में पहुंचे. जुलूस गोपाल साह उच्च विद्यालय से निकलकर चांदमारी, बलुआ, हॉस्पिटल चौक होते हुए सभा स्थल तक पहुंचा. जुलूस में युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र सिंह, वसीम अहमद खां, डॉ. सुनील, डॉ. उमेश चंद्रा, भोला यादव, विपिन श्रीवास्तव, मुकेश पटेल, कृष्णा कश्यप, लड्डू सिंह, संजीव सिंह, अख्तर हुसैन, मनोज श्रीवास्तव, अल्ताफ हैदर, सम्सी खां, तेजस्वी, कन्हैया पाठक, शिवजी साह, सज्जाद हुसैन, निक्की सिंह, डॉ. कुणाल, लखन कुमार समेत बड़ी संख्या में युवा जदयू कार्यकर्ता शामिल थे. इस अवसर पर अध्यक्ष साजिद रजा के नेतृत्व में राजा बाबू पांडेय, प्रकाश सिंह, सुजीत मशीह, मुन्नू सिंह, संतोष सिंह, छोटन सिंह, संतोष कुमार, नोयल जेम्स, पप्पू खां, टूसा खां, सुशील कुमार, सिद्धांत पटेल, झुन्नू सिंह, केके सिंह, प्रमोद प्रसाद, इकबाल नवाज, मो. तस्दीक, आबिद हुसैन, अख्तर आलम, तबरेज अंसारी व मो. फैय्याज ने विभिन्न दलों से इस्तीफा देकर जदयू की सदस्यता ग्रहण की.

– इंतेजारुल हक

दबंग ऑपरेटर

जिला सूचना जनसंपर्क कार्यालय पूर्णिया में पिछले 17 वर्षों से एक दबंग ऑपरेटर पदास्थापित है. इसकी दबंगता की चर्चा पूर्णिया समाहरणालय में ही नहीं, बल्कि प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय से लेकर सूचना जनसंपर्क निदेशालय पटना तक में होती है. कुछ स्थानीय कर्मियों ने जानकारी दी कि वह इतना दबंग है कि पदस्थापित पदाधिकारी को दिनदहाड़े कार्यालय में देख लेने की धमकी और नौकरी छोड़ने की भी हिदायत देता है. मालूम हो कि पूर्णिया ज़िला सूचना जनसंपर्क कार्यालय में विगत 17 वर्षों से ऑपरेटर के पद पर देवेंद्र राय पदस्थापित हैं. वह पूर्णिया समाहरणालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों से लेकर तृतीय श्रेणी के कई कर्मियों का राजनीतिक सलाहकार बना हुआ है. ऑपरेटर के ऐसे क्रियाकलाप से ख़ुद उनके ही विभाग के पदाधिकारी आहत हैं. ज़िला जनसंपर्क पदाधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह का कहना है कि बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर आधारित फिल्म प्रदर्शन के लिए लगभग 3 लाख की लागत से लाये गये प्रोजेक्टर को उनके द्वारा शॉर्ट लगाकर ख़राब कर दिया गया, ताकि उन्हें कार्य ना करना पड़े, जिससे अपनी राजनीति की चौकड़ी लगा सके और आराम फरमा सकें. ■

– नीरज

चौथी दुनिया को कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिसे पढ़ने व देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी उन्मूलन कार्यक्रम में अधिकांशत: निर्दोष अधिकारी ही फंस रहे हैं और खुलेआम रिश्वत लेकर जनता को ठगने वाले आराम से अपनी मंशा में कामयाब हो रहे हैं.

चंपारण

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बोलना मना है

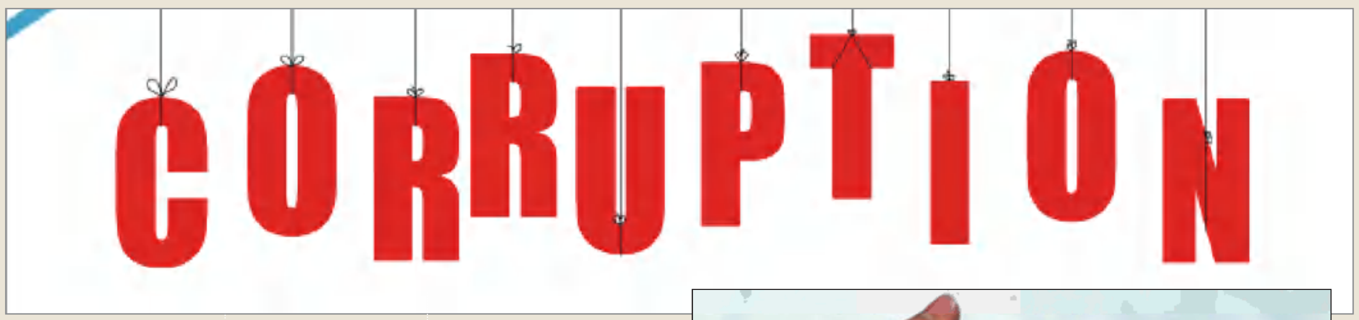

उमाशंकर राम

गौहर अंजुम

शमीम शाहवर्दी

नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बोलने पर सख्त पाबंदी है और जो लोग इसका विरोध करते हैं, उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है. यहां भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बोलने वालों पर झूठ और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन्हें निलंबित कर दिया जाता है.

इंतेजारुल हक़

नीतीश सरकार में सच बोलने वालों और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ खड़े होने की हिम्मत करने वालों पर इन दिनों क़हर टूट पड़ा है. उन्हें झुठा आरोप लगाकर निलंबित कर दिया जाता है. यही नहीं आर्थिक अपराध टीम द्वारा छोपेमारी भी की जाती है. चौथी दुनिया को कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिसे पढ़ने व देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की भ्रष्टाचारविरोधी उन्मूलन कार्यक्रम में अधिकांशत: निर्दोष अधिकारी ही फंस रहे हैं और खुलेआम रिश्वत लेकर जनता को ठगने वाले आराम से अपनी मंशा में कामयाब हो रहे हैं. हाल ही में एनइपी के निदेशक उमाशंकर राम के यहां आर्थिक अपराध की टीम द्वारा की गई छापेमारी व सुगौली में पदस्थापित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गौहर अंजुम का निलंबन शिक्षा विभाग स्थापना के कार्यक्रम पदाधिकारी अश्वनी कुमार को स्थापना से हटाकर कनीय पदाधिकारी भुषण कुमार को कार्यक्रम पदाधिकारी बनाया जाना इसका ज्वलंत उदाहरण है.

निदेशक श्री राम का कसूर सिर्फ़ इतना है कि उन्होंने इंदिरा आवास व मनरेगा में गड़बड़ी करने वाले कई प्रखंड विकास पदाधिकारियों पर जिलाधिकारी के सहयोग से नकेल कसा, जिसकी सराहना ज़िले भर में की गई. पूर्वी चम्पारण ज़िले के बंजरिया, संग्रामपुर एवं रक्सौल समेत कई प्रखंडों में तैनात प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी व इंदिरा आवास योजना में की गई गड़बड़ी को उन्होंने पकड़ा था. भ्रष्ट अधिकारियों को उनकी यह शैली पसंद नहीं आई और आर्थिक अपराध की टीम से उनके आवास पर छापेमारी करवा दी. भले ही टीम को यहां कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन वे निलंबित हो गये. यहां बताते चलें कि छापेमारी में कुछ मिले या न मिले, लेकिन नियमानुसार अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई ज़रूर कर दी जाती है. इसी तरह का मामला सुगौली के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गौहर अंजुम के साथ हुआ. गौहर का भी कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने सुगौली प्रखंड के मध्यमलती व छपरा बहास स्थित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा किये गये तेरह लाख रुपये का घोटाला पकड़ा. इसकी सूचना उन्होंने अपने आलाधिकारियों को दी. जांच प्रतिवेदन देने के बावजूद उक्त प्रधानाध्यापकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उल्टे उनकी प्रतिनियुक्ति दूसरे विद्यालय में कर दी गई. जांच प्रतिवेदन के अनुसार, राजकीय मध्य विद्यालय छपरा बहास में 4 लाख, 6 हज़ार व मध्यमलती विद्यालय में 7 लाख, 35 हज़ार, 223 रुपये का घोटाला हुआ है. मध्यमलती विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक राकेश कुमार गुप्ता द्वारा अन्य कई गड़बड़ियां भी की गई है और विभागीय नियम को ताक़ पर रखकर काम किया गया है. चिकनौटा कन्या (विद्यालय), सुगौली के प्राचार्य भैरवनाथ पांडेय द्वारा इग्नू प्रशिक्षण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और प्रशिक्षण के नाम पर केवल खानापूर्ती कर राशि का बंदरबांट किया गया है. प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों से 1-1 हज़ार रुपये की अवैध उगाही की गई है और ग्रेड के नाम पर शिक्षकों को ठगा गया है. जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती अंजुम ने इस घोटाले की जांच की तो तमाम मामले उजागर हुए और ज़िला शिक्षा पदाधिकारी को 8 दिसंबर, 2011 को पत्र लिखकर उन्होंने कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी. भेजे प्रतिवेदन में श्रीमती अंजुम ने स्पष्ट किया था कि पांडेय द्वारा असाइनमेंट के नाम पर प्रत्येक शिक्षक से 3 हज़ार से 10 हज़ार रुपये की अवैध उगाही की गई है. रिश्वत नहीं देने वाले शिक्षकों को अनुत्तीर्ण कराने की धमकी भी दी गई. इसी तरह उन्होंने राजकीय मध्य विद्यालय छपरा बहास में मध्याह्न भोजन योजना के चावल को काला बाजार में बेचने के लिए रखा गया था, जिसे उन्होंने पकड़ा. तब उन पर झूठा मुक़दमा कर दिया गया. यहां 47 बोरा चावल कालाबाजारी में बेचने के लिए रखा गया था. इतना ही नहीं, विद्यालय की कोई भी पंजी अपडेट नहीं मिली. यहां के लोगों का कहना है कि गौहर को फंसाने की साजिश पिछले दो वर्षों से चल रही थी. जब कोई बहाना नहीं मिला तो अंत में प्रखंड शिक्षक नियोजन 2012 की अंतिम मेघा सूची के प्रकाशन में गड़बड़ी करने व उत्क्रमित मध्य विद्यालय के एक पूर्व प्राचार्य का वेतन बेवजह रोकने का आरोप लगाकर निलंबित कर दिया गया. सबसे चौंकाने वाला तथ्य तो यह है कि शिक्षक नियोजन समिति का अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख होता है, जबकि बीडीओ इसके सचिव होते हैं. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भूमिका सिर्फ एक सदस्य के रूप में होती है. अगर शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी हुई तो इसकी ज़िम्मेदारी प्रखंड प्रमुख की होती है न की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर. क्या अध्यक्ष की मौजूदगी में सदस्य इतनी बड़ी ग़लती कर सकता है? गड़बड़ी हुई तो जिलाशिक्षा पदाधिकारी ने उक्त सूची का सत्यापन क्यों किया? चंपारण की जनता जिलाशिक्षा पदाधिकारी विनोदानंद झा से सवाल पुछ रही है. दूसरी तरफ़ जिले के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सैय्यद शमीम अख्तर उर्फ शमीम शहवर्दी इसके लिए जिलाशिक्षा पदाधिकारी को सीधे दोषी ठहराते हुए बताते हैं कि खुलेआम रिश्वत लेने वाले आराम से घुम रहे हैं और सरकार की मंशा के अनुकूल काम करने वाले अधिकारियों को एक साजिश के तहत परेशान किया जा रहा है. उनका आरोप यह भी है कि गौहर को एक मुस्लिम महिला समझ कर फंसाया गया है. ■

सुगौली के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गौहर अंजुम का कसूर सिर्फ़ इतना है कि उन्होंने सुगौली प्रखंड के मध्यमलती व छपरा बहास स्थित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा किये गये तेरह लाख रुपये का घोटाला पकड़ा. इसकी सूचना उन्होंने अपने आलाधिकारियों को दी, लेकिन जांच प्रतिवेदन देने के बावजूद उक्त प्रधानाध्यापकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उल्टे उनकी प्रतिनियुक्ति दूसरे विद्यालय में कर दी गई. जांच प्रतिवेदन के अनुसार, राजकीय मध्य विद्यालय छपरा बहास में 4 लाख, 6 हज़ार व मध्यमलती विद्यालय में 7 लाख, 35 हज़ार,

feedback@chauthiduniya.com

चर्चा है हुज़ूर

दुविधा में उपेंद्र

रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा दुविधा में हैं. भाजपा के साथ तालमेल का किस्सा क्लाइमेक्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा है. भाजपा में बैठे कुछ नेता उपेंद्र कुशवाहा की राह में रोड़ा बनते दिख रहे हैं. भाजपा नेताओं की राय है कि उपेंद्र कुशवाहा को बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका एक ख़ास वर्ग और इलाक़े में ही जनाधार है, लेकिन दिल्ली में भाजपा के कई बड़े नेता ऐसा नहीं मानते. ये नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ तालमेल करने के पक्ष में हैं और उनका तर्क यह है कि इस गठबंधन से भाजपा को बिहार के चुनावों में बहुत फ़ायदा होगा. भाजपा में फैली इस विचारधारा ने उपेंद्र कुशवाहा को भी दुविधा में डाल दिया है. इसलिए वह अब यह भी कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार के शासन को ख़त्म करेगा, हम उसी के साथ तालमेल करेंगे. मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सभी विकल्प खोल रखे हैं. जानकार बताते हैं कि पेंच सीटों की संख्या व क्षेत्र को लेकर फंस रहा है. भाजपा चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा के कुछ उम्मीदवार कमल के निशान पर चुनाव में उतरें. कुशवाहा को यह शर्त रास नहीं आ रही है. यही वजह है कि तालमेल की गाड़ी बढ़ नहीं रही है. उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि अभी तालमेल पर टिप्पणी करना जल्दबाज़ी होगी.

नागमणि के सपने

राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष नागमणि इन दिनों बड़े-बड़े सपने देख रहे हैं. नागमणि का दावा है कि अगले चुनाव के बाद सूबे का अगला मुख्यमंत्री वहीं बनेंगे. इसके पीछे उनका तर्क यह है कि बिहार की जनता लालू और नीतीश दोनों से काफ़ी निराश हो चुकी है. वह कहते हैं कि ऐसे में मैं ही तीसरा विकल्प हूं. अबकी बार कोई कुशवाहा ही इस कुर्सी पर बैठेगा और इसके लिए मैं सबसे उपयुक्त हूं. मैं बिहार की जनता की पहली पसंद हूं. मुझे हर जाति व वर्ग का समर्थन हासिल है. चुनाव नजदीक आते ही राकांपा के पक्ष में बड़ा ध्रूवीकरण होगा और बिहार में तीसरे मोर्चे की सरकार बन जाएगी.

साधु जप रहे नमो नमो

आपको जानकर शायद हैरत हो पर यह सच है कि इन दिनों किसी भाजपाई से कहीं ज़्यादा साधु यादव नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं. वह कहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी के हाथों ही यह देश सुरक्षित रह सकता है. गुजरात का विकास साधु यादव को इतना रास आ रहा है कि वह अपनी पार्टी कांग्रेस को भी नरेंद्र मोदी से कुछ सीखने की सलाह दे रहे हैं. नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर साधु यादव को ज़रा सा भी अफसोस नहीं है. वह कहते हैं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया. दुनियाभर के लोग नरेंद्र भाई से मिलते हैं. मेरी उनसे मुलाकात को बेवजह हौव्वा बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ज़िला इकाई की नोटिस का मैं कोई जबाव नहीं दूंगा. हां, अगर सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी की ओर से कोई नोटिस आता है, तो मैं जवाब ज़रूर दूंगा. साधु यादव कहते हैं कि गांव-गांव में नमो नमो का जाप हो रहा है, अब अगर किसी को यह सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं. साधु यादव का कहना है कि मेरी वजह से कांग्रेस को चुनावों में फ़ायदा हुआ न कि मुझे कभी कांग्रेस से कोई फ़ायदा मिला.

जदयू से लड़ेंगे अवनीश

भाजपा के वरिष्ठ नेता अवनीश कुमार सिंह के जदयू की टिकट पर मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा इन दिनों ज़ोरों पर है. चर्चा है कि अवनीश कुमार मोतिहारी लोक सभा क्षेत्र से जदयू के प्रत्याशी होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बाबत उनकी बात पक्की हो गई है. उन्होंने अंदर ही अंदर इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है और अपने राजनीतिक सलाहकारों के साथ जोड़-घटाव कर रहे हैं. जानकार सूत्र बताते हैं कि अवनीश कुमार जल्द ही भाजपा का दामन छोड़ेंगे और जदयू में जायेंगे. अगर ऐसा हुआ तो चंपारण समेत उत्तर बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आएगा और अंदरूनी कलह से जुझ रही भाजपा को एक बड़ा धक्का लगेगा. राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि अवनीश कुमार के मोतिहारी लोक सभा क्षेत्र से प्रत्याशी होने पर भाजपा व राजद का वोट बैंक एक तरफ़ ध्वस्त हो जाएगा, वहीं सांसद राधामोहन सिंह को भी एक बड़ा झटका लगेगा. अवनीश कुमार सिंह फिलहाल चिरैया विधान सभा क्षेत्र के विधायक हैं और चंपारण में भाजपा के एक मजबूत पिलर भी हैं. यहां बताते चलें कि मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के अंदर मोतिहारी, पिपरा, केसरिया, कल्यानपुर, हरसिद्धि व गोविंद्र गंज विधान सभा क्षेत्र आता है. इनमें पिपरा, गोविंदगंज व कल्याणपुर विद्यान सभा क्षेत्रों पर जदयू का क़ब्ज़ा है, जबकि शेष पर भाजपा का. ■

– चौथी दुनिया ब्यूरो

चौथी दुनिया

23 सितंबर-29 सितंबर 2013

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड

सास-बहू के मिलते-जुलते सियासी समीकरण

गरीबी हटाओ से भुखमरी मिटाओ तक

इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर देश की जनता का ध्यान कांग्रेस की ओर खींचा था. ठीक इसी तर्ज पर सोनिया गांधी ने भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले खाद्य सुरक्षा बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाकर भुखमरी मिटाओ जैसा संदेश देने की कोशिश की है. हालांकि, कांग्रेस के हाथ कॉमनवेल्थ, टूजी और कोयला घोटाले की कालिख से रंगे हैं. खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भी राजनीतिक गलियारे में खासी हलचल मचाई. अब देखना यह है कि सोनिया की यह रणनीति कितनी कारगर साबित होती है.

दर्शन शर्मा

कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भले ही प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठी हों, लेकिन सोनिया की सियासी चालें उनकी सास इंदिरा गांधी से काफी हद तक मेल खाती हैं. जिस तरह इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर देश की जनता का ध्यान कांग्रेस की ओर खींचा था. ठीक इसी तर्ज पर सोनिया गांधी ने भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले खाद्य सुरक्षा बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाकर भुखमरी मिटाओ जैसा संदेश देने की कोशिश की है. खाद्य सुरक्षा बिल पास होने के बाद विपक्षी दलों में हलचल मच गई है. राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर जोर-शोर से बहस चलने लगी है. इस बिल के पास होने के बाद रसातल में जा रही कांग्रेस को एक बार फिर सोनिया ने संजीवनी प्रदान की है. अगर जनता के बीच इस खाद्य सुरक्षा बिल का सही और सटीक क्रियान्वयन किया गया, अगर जनता को उसकी इस घोषणा पर भरोसा हुआ, तो कांग्रेस लोकसभा में हैट्रिक लगा सकती है. भले ही उसके हाथ कोयला, टू जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम जैसे घोटालों की कालिख से रंगे हों.

हालांकि इस बिल के पास होने में संप्रग सरकार को समर्थन दे रहे समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह ने इसे किसान विरोधी करार दिया था, लेकिन बाद में उनके तेवर ठंडे पड़ गए. उनका यह जुमला बार-बार दोहराना कि वह सांप्रदायिक ताकतों को न बढ़ने देने के लिए कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस उनका एहसान मानती है. मुलायम सिंह बीच में गीदड़ भभकी जरूर देते रहते हैं, लेकिन अंततोगत्वा जो कांग्रेस चाहती है, वे वही करते हैं. उत्तर प्रदेश में आने पर उनके स्वर वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए भले ही बदल जाते हों, लेकिन हकीकत यह है कि मुलायम सिंह ने अभी तक न तो सोनिया के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर रायबरेली में अपना प्रत्याशी उतारा है और न ही राहुल के संसदीय क्षेत्र में उनका प्रत्याशी खड़ा हुआ है. सपा 76 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है. मुलायम के संप्रग को समर्थन से उत्तर प्रदेश को विकास के लिए केंद्र सरकार ने समय-समय पर वित्तीय सहायता देने में कहीं कोताही भी नहीं बरती है. आय से अधिक संपत्ति के मामले में परेशान मुलायम को हमेशा सीबीआई का डर सताता रहा है. वहीं वह अपने मुख्यमंत्री बेटे अखिलेश को भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में बचाते आ रहे हैं. उम्मीद यहां तक बन चुकी है कि देर सबेर इस फंदे से छुड़ाने में प्रत्यक्ष अथवा परोध रूप से संप्रग सरकार का उन्हें सहारा मिल सकता है. मालूम हो कि इसके पहले संप्रग सरकार को समर्थन दे रही बसपा सुप्रीमो मायावती को आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लीन चिट मिल गई है. यह भी सोनिया की सियासी गणित का एक सूत्र है. इसी तरह सोनिया के कई समीकरण इंदिरा गांधी के सियासी गुणा भाग से ओतप्रोत हैं.

सोनिया गांधी ने जमीनी 2005 में देश के मजदूरों के लिए मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना जनता के सामने पेश की. उसकी बदौलत संप्रग टू में जनता ने अप्रत्याशित ढंग से कांग्रेस का साथ दिया. हालांकि मनरेगा का पूरा लाभ मजदूरों को न मिलकर मठाधीशों को मिला है. इस बात को लेकर संप्रग सरकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर तोहमत लगाती है कि इस योजना का सही क्रियान्वयन राज्य सरकारों ने नहीं किया, जिसके कारण निचले स्तर के लोगों को सही लाभ नहीं मिल पाया है. संप्रग टू का कार्यकाल बीतने वाला है. चुनाव होने में कुछ ही महीने शेष हैं. ऐसे में सोनिया गांधी ने आनन-फानन में फिर वही हाथ आजमाए हैं, जैसा कि पिछले लोकसभा चुनावों में कर दिखाया था और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी. अब कांग्रेस अध्यक्ष संप्रग-3 का सपना देख रही हैं. मोदी का मुंह बंद करने के लिए सोनिया ने वोटों का खजाना माने जाने वाले खाद्य सुरक्षा बिल और पेंशन बिल को पास कराकर अपना अमोघ अस्त्र विपक्ष पर तान दिया है. सोनिया के इस हथकंडे को देखकर राजनीति के जानकार मानने लगे हैं कि सोनिया की इस रणनीति ने एक बार फिर इंदिरा गांधी की यादव दिलाई है.

इंदिरा गांधी हवा के खिलाफ दो टूक फैसले लेने के लिए जानी जाती थीं. इनकी निर्णय क्षमता पर आलोचक भी सवाल नहीं खड़े करते थे. 1967 के बाद चाहे वह पार्टी के आधिकारिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी की जगह वीवी गिरि को समर्थन देना हो, या फिर बैंक राष्ट्रीयकरण करना और प्रिवीपर्स खत्म करना रहा हो या 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए सेना भेजना हो, या फिर 1984 में स्वर्ण मंदिर से चरमपंथियों को निकालना रहा हो, एक बार तय करने के बाद इंदिरा गांधी हिचकी नहीं. किसी मामूली नेता के लिए सत्तर के दशक में आपातकाल लागू करने का फैसला आसान नहीं होता. इंदिरा गांधी ने न केवल फैसला किया, बल्कि गलती का एहसास होते ही आपातकाल हटा भी लिया. हालांकि, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी. सोनिया का भी राजनीतिकि तजुर्बा कम नहीं है. उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए बिसातें बिछानी शुरू कर दी हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा गांरटी जैसे बिल अहम भूमिका अदा करेंगे.

बहरहाल संसद में खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना से संबंधी विधेयक पारित हो गया है, जिसके अंतर्गत 65 प्रतिशत से अधिक आबादी को तीन रुपये किलो चावल, दो रुपये किलो गेहूं तथा एक रुपये किलो की दर से मोटा अनाज उपलब्ध कराया जाएगा. हर माह एक व्यक्ति को 35 किलो तक अनाज मिलेगा. तीन राज्यों दिल्ली, हरियाणा तथा उत्तराखंड में पहली सितम्बर से यह योजना लागू भी हो गई है. देर-सबेर यूपी में भी लागू होनी है. लेकिन लागू करने वाली मशीनरी ध्वस्त है. 60 फीसदी लोगों के पास राशन कार्ड तक नहीं हैं. राशनकार्ड विहीन लोगों में वे परिवार भी हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है और रातें फुटपाथों पर गुजारने को मजबूर हैं. घुमंतू जातियां बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. करीब दो दर्जन जिलों में हुए खाद्यान्न घोटाले की सीबीआई जांच सालों से चल रही है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही है. योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति एवं परिवार के पास राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड भी होना चाहिए, लेकिन यूपी में 20 फीसदी से ज्यादा लोगों को आधार कार्ड बने ही नहीं हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार, यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ से ऊपर है. तीस फीसदी जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करती है. इस प्रकार 6 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि राज्य सरकार को खाद्य सुरक्षा योजना लागू करने की कोई जल्दी नहीं हैं. केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित कराया है और बहुत सारी चीजों का उत्तर प्रदेश सरकार को सामना करना पड़ेगा. इस योजना पर बहुत ज्यादा खर्च होगा. वहन संबंधी खर्च तथा अन्य मुद्दों पर सरकार विचार करके तय करेगी कि वह इस भार को उठा पाएगी या नहीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

आईटी हब बनेगा यूपी : अखिलेश

रवि प्रकाश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नेसकॉम के नोएडा में मुख्यालय बनाए जाने पर बेहद प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार आईटी क्षेत्र में प्रदेश को देश में सर्वोच्च स्थान पर लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है. उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती पर नेसकॉम का स्वागत करते हुए कहा कि नेसकॉम एक ऐसा संगठन है, जो विश्व स्तर पर सॉटवेयर, कन्सल्टेशन, बीपीओ और हार्डवेयर के क्षेत्र में कार्य कर रहा है. अखिलेश यादव ने यह बात दिल्ली के ताज मानसिंह होटल में नेसकॉम मुख्यालय, नोएडा के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पूंजी निवेश और व्यापारिक गतिविधियों का वातावरण बनाए जाने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जा रही है, जिसके फलस्वरूप कई सफल कंपनियों ने यहां पूंजी निवेश की इच्छा जाहिर की है. आज भी प्रदेश में कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों जैसे-एचसीएल, विप्रो, टीसीएस, सीएससी, बिरला सॉफ्ट, एक्सेंचर, सेपियन्ट, पाटनी, आईबीएम आदि द्वारा बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है.

यादव ने इच्छा जाहिर की कि नोएडा के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जनपदों में भी सूचना प्रौद्योगिकी के लोग पहुंचें. निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं इस पर आधारित सेवाओं की कंपनियों को सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 लागू की गई है. इसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपये या इससे अधिक के मेगा प्रोजेक्ट्स स्थापित करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी इनेबल्ड सर्विस इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की कोशिशों के फलस्वरूप प्रदेश के औद्योगिक ढांचे में निरंतर सुधार हो रहा है. नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में विकसित एवं समन्वित औद्योगिक टाउनशिप स्थापित हुई है. प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आईटी सिटी का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि प्रदेश के विभिन्न शहरों में आईटी पार्क भी स्थापित किए जाने की कार्यवाही तेजी से चल रही है. राज्य सरकार का यह प्रयास है कि वह उत्तर प्रदेश को एक अंतरराष्ट्रीय आईटी हब के रूप में विकसित करे. वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत का छठवां सबसे बड़ा आईटी निर्यातक और उत्तर भारत का आईटी हब भी है. इस पूरे क्षेत्र में इसकी भागीदारी 35 प्रतिशत है. इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा का योगदान आज किसी से छिपा नहीं है. प्रदेश में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में शिक्षण का कार्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों सहित आईटीआई आदि में बड़े पैमाने पर हो रहा है. इस प्रदेश में आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, आईटी-बीएचयू जैसे संस्थान भी अपना योगदान दे रहे हैं. राज्य सरकार ने अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति-2012 लागू की है, जिसका उद्देश्य पूंजी निवेश को आकर्षित करते हुए वर्तमान निवेशकों को और सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे औद्योगिक क्षमता का विकास किया जा सके. प्रदेश में कई परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है, जिसमें आईटी सिटी, डेयरी प्लांट, टेक्सटाइल पार्क, आईटी पार्क, मेगा लेदर क्लस्टर, मेगा फूड पार्क, मेट्रो रेल जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं. अखिलेश ने बताया कि विद्युत उत्पादन एवं वितरण में भी प्रभावी कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे. सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लागू किए जाने की दिशा में भी कार्रवाई की गई है. राज्य सरकार के प्रयासों के चलते प्रदेश में व्यापार और औद्योगिक विकास का वातावरण बना है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार समुचित कदम उठा रही है. हम प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा का माहौल देना चाहते हैं. इसलिए प्रथम चरण में प्रदेश के चार शहरों में आधुनिकतम पुलिसिंग व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं. यहां महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस सिस्टमयुक्त गाड़ियां पुलिस को मुहैया कराने जा रहे हैं. दूसरे चरण में इस योजना के अंतर्गत अन्य शहरों को भी लिया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार व्यापार, उद्योग और आर्थिक विकास की दिशा में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी. नेसकॉम के सदस्यों को लखनऊ आमंत्रित किया है, जहां राज्य के विकास के लिए एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का सुझाव दिया. इसके पूर्व एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी जीवेश नंदन तथा नोएडा अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रमारमण तथा नेसकॉम के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति, भविष्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला. ■

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

सत्ता के नशे में चूर अखिलेश सरकार

किसानों की भूमि पर क़ब्ज़े की कोशिश

किसानों और ग़रीबों की हमदर्द बनने वाली प्रदेश की समाजवादी सरकार अपने एजेंडे और चुनावी वायदों की पोटलियों व ग़रीब किसानों के वोट बैंक के सहारे केंद्र में बैठने का सपना देख रही है. लेकिन कार्यकर्ता हैं कि नेताजी मुलायम सिंह यादव का प्रधानमंत्री बनने का मंसूबा पूरा होने नहीं देना चाहते.

सैयद शावेज़ फ़िरोज़

एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार और युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उनकी पार्टी किसानों की हितैषी है, दूसरी ओर उनके कार्यकर्ता सत्ता के नशे में चूर हैं. वे आए दिन कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करने से बाज़ नहीं आ रहे हैं. ताज़ा मामला सूबे के जनपद चंदौली की तहसील चकिया का है. यहां सपाइयों ने दबंगई दिखाकर लठियां ग्राम सभा के बशारिकपुर गांव अंतर्गत पूर्व काशी नरेश की कृषि योग्य भूमि पर कब्जे की कोशिश की. लठियां ग्राम प्रधान के इशारे पर सपा कार्यकर्ताओं ने 6 अगस्त को न सिर्फ़ किसानों को डराया-धमकाया, बल्कि बुरी तरह मारपीट कर घायल भी कर दिया. मामले ने तूल पकड़ा तो दोनों पक्षों में टकराव हुआ, लाठियां चटकीं, जिसमें सत्ता पक्ष के एक व्यक्ति की मौत भी हो गई. मामले की जानकारी होते ही जिला प्रशासन से लेकर मंडल स्तर तक के अधिकारियों में हड़कंप मच गया. विवादित स्थल को लेकर धरना-प्रदर्शन प्रारंभ हुआ और मान-मनौव्वल पर समाप्त हो गया. इस मामले में एसडीएम चकिया जितेंद्र मोहन सिंह पर गाज गिरी. उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया.

दरअसल, मामला यह है कि पूर्व काशी नरेश स्वर्गीय डॉ. विभूति नारायण सिंह की बैराठ फ़ार्म की भूमि नियत प्राधिकारी के द्वारा सीलिंग क़ानून के अंतर्गत सीलिंग से अतिरिक्त घोषित कर दी गई थी. जिसके विरुद्ध डॉ. विभूति ने अपर आयुक्त वाराणसी के न्यायालय में अपील दाखिल किया था. न्यायालय अपर आयुक्त वाराणसी ने इस अपील को 21 फ़रवरी, 1990 में खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया कि अतिरिक्त घोषित भूमि पर डॉ. विभूति नारायण सिंह का नाम काट कर खतौनी में उत्तर प्रदेश सरकार का नाम दर्ज किया जाए और संबंधित भूमि पर क़ब्ज़ा लेकर सूचना उपलब्ध कराई जाए. 8 मई, 1990 व 1 जून, 1990 को भूमि आलेख निरीक्षक द्वारा तहसीलदार चकिया द्वारा उच्चाधिकारियों को इस बात से अवगत कराया गया कि उक्त बैराठ फ़ार्म की भूमि पर उत्तर प्रदेश सरकार का क़ब्ज़ा हो गया है. पूर्व काशी नरेश ने इस आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दाखिल की, जिस पर उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार किया और 11 मई, 1990 को यह आदेश पारित किया कि भूमि से याचिकाकर्ता को बेदखल न किया गया हो तो उसे बेदखल न किया जाए. इस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि श्यामलाल कुशवाहा ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद

में इस बात का हलफ़नामा प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश सरकार का बैराठ फ़ार्म पर क़ब्ज़ा हो चुका है. जिस पर न्यायालय का उक्त आदेश निष्प्रभावी हो गया. पूर्व काशी नरेश ने पुन: स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय में दाखिल किया. जिस पर न्यायालय द्वारा 28 जनवरी, 1992 को आदेश पारित किया गया कि दौरान-ए-मुक़दमा उक्त भूमि का आवंटन न किया जाए. चूंकि अब बैराठ फ़ार्म की भूमि उत्तर प्रदेश सरकार की हो गई, इसलिए इसके आवंटन पर रोक लगी थी.

इस तथ्य को जानते हुए मार्क्सवादी पार्टी ने जनहित व राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए ज़मीन को जोतने-बोने के लिए न्यायालय में ठोस पैरवी करते हुए मुक़दमे का निस्तारण कराने के उद्देश्य से 1995 में एक ज़बरदस्त आंदोलन छेड़ा था. जो तक़रीबन तीन वर्ष तक चला. 28 नवंबर, 1998 को एसडीएम चकिया व क्षेत्राधिकारी चकिया प्रथम पक्ष तथा मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के तत्कालीन जिला मंत्री बच्चन सिंह को द्वितीय पक्ष और काशी नरेश के मैनेजर कैप्टन दशरथ सिंह तृतीय पक्ष के बीच एक समझौता पत्र लिखा गया, जिसके अनुसार बैराठ फार्म के एक छोटे भाग पर दशरथ सिंह द्वारा तथा फ़ार्म के बड़े भाग पर बच्चन सिंह के निर्देशन में आंदोलनकारी किसानों को खेती करने की अनुमति दी गई. बच्चन सिंह द्वारा आंदोलनकारियों में मुसहर, चमार व अन्य पिछड़ी जाति के लोग थे. इन सबकी एक किसान सहकारी समिति बनाकर भूमि पर जोताई-बोआई का काम शुरू किया गया. तभी से अब तक बैराठ फ़ार्म में किसान खेती करते चले आ रहे हैं.

जून 2013 में बैराठ फ़ार्म के आसपास के दबंग, असामाजिक और स्वार्थी तत्वों का एक गठजोड़ बना. जिसने फ़ार्म पर खेती कर रहे सहकारी समिति के किसानों को आतंकित कर भगा देने, उनके घरों व ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर लेने की नियत से उपद्रव शुरू किया. इन उपद्रवियों को सपा के कुछ क्षेत्रीय नेताओं ने शह दी. लठियां गांव सभा के प्रधान कल्लू यादव के नेतृत्व में असामाजिक तत्वों व गुंडों ने महिलाओं को बेइज़्ज़त किया और लूटपाट करते हुए खपरैल व झोपड़ियां तहस-नहस कर डालीं. जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज है. यही नहीं, लकड़ी बेचकर आ रहे एक मुसहर और एक चमार को दबंगों ने मारा-पीटा और लूट लिया. इस तरह की घटनाएं माह भर से लगातार हो रही हैं. जिसकी सूचना चकिया कोतवाल से लेकर सभी उच्चाधिकारियों तक लिखित तौर पर पहुंचाई जा चुकी है, जिस पर सपा के क्षेत्रीय नेताओं व जन प्रतिनिधियों के भारी दबाव में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर सका. इससे दबंगों का मनोबल बढ़ा हुआ है.

6 अगस्त, 2013 को जब समिति के किसान ट्रैक्टर से ज़मीन की जोताई कर रहे थे. तब लगभग दो बजे प्रधान व उनके साथ के दबंगों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर लाठी, बल्लम और बंदूक से किसानों पर हमला बोल दिया. तीन पुरुष और तीन महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गईं, वहीं एक हमलावर सुरेश शर्मा की मृत्यु हो गई. बैराठ फ़ार्म पर आज भी सत्ता पक्ष से जुड़े दबंगों का आतंक जारी है और छोटी-मोटी घटनाएं रोज़ घट रही हैं. संबंधित थानों में इन घटनाओं की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, बल्कि उल्टे किसानों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन से जुड़े नुमाइंदों पर फ़र्ज़ी प्राथमिकियां दर्ज कराई गई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

बाढ़ से बर्बाद हुए किसान

दर्शन शर्मा

उत्तर प्रदेश सरकार ने माना है कि प्रदेश के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार ने धन मुहैया करा दिया है. सबसे बुरा हाल बनारस का रहा है, जहां कई दशकों के बाद ऐसी भीषण बाढ़ आई है. बाढ़ की त्रासदी झेल रहे प्रदेश के किसान अभी तक उबर नहीं सके हैं. उनके घर-मकान डूब गए. घर-गृहस्थी नष्ट हो गई. खेतों में लहलहाती खड़ी फसलें पानी से बर्बाद हो गई हैं. लोग अन्न के एक-एक दाने के लिए तरस गए. जानवरों को चारे की समस्या खड़ी हो गई है. लोग भूख और प्यास और डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों से परेशान हैं. बाढ़ पीड़ितों का मानना है कि उनके वोट के लिए राजनेता उनके पीछे-पीछे घूमते हैं, मगर जब उनके ऊपर आपत्ति आती है, तो वे दूर-दूर तक नजर नहीं आते हैं. लैपटॉप बांटने में मशगूल सरकार के मुलाजिम परेशानी के समय झांकने भी नहीं आते. राहत के नाम पर बंदरबांट होती है. जो कुछ मिला, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान होता है. जनता भाग्य के भरोसे मरती-जीती है. गौरतलब है कि बनारस, इलाहाबाद, बलिया जैसे दर्जनों जिलों के लोग भयावह बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए. लोग जान जोखिम में डालकर पानी से डूबे घरों की छतों पर बैठे रहे. तमाम लोगों ने मठों और मंदिरों में शरण ली. तमाम घर-बार छोड़कर रिश्तेदारों के यहां पलायन कर गए. चोर-उचक्कों के कारण लोग जहां रातें जाग-जागकर रात बिताते रहे, वहीं हज़ारों लोग खुले आसमान के नीचे भीगते रहे. बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना रहा कि सरकार ने उनकी कोई चिंता नहीं की है. सरकार को उनकी सुध तब आई, जब नदियों का पानी कुछ कम हुआ. हालांकि बाढ़ की जंग लड़ रहे लोगों की बेहाली की खबरें लगातार सुर्खियों में छाई रहीं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए आगाह किया था कि जिन-जिन स्थानों पर बाढ़ आई है, कार्यकर्ता पूरी तत्परता से पीड़ितों की मदद करें. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है प्रदेश कानून व्यवस्था के संकट से गुजर रहा है. तुष्टीकरण में मशगूल है. इसे न किसान के खेतों में बाढ़ से उजड़ी फसल की चिंता है और न ही मजदूरों की. बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा को कोई सुनने वाला ही नहीं है. वे भगवान भरोसे जीते और मरते रहे हैं. बाढ़ में सैकड़ों की जानें चली गई हैं. जानवरों को चारा नहीं मिल पा रहा है. लेकिन राज्य के काबीना मंत्री शिवपाल सिंह का कहना है कि राज्य में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर दिए थे. उन्होंने संबंधित आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी तरह से बाढ़ पीड़ितों की मदद में कोताही न बरतें. वे मौके पर जाकर लगन और निष्ठा के साथ राहत का स्थलीय निरीक्षण करें और पीड़ित परिवारों के लिए दवाइयां, खाद्य सामग्री व पशु आहार उपलब्ध कराएं. राहत कार्यों में जो भी लापरवाही बरतेगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि राहत एवं बचाव आयुक्त एल वेंकटेश्वर लू के अनुसार अधिकांश स्थानों पर बाढ़ का पानी कम हो रहा है. हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं. राहत एवं बचाव कार्य के लिए सभी जिलों में धनराशि उपलब्ध करा दी गई है. आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए लगभग 98.33 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए भी 78.05 करोड़ रुपये जारी किए गए तथा बाढ़ से अति प्रभावित जिलों-वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर तथा बलिया में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तैनात की गई. बाढ़ से विभिन्न जनपदों की लगभग 14 लाख 26 हजार 213 लोग प्रभावित हैं. उनके लिए अनाज वितरण का काम तेजी से चलाया जा रहा है, वहीं पशुओं के चारे की भी व्यवस्था बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में की जा रही है. जिन जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया है, उनमें इलाहाबाद, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, फैजाबाद, गाजीपुर, अमेठी, बलिया, बलरामपुर, औरैया, गोरखपुर, वाराणसी, संतकबीर नगर, गोंडा, हमीरपुर, बहराइच, लखीमपुर, जालौन, बांदा, फैजाबाद, कुशीनगर, बाराबंकी, सीतापुर, पीलीभीत और लखीमपुर शामिल हैं.

कुल मिलाकर जहां प्रदेश के दो दर्जन से अधिक जिले बाढ़ से प्रभावित हुए. वहीं बुंदेलखंड में बाढ़ ने किसानों की कमर ही तोड़ दी है. खेतों में लहलहाते ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, लोबिया, अरहर के खेतों में कई दिनों तक पानी भरे रहने से फसलें खराब हो गईं. जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है. उनके ऊपर प्रकृति की दोहरी मार पड़ी है. एक ओर सूखे ने उन्हें एक-एक दाने के लिए मोहताज कर दिया था. वहीं इस बार भीषण बाढ़ ने बुंदेलखंड के किसानों के सामने भुखमरी जैसी स्थिति पैदा कर दी है. बहरहाल, सूखा झेल चुके किसानों के चेहरे अच्छी बारिश होने से खिल उठे थे, लेकिन बाढ़ ने उनकी खुशियां ही छीन लीं हैं. देखना यह है कि राजनीतिक अखाड़ा बनने वाले बुंदेलखंड के किसानों को उबारने के लिए सरकार क्या योजना बनाती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है

सैयद शावेज़ फ़िरोज़

चुनाव तय समय पर हो या उसके पहले, समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार है. नहरों के टेल तक पानी पहुंचने की बात हो या नहरों की खुदाई की या फिर बिजली की ही समस्या हो, सपा सरकार धीरे-धीरे अपने सभी वायदों को पूरा कर रही है. पार्टी की यही नीति इसे लोकसभा चुनाव में कामयाब बनाएगी. उक्त बातें चंदौली सांसद एवं समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रामकिशुन यादव ने पिछले दिनों पार्टी के लोकसभा केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के पश्चात कहीं. सांसद ने कहा कि इस कार्यालय से सरकार की उपलब्धियां जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही चुनावी रणनीत बनाने के सभी कार्य किए जाएंगे. यही नहीं, यह कार्यालय वाराणसी व आसपास के जनपदों के वोट बैंक को भी मज़बूत करेगा. चंदौली के आगामी विकास प्रोजेक्ट पर रोशनी डालते हुए उन्होंने अपना राजनीतिक एजेंडा लाल बहादुर शास्त्री आधुनिक स्टेडियम, जिला मुख्यालय के लिए ज़मीन, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना, फल एवं सब्जी मंडी के लिए जमीन एवं पत्रकार भवन के निर्माण को बताया. कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनपद के लिए दस करोड़ की घोषणा की थी. इससे ज़ाहिर है कि चंदौली सरकार की नज़र में है और इसके लिए बतौर सांसद मैं ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी कृत संकल्पित है. क्योंकि यहां से हमारे नेताजी (मुलायम सिंह यादव) का भी गहरा रिश्ता है. इस दौरान मौजूद राज्य मंत्री व्यवसायिक शिक्षा डा. बहादुर सिंह यादव ने कहा कि सपा विकास का काम करती है, जबकि अन्य पार्टियां वोट की राजनीत करती हैं. बसपा जहां जातिगत राजनीति करती है तो वहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों ही वोट की राजनीति में विश्वास करने वाली पार्टियां हैं. भाजपा ने देश को बांटने काम किया है और अब कांग्रेस भी इसी रास्ते पर चल निकली है. एक बार जहां उत्तर प्रदेश को बांट कर उत्तराखंड का निर्माण किया तो वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना बना कर देश की अखंडता को प्रभावित किया है. यही वजह है कि आज दर्जनभर से ज़्यादा राज्यों में आंदोलन छिड़े हुए हैं. वाराणसी की ही बात करें तो यहां बसपा ने जब चंदौली को जिला बनाया तो इसमें कई किसानों की ज़मीन अधिग्रहीत हो गई. आज भी किसान न्याय पाने के लिए जूझ रहे हैं. लेकिन इनकी आवाज़ को बार-बार दबाया जा रहा है. पिछड़ों की दबी आवाज़ को समाजवादी पार्टी और इनके कार्यकर्ता आगे बढ़ कर उठा रहे हैं. इसलिए मिशन-2014 समाजवादी पार्टी अपने दम पर लड़ने को तैयार है. इस दौरान सपा के जिलाध्यक्ष चंदौली बलिराम यादव, सैयदराजा विधायक मनोज सिंह डब्लू, वाराणसी जिलाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा, पूर्व विधायक सैदपुर राजनाथ, मनोज सिंह काका, संजय मिश्रा, नरेंद्र नथुनी, सुरेंद, पूर्व ब्लाक प्रमुख बाबूलाल यादव सहित अन्य लोग शामिल रहे. ■

feedback@chauthiduniya.com

बांध परियोजनाओं से तबाह उत्तराखंड की धरती

उत्तराखंड में नदियों पर बनीं परियोजनाओं के कारण जब-तब विनाशकारी घटनाएं घटती रही हैं, लेकिन उन पर गौर नहीं किया गया. कई परियोजनाओं को बिना अनुमति के और बिना उनके परिणामों पर गौर किए बना दिया गया. हाल में आई तबाही के लिए कहीं न कहीं ये बांध ही जिम्मेदार हैं. इन पर नकेल कसे बिना जनता और प्रदेश के बेशकीमती पर्यावरण की सुरक्षा संभव नहीं है.

जबर सिंह वर्मा

उत्तराखंड में मानसून के आरंभ में ही जो नुकसान हुआ है, उसमें बांधों की बड़ी भूमिका है. राज्य सरकार ने लगातार बांधों में हो रहे पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी की है, जिसका परिणाम है कि इस आपदा में बांधों के कारण नुकसान की मात्रा काफी बढ़ गई. राज्य सरकार भविष्य में यह गलती न दोहराए और बांध कंपनियों को उनके किए की सजा मिले, तभी उत्तराखंड का पर्यावरण और लोग सुरक्षित रह पाएंगे. हाल की बाढ़ में ये बांध कभी भी फट जाने वाले बम साबित हुए हैं, जो कभी भी तबाही ला सकते हैं.

16-17 जून की रात बद्रीनाथ जी के नीचे अलकनंदा-गंगा पर बना जेपी कंपनी का बांध, दरवाज़े न खोलने के कारण टूट गया. फिर नदी ने बांध के नीचे के क्षेत्र में भयंकर तबाही मचाई. लामबगड़, विनायक चट्टी, पांडुकेश्वर, गोविंदघाट, पिनोला घाट आदि गांवों में मकानों, खेती, वन और गोविंद घाट के पुल के बहने से जो नुकसान हुआ इसका मुख्य कारण था समय रहते जेपी कंपनी द्वारा विष्णुप्रयाग बांध के दरवाजे न खोलना. विष्णुप्रयाग बांध से कभी ग्रामीणों की आवश्यकता के लिए पानी तक नहीं छोड़ा जाता था. 2012 के मानसून में इस परियोजना के कारण आई तबाही में लामबगड़ गांव के बाजार की दुकानें बह गई थीं. जेपी कंपनी ने मुआवज़ा नहीं दिया. विष्णुप्रयाग बांध की सुरंग में चांई व थैंग गांव 2007 में धंस गए थे. लगभग 30 परिवार आज भी बिना पुर्नवास के भटक रहे हैं.

इसी बांध के ऊपर जीएमआर का अलकनंदा-बद्रीनाथ जल विद्युत परियोजना (300 मेगावाट) प्रस्तावित है, जिसके लिए वनभूमि का राज्य सरकार के वन विभाग ने 19 जुलाई तक हस्तांतरित नहीं की थी, किंतु वन कटान का काम द्रुतगति से चालू हो गया था. वे पेड़ व मलबे अलकनंदा-गंगा में बहे, जिसने नीचे के क्षेत्र में तबाही लाने में बड़ी भूमिका अदा की.

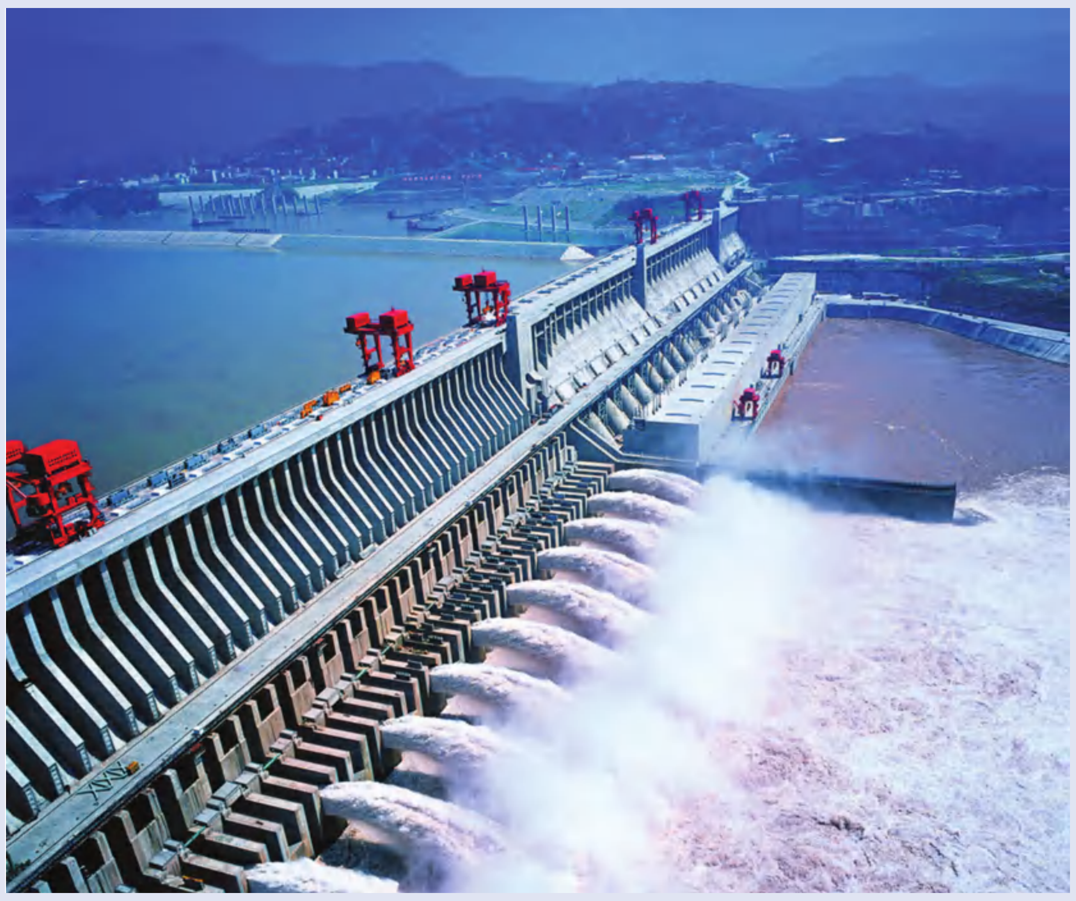

इसी नदी में विष्णुप्रयाग बांध से लगभग 200 किमी नीचे, भागीरथीगंगा और अलकनंदागंगा के संगम देवप्रयाग से 32 किमी ऊपर श्रीनगर में लगभग बन चुकी श्रीनगर परियोजना (330 मेगावाट) के मलबे की वजह से बड़ी तबाही हुई. श्रीनगर परियोजना बिना किसी पर्यावरणीय स्वीकृति के 200 मेगावाट से 330 मेगावाट की कर दी गई और बांध की ऊंचाई 65 से 95 मीटर कर दी गई. 1985 में 65 मीटर बांध के साथ 200 मेगावाट की बांध स्वीकृति मे तमाम खामियां थीं. कई मुकदमे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में इन्ही विषयों को लेकर लंबित हैं. इन मुकदमों में उठाई गई आशंकाएं सच साबित हुईं, जब इस बांध का पांच लाख टन मलबा बांध के ठीक नीचे बिना सुरक्षा दीवार बनाए डाला गया और पानी के साथ बहकर 70 घर तबाह कर गया. 16-17 जून को तबाही के दौरान ऊपर से आ रहे पानी से जलाशय का जलस्तर बढ़ने की परिस्थितियों का फायदा उठाकर श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की निर्माणदायी कंपनी जीवीके के कुछ अधिकारियों द्वारा धारी देवी मंदिर को अपलिफ्ट करने का षडयंत्र रचा गया, जो कि अगस्त 2013 में प्रस्तावित था. इस दौरान बांध के गेट, जो पहले आधे खुले थे, उनको पूरा बंद कर दिया गया, जिससे कि बांध की झील का जलस्तर बढ़ गया. बाद में पानी से बांध पर दबाब बड़ने लगा तो बांध को टूटने से बचाने के लिए जीवीके कंपनी द्वारा आनन-फानन में नदी तट पर रहने वालों को बिना किसी चेतावनी के दिए बांध के गेटों को खोल दिया गया, जिससे जलाशय का पानी प्रबल वेग से नीचे की ओर बहा और इसने विनाशकारी रूप अख्तियार कर लिया. इससे श्रीनगर शहर के कई इलाकों में व्यापक नुकसान हुआ.

अलकनंदागंगा की सहयोगिनी मंदाकिनी में छोटी से लेकर बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं जैसे फाटा-ब्योंग और सिंगोली-भटवाड़ी का भी यही हाल हुआ. बांधों के निर्माण में प्रयुक्त विस्फोटकों, सुरंग और पहाड़ के अंदर बने विद्युतगृह व अन्य निर्माण कार्यों से निकला मलबा हाल की तबाही का बड़ा कारण बना. इन सब कार्यों पर किसी भी तरह की कोई निगरानी का गंभीर प्रयास सरकार की ओर से नही हुआ. एक आकलन के अनुसार, बांध परियोजनाओं से 150 लाख घनमीटर मलबा नदियों में बहा है. इस मलबे ने पानी की विनाशकारी शक्ति को बढ़ाया है.

विष्णुप्रयाग और श्रीनगर इन दोनों ही परियोजनाओं से हुई बर्बादी के बाद बांध कंपनी के व्यवहार में एक समानता थी. जेपी और जीवीके कंपनी के किसी भी कर्मचारी अधिकारी ने आकर लोगों का हाल नहीं पूछा. सरकारी अधिकारियों का भी यही रवैया रहा.

मात्र 10 महीने पहले उत्तराखंड में गंगा की दोनों मुख्य धाराओं भागीरथी की अस्सीगंगा घाटी और अलकनंदा की केदारघाटी में अगस्त और सितंबर 2012 में भयानक तबाही हुई. भगीरथी में 3 अगस्त 2012 को अस्सी गंगा नदी में बादल फटने के कारण निमार्णाधीन कल्दीगाड व अस्सी गंगा जलविद्युत परियोजनाओं ने तबाही मचाई. भागीरथी में मनेरी भाली परियोजना के कारण बहुत नुकसान हुआ. अस्सीगंगा के गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए. जिस तरह की तबाही हुई, उसकी भारपाई में कई दशक लगेंगे.

13 सितंबर, 2012 को ऊखीमठ तहसील मुख्यालय के चार किमी के दायरे में एक साथ छह स्थानों पर बादल फटने की घटना से चारों तरफ तबाही मचा दी. यहां एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी द्वारा पोषित कालीगंगा प्रथम, द्वितीय और मद्महेश्वर जलविद्युत परियोजनाएं बन रही हैं. इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य के कारण ही अनेक गांवों की स्थिति खराब हुई है.

टिहरी बांध झील में अस्सीगंगा के टूटे बांधों का सारा मलबा जमा है. केंद्रीय जल आयोग के नियमों का पालन न करते हुए बांध निर्माणा को सही साबित करने की कोशिश का नतीजा यह है कि आज टिहरी बांध की झील में लगातार बढ़ता पानी देवप्रयाग-हरिद्वार-ऋषिकेश और अन्य मैदानी क्षेत्र में बाढ़ का कारण बना हुआ है.

जो बांध टूटे हैं, उन बांध कपंनियों की चिंता है कि कैसे भी बांधों की मरम्मत का काम शुरू किया जाए. वे भी सरकार से आपदा के तहत करोड़ों रुपयों की मांग कर रही है. जबकि बांध कंपनियों ने सुरक्षा प्रबंधों की पूरी तरह अनदेखी की है. बांधों के खिलाफ लगातार आंदोलन चले हैं. किन्तु हर बार विरोध को जैसे-तैसे दबा दिया जाता रहा. आज हो रही बर्बादी पर विकास का राग अलापने वाले मौन हैं.

नेषनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट के राष्ट्रीय समन्वयक विमल भाई कहते हैं कि तबाही के लिए जिम्मेदार इन दर्जनों परियोजनाओं पर आपराधिक मुकदमें दर्ज होने चाहिए. सरकार यदि ऐसा कदम उठाए तो यह जनता के साथ न्याय होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

केदारनाथ घाटी में अभी भी बिखरे हैं शव

राजकुमार शर्मा

केदारनाथ क्षेत्र की पहाड़ियों में लगातार मिल रहे शव सरकार के सर्च ऑपरेशन के दावों की पोल खोलते हैं. आपदा को करीब तीन महीने होने को हैं लेकिन सरकार को अभी तक न तो यह पता है कि कितने लोग दैवी प्रकोप में मारे गए और न ही यह पता है कि कहां-कहां लोगों के शव बिखरे पड़े हैं. सितंबर के पहले सप्ताह में पुलिस को तलाशी अभियान के तीसरे चरण में चार दिनों में 197 शव मिले. ये शव उन यात्रियों के हैं जो एक बार मौत को मात देकर इन पहाड़ों तक जा पहुंचे थे. समय से मदद न मिलने पर ये बदनसीबों की ठंड और भूख से तड़प-तड़प कर अकाल मौत हो गई. इतने ऊंचे स्थानों पर शव देखकर पुलिस भी हैरत में है. जहां ये शव मिले हैं, वहां सामान्य परिस्थितियों में पहुंचना काफी दुरूह है. शव अभी खुले क्षेत्रों में ही मिले हैं. पुलिस को लगातार इलाके में बिखरे पड़े कंकाल मिल रहे हैं. पुलिस को अभी भी केदारनाथ की पहाड़ियों में और शव मिलने की आशंका है.

केदारनाथ घाटी में 16-17 जून को आई बाढ़ में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों लोग लापता हैं. आपदा के बाद चले राहत बचाव कार्यों में सेना, एनडीआरएफ, आइटीबीपी और पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान में हजारों यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया. हालांकि, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति व खराब मौसम के चलते अभियान चलाने में खासी दिक्कतें आई. अभियान के दौरान स्थानीय निवासियों द्वारा केदारनाथ के आसपास के पर्वत शिखरों में लोगों के जीवित होने की संभावना व्यक्त की गई थी. इस समय इन पर्वत शिखरों की ओर जाने की न तो किसी ने जहमत उठाई और न ही कोई हिम्मत कर पाया. नतीजतन इन पर्वत शिखरों पर किसी तरह बच कर पहुंचे लोग प्रकृति की विभीषिका का मुकाबला नहीं कर पाए और मौत के मुंह में समा गए.

स्थानीय मीडिया ने उस वक्त आशंका व्यक्त भी की थी कि संभवत: केदारनाथ की पहाड़ियों में काफी संख्या में यात्री हो सकते हैं. उस समय सेना और सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. अब पुलिस की ओर से तकरीबन 14 हजार फुट की ऊंचाई में चलाए जा रहे इस अभियान में सामने आए तथ्य यह साबित कर रहे हैं कि लोग इन पर्वतों तक जीवित पहुंचे थे. पुलिस को चार दिनों के अभियान में जो 197 शव मिले हैं, यह अभी तक के अभियान में सबसे अधिक हैं. केदारनाथ में पुलिस की ओर से शवों की खोज का कार्य आपदा के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था. पुलिस की ओर से 31 जुलाई तक 139 शव ढूंढे गए थे, जिनका डीएनए सेंपल एकत्र कर दाह संस्कार किया गया.

दूसरे चरण में पुलिस ने दो अगस्त से केदारनाथ परिसर में स्थित भवनों में फंसे शवों को निकालने व रामबाड़ा क्षेत्र में अभियान चलाया. 26 अगस्त तक चलाए गए अभियान में पुलिस ने 159 शव खोज कर इनका दाह संस्कार किया. स्थानीय लोगों से मिल रही सूचना के आधार पर पुलिस ने तीसरे चरण में 12 हजार से 14 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित पर्वतों पर सर्च अभियान चलाया. इसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं. पुलिस की ओर से गरुड़चट्टी और गौरीकुंड के बीच स्थित भीमबली व गोमकुरा की पहाड़ियों में चार दिनों में यहां अभी तक 197 शवों के कंकाल मिले हैं. इन शवों के पंचायतनामा भरने के साथ ही इनका डीएनए सेंपल भी सुरक्षित रखा जा रहा है.

पुलिस महानिरीक्षक कानून-व्यवस्था राम सिंह मीणा का कहना है कि शायद ये लोग 18 जून तक दम तोड़ चुके थे. 18 जून के बाद आसपास की पहाड़ियों से काफी लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिये बचाया गया था. ये लोग इतना ऊपर चढ़ गए थे कि संभवत: नीचे नहीं उतर पाए और ठंड से अपनी जान गंवा बैठे.

निशंक ने की श्वेत पत्र जारी करने की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केदारघाटी में शवों के मिलने पर राज्य सरकार को आपदा राहत कार्यों में लापरवाही के मामले में आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि शवों की बरामदगी ने राज्य सरकार की असंवेदनशीलता, अमानवीयता और घोर उपेक्षा की कलई खोल दी है. आपदा के बाद भूख-प्यास के कारण और समय पर मानवीय मदद, इलाज न मिलने से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है. सरकारी तंत्र अगर समय रहते कोशिश करता तो उन्हें बचाया जा सकता था. इन मौतों के लिए सीधे सरकार जिम्मेदार और गुनहगार है. आपदा में घायल हुए लोग कई दिनों तक जंगलों में जान बचाने को भटकते रहे और सरकार इनकी सुध लेने की बजाए राजधानी में बैठकर आंकड़ों का खेल खेलती रही. आपदा के लगभग तीन महीने बाद भी प्रभावित लोगों तक खाद्यान्न और अन्य जरूरी चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं. सरकार को वास्तव में मृतकों की सही संख्या का अंदाजा ही नहीं है. निशंक ने एक बार फिर आपदा में मृतकों, प्रभावितों तथा नुकसान को लेकर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की. ■

feedback@chauthiduniya.com

खतरे के साये में आपदा पीड़ित

उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिला इस बार दैवीय आपदा की इस मार से बच गया, जैसी 2010 में आई थी. आपदा पीड़ितों को तत्काल दीर्घगामी सहायता देने का दावा करने वाला प्रशासन 2010 के प्रभावितों को एक प्रकार से भूल ही गया है. लमगड़ा विकास खंड के मालता, छतोला जैसे क्षेत्रों में दर्जनों परिवार आज तक 2010 की आपदा के बाद से बेघर हैं. ग्रामीणों के अनुसार, तत्काल राहत के तौर पर उन्हें 10 से 20 हजार रुपये तक मिले और स्कूलों व पंचायत घरों में शरण दी गई. कोई स्थायी ठिकाना न होने के कारण ग्रामीणों को मजबूरन वापस पुराने जर्जर घरों में लौटने को विवश होना पड़ा है. यहां वे खतरे के साये में जीने को विवश हैं.

भैंसियाछाना विकासखंड के खैरखेत के ग्रामीणों का यही हाल है. पहाड़ी के नीचे बसे इस तोक में लगभग नौ परिवार पूरी तरह से खतरे की जद में आ गए थे. पूरी पहाड़ी अचानक दरकने लगी और धूल मिट्टी व पत्थरों ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया. गांव वालों के हो-हल्ले के कारण प्रशासन ने दबाव में 9 परिवारों के लगभग चार दर्जन लोगों को स्थानी जूनियर हाईस्कूल और पंचायत घर में रुकवा तो किया, लेकिन बीते कई माह से वहां रहने लायक नहीं रह गया है. इसके बावजूद छोटी खेती, दो चार मवेशी और सीमित आर्थिक आय के साधनों से वंचित ये लोग शरणार्थियों की भांति रहने को विवश हैं. लमगड़ा विकासखंड के प्रभावित गांवों में खुद विधानसभा अध्यक्ष दौरा कर चुके हैं. जबकि भैंसियाछाना के खैरखेत में विधायक अजय टम्टा, संसदीय सचिव मनोज तिवारी व जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता जाकर हाल देख चुके हैं. बावजूद इसके इन ग्रामीणों का अभी स्थाई विस्थापन नहीं हो पाया है. भैंसियाछाना खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र बिष्ट के अनुसार अभी लगभग नौ परिवार अन्यत्र विस्थापित हैं और इनके लिए भूमि चयन का काम उपजिलाधिकारी को सौंपा गया है. प्रशासन की ओर से राहत सामग्री दी जा रही है. मंत्री, नेता अधिकारियों के संयुक्त प्रयासों के बाद भी विस्थापन

के कार्य में यह ढिलाई सचमुच आपदा पीड़ितों को अखर रही है. मृत लोगों को भले ही सरकार की ओर से लगभग समय पर मुआवजा मिल गया हो, लेकिन अन्य पुनर्वास के कामों में देरी से प्रभावित परिवारों की वेदना बढ़ती जा रही है. लमगड़ा विकासखंड के मालता और छतोला क्षेत्रों में दर्जनों परिवार 2010 से रह रहे थे. अब वे बेघर हैं और संकट के दौर से गुजर रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

आपदा में हेलीकॉप्टरों पर खर्च हुए 673 करोड़

उत्तराखंड में आई दैवी आपदा में व्यापक पैमाने पर चले बचाव एवं राहत कार्य के दौरान सिर्फ हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल पर 673 करोड़ की धनराशि खर्च हुई. वायुसेना के अलावा निजी हेलीकॉप्टर कंपनियों पर हुआ खर्च भी इसमें शामिल है. नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से राज्य को मिलने वाले 1187 करोड़ रुपये में यह धनराशि भी शामिल की गई है. गत जून की दैवीय आपदा के बाद सेना, एनडीआरएफ, आइटीबीपी और राज्य सरकार द्वारा चलाया गया बचाव एवं राहत अभियान अपने आप में इस तरह के इतिहास के कुछ बड़े बचाव अभियानों में शुमार किया जा रहा है. इस अभियान में कई हजार लोगों को बचया गया था.

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क पूरी तरह ध्वस्त हो जाने से बचाव एवं राहत अभियान के संचालन के लिए पूरी निर्भरता हवाई मार्ग पर ही बन गई. भारतीय वायु सेना के साथ ही निजी हेलीकॉप्टर कंपनियों को इस कार्य में लगाया गया. अभी भी सेना के कुछ हेलीकॉप्टर राज्य के अलग-अलग आपदाग्रस्त इलाकों में राहत कार्य के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

पिछले सप्ताह नई दिल्ली में हुई सेंट्रल इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप (आइएमजी) की बैठक में उत्तराखंड को आपदा के बाद पुनर्निर्माण आदि कार्यों के लिए 6687 करोड़ रुपये की धनराशि देने पर सहमति बनी. अभी इस धनराशि को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट कमेटी में मंजूरी मिलनी शेष है. राज्य को एनडीआरएफ मद में 1187 करोड़ की मंजूरी दी गई. इसमें से 673 करोड़ रुपये की धनराशि आपदा के बाद बचाव अभियान में शामिल हेलीकाप्टरों के खर्च के रूप में है. इसके अलावा 82 करोड़ रुपये एक्सग्रेशिया (राहत), 25 करोड़ रुपये खोज एवं बचाव कार्य के लिए राज्य सरकार को मंजूर किए गए हैं.

राज्य सरकार को केंद्र से लगभग 250 करोड़ रुपये की धनराशि आपदा राहत कार्यों के लिए पहले ही प्राप्त हो चुकी है. राज्य की ओर से केंद्र को तकरीबन 14 हजार करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था. इसमें आठ हजार करोड़ की मांग आपदा से तबाह और आपदा के प्रति संवेदनशील तकरीबन 300 से ज्यादा गांवों के पुनर्वास के लिए की गई है. उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए विश्व के तमाम क्षेत्रों से लगातार उदार सहयोग मिल रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHI/2009/30467

मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए राज्यमंत्री और कुलपति की निगाह भले ही दर्शननगर स्थित 300 बिस्तरों वाले चिकित्सालय पर गड़ी है, लेकिन उनकी मंशा कैसे संभव होगी, यह अभी भी भविष्य के गर्भ में है. 2008 से निर्माणाधीन चिकित्सालय अभी हैंडओवर लायक भी नहीं हुआ है.

छोटे दलों के बड़े मंसूबे

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश की फिजा से माफियागिरी, दबंगई, साम्प्रदायिकता और जातिवाद का जहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. नेताओं को ही नहीं, जनता को भी यह गंदा खेल खूब रास आ रहा है. इस खेल में अदालती आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है. कुछ समय पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में जातीय आयोजनों और रैलियों पर रोक लगा दी थी, लेकिन जातिवाद की राजनीति करने वाले नेता इसकी काट निकालने से बाज नहीं आ रहे. सूबे में काफी चालाकी के साथ चुनावी लिहाज से जातियों की गोलबंदी का खेल खेला जा रहा है. इसके लिए दबंगों को भी अपनी-अपनी बिरादरियों के बीच प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. पहले जो जातीय सम्मेलन विभिन्न राजनीतिक दलों के बैनर तले खुले आम हुआ करते थे, अब उनकी जगह पर विभिन्न जातियों के बैनर तले यह आयोजन होने लगे हैं. नेतागण भी ऐसे सम्मेलनों में हिस्सा ले रहे हैं. कोई इससे अछूता नहीं है.

क्षेत्रीय दल कहलाने वाली समाजवादी पार्टी, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल तो जातपात की राजनीति करते ही हैं, राष्ट्रीय दल कहलाने वाली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी जातीयता के खेल से अछूते नहीं हैं. लोकसभा चुनाव 2014 के लिए उत्तर प्रदेश में भाजपा बूथ लेवल पर अपने संगठन को जातीय समीकरण के हिसाब से ही खड़ा कर रही है. कांग्रेस भी जातीय गोटियां बिछाने में लगी है. सपा-बसपा और रालोद की देखा-देखी कई जातियों के सूरमा भी अपनी अलग पार्टी बना कर चुनावी मैदान में ताल ठोंकने लगे हैं. पिछले करीब डेढ़ दशक में अधिकांश इन जातियों के रहनुमाओं ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली है, जिसका अच्छा वोट प्रतिशत है. यह अपनी जातियों तक ही सीमित है. छोटे-छोटे दल बनाकर जातीय नेता बहुत बड़ा करिश्मा नहीं करना चाहते हैं. वह 7-8 सीटें जीत कर या फिर बड़े-बड़े दलों से सौदेबाजी या ब्लैकमेलिंग करके अपने हित साधने में भी पीछे नहीं रहते हैं. यह चौंकाने वाला तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में सौ से अधिक गैर मान्यता प्राप्त दल पंजीकृत हैं. कहने को तो ये दल दूसरी जातियों के भी उम्मीदवारों को मौका देते हैं, लेकिन इन दलों पर ठप्पा अपनी अपनी जाति का ही लगा रहता है. कई दलों के आकाओं ने तो काले धन को सफेद करने का ही गोरखधंधा चला रखा है. यह दल राजनीतिक दलों को मिलने वाली तमाम रियायतों का पूरा फायदा उठाते हैं.

मुख्तार अंसारी

अनुप्रिया पटेल

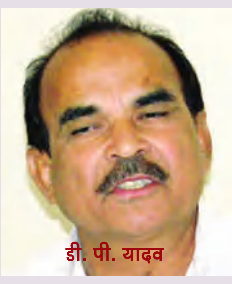

डी. पी. यादव

ब्रिजेश सिंह

अतीक अहमद

बाबू सिंह

बहरहाल, बात जातीय और क्षेत्रीय आधार पर बने राजनीतिक दलों की करें तो कुर्मी बिरादरी को अपना दल अपनी बपौती समझता है. उसके आका सोने लाल पटेल थे. उनकी मौत के बाद पार्टी की कमान उनकी पत्नी और बेटी सुप्रिया पटेल के हाथ में आ गई है. राजभर समाज की भारतीय समाज पार्टी (भासपा), चौहान और नोनिया की जनवादी पार्टी, पाल गड़रिया की राष्ट्रीय कामगार पार्टी, भरभूज और गोंड़ की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, निषाद और मल्लाह की वंचित जमात पार्टी, सोनकर और खटिक की इंडियन जस्टिस पार्टी, बिंद जाति की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और पिछड़े मुसलमानों की पीस पार्टी जैसे अनेक दल समय-बेसमय राजनीतिक राग अलापते रहते हैं. इन दलों के प्रमुख नेताओं ने अपने जातीय बहुल इलाकों की कुछ लोकसभा के प्रत्याशी भी घोषित कर रखे हैं. क्षेत्रीय आधार पर बुंदेलखंड कांग्रेस पार्टी, लोकमंच जैसे तमाम दल ताल ठोंक रहे हैं. कहने को तो यह दल अपनी-अपनी बिरादरियों के इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं. बड़े दलों से दूरी बनाकर चलते हैं, लेकिन चुनावी मौसम में अपनी ताकत दिखाने के लिए छोटे-छोटे दलों का महाकुनबा भी बना लेते हैं. 2012 के विधान सभा चुनाव में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह ने पूरे सूबे में क्षेत्रिय सम्मेलन आयोजित कर गठबंधन की भूमिका रची और अंततः पीस पार्टी और अपना दल के गठबंधन के सूत्रधार बने. कुंवर ने इस गठबंधन से कई क्षत्रियों को टिकट दिलाने में सफलता हासिल की, लेकिन चुनाव से पूर्व ही यह कुनबा बिखर भी गया. 2014 के चुनाव की आहट ने इन दलों के आकाओं के कान एक बार फिर खड़े कर दिए हैं. कहा जा रहा है कि अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव के लिए क्षत्रिय महासभा की बातचीत एकता मंच से चल रही हैं. अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी भी नए समीकरण की तलाश में हैं.

जातीय आधार पर बने इन दलों के नेताओं को इस बात की चिंता नहीं है कि अदालत ने जातीय आधार पर होने वाली रैलियों आदि पर रोक लगा रखी है. वह अदालत के अवहेलना की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन इस सच्चाई से भी इन्कार नहीं करते हैं कि प्रदेष का राजनीतिक और सामाजिक तानाबाना जातीय आधार पर ही बुना गया है. इन दलों के आकाओं में जीत की भूख इतनी तीव्र है होती है, अच्छे-बुरे का अंतर भी यह लोग भूल जाते हैं. कई अपराधिक व्यक्तियों और माफियाओं को यह दल सिर्फ इसलिए टिकट थमा देते हैं, क्योंकि वे इनकी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं. जिन माफियाओं को कोई दल टिकट नहीं देता है, उन्हें भी यह दल टिकट देते हैं. इन्हीं दलों के आकाओं की मेहरबानी से विधानसभा चुनाव में माफिया मुख्तार अंसारी, बृजेश सिंह, मुन्ना बजरंगी, अतीक अहमद, डीपी यादव जैसे बाहुबली ताल ठोंकते हैं. अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए भी तमाम माफिया बड़े दलों से टिकट के लिए प्रयासरत हैं, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो छोटे दल इनके पालनहार बनेंगे. 2014 के आम चुनाव के लिए अफजाल और मुख्तार अंसारी बंधुओं ने अपनी पार्टी कौमी एकता दल का भारतीय समाज पार्टी और पूर्वांचल के कुछ दलों को मिलाकर एकता मंच कर गठन कर लिया है. मुख्तार वाराणसी से और उनके भाई अफजाल अंसारी बलिया से सांसद बनना चाहते हैं. एकता मंच का सहारा बसपा से निकाले गए बाबू सिंह कुशवाहा को भी मिल सकता है. वह गाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं. इसी प्रकार प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के टिकट से 2012 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाला माफिया बृजेश सिंह भी चंदौली से अपनी किस्मत आजमाने के चक्कर में हैं. बाहुबली अतीक अहमद को अपना दल एक बार फिर प्रत्याशी बना सकता है. पिछला लोकसभा चुनाव अतीक प्रतापगढ़ से हार गए थे. अबकी वह दूसरा ठिकाना तलाश रहे हैं. पश्चिमी यूपी में बाहुबली डीपी यादव की कभी भाजपा से सेटिंग की बात होती है तो कभी अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय परिवर्तन दल के सहारे चुनावी बैतरणी पार करने की बात कही जाती है.

राजनीति के मैदान में जातिवाद और माफियाओं की बढ़ती सक्रियता पर अपना दल की महासचिव और विधायक अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि जातिवाद की राजनीति और बाहुबलियों का राजनीति में दखल कड़वी सच्चाई है. इसकी शुरुआत कहां से हुई, सब जानते हैं. कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा कोई दल इससे अछूता नहीं है. भासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के भी कुछ इसी तरह के विचार हैं. वह कहते हैं कि यह तो बराबरी की हिस्सेदारी है. बात बड़े दलों की की जाए तो यह छोटे-छोटे दल उनके लिए वोट कटवा साबित होते हैं. इसीलिए इन दलों से बड़े-बड़े दलों के नेता भी कांपते हैं. इसके चलते अक्सर थोड़ा-बहुत ले-देकर बड़े दल इन्हें अपने साथ खड़ा करने में भी गुरेज नहीं करते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

अवध विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज प्रस्ताव

अधर में चिकित्सालय

राकेश कुमार यादव

फैजाबाद में लंबे अर्से से निमार्णाधीन 300 बिस्तरों वाला चिकित्सालय अब मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव के चलते अधर में लटक गया है. डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा अपने मेडिकल कॉलेज निर्माण प्रस्ताव में दर्शननगर के निर्माणाधीन 300 शैया चिकित्सालय को 500 शैया में तब्दील करने का सुझाव दिया है. दूसरी ओर अभी भी यह तय नहीं हो पा रहा है कि कार्यदायी संस्था 300 शैया चिकित्सालय निर्माण में कितना वक्त लगाएगी, जबकि कार्यदायी संस्था उप्र राजकीय निर्माण निगम को सख्त निर्देश दिया गया है कि सितंबर माह के अंत तक चिकित्सालय को क्रियाशील कराने के लिए मुख्य भवन, वार्ड ब्लॉक का भू-तल हस्तगत करा दिया जाए और शेष कार्य 31 मार्च, 2014 तक पूरा कराकर हस्तगत कर दिया जाए, लेकिन निर्माण की गति इतनी सुस्त है कि निर्धारित समय में पूरा करा पाना दूर की कौड़ी लग रहा है. कार्यदायी संस्था निर्माण के लिए लगभग ढाई करोड़ रुपये की और मांग कर रही है. स्वास्थ्य विभाग यह मांग मानने को तब तक तैयार नहीं है जब तक परियोजना पूरी नहीं हो जाती.

मेडिकल कॉलेज को लेकर जो योजना डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. वीके गुप्ता ने 9 मई 2013 को पदभार ग्रहण करते हुए बनानी शुरू की थी, उसपर भी पानी फिरता नजर आ रहा है. पदभार ग्रहण करने के साथ-साथ कुलपति प्रो. गुप्ता वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के मकड़जाल ऐसे जकड़ते चले गए कि जांच में आरोप सही पाने के बाद उन्हें मात्र 4 महीने के कार्यकाल में ही 9 सितंबर 2013 को कुलाधिपति को त्यागपत्र सौंपा पड़ा. नये कुलपति प्रो. प्रवीण चंद्र त्रिवेदी ने पदभार संभाल लिया है.

डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने अर्से से प्रतीक्षारत ऐलोपैथिक मेडिकल कॉलेज को फैजाबाद में स्थापित करने की मुहिम पुन: तेज कर दी है. पूर्व कुलपति प्रो. वीके गुप्ता ने क्षेत्रीय विधायक व मनोरंजन कर राज्यमंत्री तेजनारायण पांडेय पवन के साथ मिलकर परियोजना का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा था. प्रस्ताव के अनुसार, दर्शननगर में निर्माणाधीन 300 शैया चिकित्सालय को उच्चीकृत कर 500 शैया में तब्दील किया जाएगा और इसे विश्वविद्यालय को हस्तगत कराया जाएगा. अस्पताल मिल जाने से विश्वविद्यालय को लेक्चर थियेटर, लैब, ऑफिस ब्लॉक का ही निर्माण कराना होगा, जिसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के पार्श्व की भूमि का चयन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर लिया है. मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर लगभग 365 करोड़ रुपये व्यय आएगा, जिसका प्रस्ताव 29 जुलाई, 2013 को भेजा जा चुका है. कुलपति का कहना है कि मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध हैं और सरकार ने 210 करोड़ रुपये देने की सहमति दे दी है. कुलपति वीके गुप्ता का दावा था कि सरकार का रुख यदि इसी तरह सकारात्मक रहा तो मेडिकल कॉलेज का निर्माण सितंबर माह के अंत तक आरंभ करा दिया जाएगा. इस संदर्भ में मनोरंजन कर राज्य मंत्री व क्षेत्रीय विधायक तेजनारायण पांडेय पवन का कहना है कि विश्वविद्यालय व स्वास्थ्य विभाग के पास मेडिकल कॉलेज के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है. पिछली सरकार की उदासीनता के कारणा मेडिकल कॉलेज वजूद में नहीं आ सका था. लेकिन यह परियोजना पूरी होगी, यह अभी भी भविष्य के गर्भ में है. 2008 से निर्माणाधीन चिकित्सालय अभी हैंडओवर लायक भी नहीं हुआ है. दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज के लिए 500 शैया चिकित्सालय का होना अनिवार्य शर्त है. कुलपति और मंत्री 500 शैया पृथक चिकित्सालय की व्यवस्था को दरकिनार किए हुए हैं. असलियत यह है कि एरोड्रम के समीप स्थित विश्वविद्यालय की जिस 14 हेक्टेयर भूमि पर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की जा रही है, वह मेडिकल कॉलेज के लिए अपर्याप्त और अनुपयुक्त है. इस भूमि के ठीक बगल में राजकीय हवाई अड्डा विस्तार की कवायद भी तेजी पकड़ रही है, जबकि एरोड्रम को लाइंग क्लब के लिए एक कंपनी को बसपा शासनकाल में ही दिया जा चुका है.

पूर्व की बसपा सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के ध्येय से फैजाबाद के दर्शननगर क्षेत्र में 300 शैया के मंडलीय चिकित्सालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई. तत्कालीन समय में इस चिकित्सालय के निर्माण कार्य की लागत 33.68 करोड़ रुपये थी. चिकित्सालय में न्यूरो सर्जरी विभाग व एमआरआइ स्कैन आदि की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई थी. चिकित्सालय के निर्माण की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को सौंपी गई, जिसने जून 2008 में निर्माण कार्य प्रारंभ किया. शुरुआती दौर में इसके निर्माण की संभावित तिथि अक्टूबर, 2010 थी, लेकिन समय से कार्यदायी संस्था को धन अवमुक्त न होने की वजह से निर्माण कार्य धीमी गति से हुआ. हालांकि विधानसभा चुनाव पूर्व ही बसपा सरकार ने इसे चालू कराने का दावा किया, जो विधानसभा चुनाव तक कायम रहा और पूरा नहीं हो सका. बसपा सरकार की सत्ता जाने के बाद सपा सरकार के वर्तमान अयोध्या विधायक तेजनाराण पाण्डेय ने भी चुनाव के समय व चुनाव जीतने के बाद शीघ्र चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की बात कहीं थी, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

भ्रष्टाचारियों से पस्त कुलपतियों का इस्तीफा

भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे फैजाबाद के दो विश्वविद्यालय डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और नरेंद्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कुलपति टिक नहीं पा रहे हैं. दोनों विवि के भ्रष्टाचारी ऐन-केन प्रकारेण मनमाफिक न चलने वाले कुलपतियों को इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहे हैं. 30 दिन के भीतर दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इस्तीफा दे दिया है जिसको लेकर शिक्षा जगत में हलचल है. डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. वीके गुप्ता जो पदभार संभालने के बाद विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचारमुक्त और पारदर्शी प्रशासन के लिए अहम निर्णय ले रहे थे, भ्रष्टाचारियों को रास नही आया. दो सांसद सहित आधा दर्जन विधायकों ने प्रो. गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. मोर्चे का ही नतीजा रहा कि शासन ने मंडलायुक्त के नेतृत्व में जांच समिति गठित कर आरोपों की जांच करवानी शुरू कर दी, कहा जाता है कि कुलपति प्रो. वीके गुप्ता के ऊपर लगाये गए आरोप सही पाए गए. नतीजतन मात्र चार माह के कार्यकाल के बाद ही राज्यपाल/कुलाधिपति ने प्रो. गुप्ता को लखनऊ तलब कर उनसे इस्तीफा ले लिया. इसी तरह 20 अगस्त 2013 को नरेंद्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज के कुलपति डॉ. आरएस कुरील ने भी त्यागपत्र दे दिया था. कुरील पर नियुक्तियों मे धनउगाही का आरोप लगाया गया और जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर शासन ने जांच भी शुरू करा दी थी. जांच का नतीजा सामने आता, इसके पहले ही डॉ. कुरील ने इस्तीफा दे दिया. भ्रष्टाचार के आरोप दोनों विश्वविद्यालयों के अन्य कुलपतियों पर भी लगते रहे हैं. पहले भी कम ही कुलपति ऐसे हुए हैं जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए हैं. पूर्व कुलपति प्रो. रमेशचंद्र सारस्वत ने कार्यकाल पूरा होने के डेढ़ वर्ष पहले ही इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डा. एसएम इलियास और डा. बसंत राय भी भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे चुके हैं.

क्या कहते हैं अधिकारी

दर्शननगर स्थित 300 शैया चिकित्सालय में विद्युत कनेक्शन के लिए 2 करोड़ 84 लाख रुपये कार्यदायी संस्था ने विद्युत विभाग में जमा करा दिया है. अधिशासी अभियंता विद्युत को 30 अगस्त तक विद्युत कनेक्शन देने का निर्देश दिया गया, परंतु अभी तक विद्युत विभाग ने कनेक्शन नहीं दिया है.

-विपिन कुमार द्विवेदी, जिलाधिकारी फैजाबाद

दर्शननगर चिकित्सालय के लिए कई करोड़ रुपये के उपकरण व फर्नीचर सालों पूर्व आ चुके हैं. भवन निर्माण पूरा न होने के कारण उपकरणों का इस्तेमाल संभव नहीं है. बिना पूरा निर्माण हुए चिकित्सालय चलाना संभव नहीं है.

-राकेश कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तराखण्ड के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन, प्रसार प्रतिनिधियों एवं एजेंसियों के लिए शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
arifali@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120-6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627366